

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



फरवरी 2018

खंड 72 अंक 2

संपादन समिति
जनक राज
गौतम चैटर्जी
राजीव रंजन

संपादक
सुनील कुमार

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादन समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडळ उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेख में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषयवस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 1

भाषण

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना और प्रबंध करना
विरल वी. आचार्य 7

भारत के आर्थिक सुधार: अपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में चिंतन
विजय जोशी 19

लेख

जीडीपी आंकड़ों में सांख्यिकीय विसंगतियां: भारत से प्रमाण 31

वर्तमान सांख्यिकी 49

हाल के प्रकाशन 92

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18

छठा द्वािमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि -

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

2. दिसंबर 2017 में एमपीसी की अंतिम बैठक के समय से, सभी क्षेत्रों में वृद्धि की भावनाओं के अधिक समन्वित होने के साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने और गति प्राप्त की है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में यूरो क्षेत्र में मजबूत गति पर विस्तार हुआ है जिसमें उपभोग और निवेश ने सहायता दी। कम होती बेरोजगारी और कम ब्याज दरों के साथ आर्थिक आशावाद सुधार में सहयोग कर रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017 की चौथी तिमाही में वृद्धि के मंदा होने के साथ कुछ गति खो दी, हालांकि विनिर्माण गतिविधि ने दिसंबर में बहुत महीनों के उच्च स्तर को छुआ। जापानी अर्थव्यवस्था का बढ़ना जारी है क्योंकि विनिर्माण गतिविधि ने मजबूत बाह्य

मांग के कारण जनवरी में गति पकड़ी है जो पहले के मजबूत कारोबारी विश्वास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

3. वर्ष 2017 के अंतिम तिमाही में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि में तेजी आई। चीनी अर्थव्यवस्था अधिकारिक लक्ष्य से अधिक बढ़ी जिसका कारण मजबूत घरेलू उपभोग और सुदृढ़ निर्यात रहा। तथापि, वृद्धि के लिए कुछ डाउनसाइड जोखिम बने हुए हैं, विशेषरूप से ऐसा सहज होती स्थायी परिसंपत्ति निवेश और बढ़ते ऋण स्तरों से हो रहा है। रूस में, मजबूत निजी उपभोग, तेल की बढ़ती कीमतें और उच्च निर्यात से आर्थिक गतिविधि में सहायता मिल रही है, हालांकि कमजोर निवेश और आर्थिक मंजूरियां इसकी वृद्धि संभावनाओं पर प्रभाव डाल रही हैं। ब्राजील में, परिवार खर्च और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े चौथी तिमाही में सकारात्मक रहे। तथापि, राजनीतिक अनिश्चितता के चलते सुधार कमजोर बना हुआ है जिसने उपभोक्ता विश्वास को कम कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका घरेलू और बाह्य दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है जिसमें उच्च बेरोजगारी और कम होती फैक्टरी गतिविधि शामिल है।

4. वैश्विक व्यापार में विस्तार जारी है जिसे मजबूत निवेश और सुदृढ़ विनिर्माण गतिविधि द्वारा सहायता प्रदान की गई है। कच्चे तेल की कीमतों ने तीन वर्ष के उच्च स्तर को छू लिया क्योंकि कम होती इन्वेंटरी के साथ ओपेक द्वारा उत्पादन कटौती ने वैश्विक मांग-आपूर्ति संतुलन पर प्रभाव डाला। बुलियन कीमतों ने कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण कई-महीनों के उच्च स्तर को छू लिया। यूके को छोड़कर अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मंद मजदूरी दबावों के कारण मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। मुद्रास्फीति देश-विशिष्ट कारकों के कारण मुख्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न रही।

5. जनवरी पे-रोल आंकड़ों की दृष्टि से यूएस फेडरल की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति पर अनिश्चितता के कारण हाल के दिनों में वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए हैं, इन आंकड़ों में तेजी से बढ़ती मजदूरी वृद्धि और संभावना से बेहतर रोजगार दिखाया गया है। ब्रेग्जिट के समय से अस्थिरता सूचकांक (VIX) अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों ने तेज सुधार दर्शाया है। अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल काफी सख्त हो गया है जो जनवरी में देखे गए ऊपरी दबावों

* 07 फरवरी 2018 को जारी।

को बढ़ा रहा है, जिससे अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफलों में सहगामी वृद्धि हुई। विदेशी बाजार भी अस्थिर हो गए हैं। हाल की अस्थिरता की इस घटना तक वैश्विक वित्तीय बाजारों में निवेशक द्वारा जोखिम उठाने की क्षमता, यूएस द्वारा कॉर्पोरेट कर में कटौती और स्थिर आर्थिक स्थिति के चलते काफी उछाल था। इक्विटी बाजारों में जनवरी में काफी उछाल आया जिसका कारण सुदृढ़ चीनी वृद्धि, पण्य-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और सामान्य रूप से सकारात्मक कॉर्पोरेट भावना थी। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर ने 1 फरवरी को कई-महीनों के निम्न स्तर को छुआ जिसका कारण राजकोषीय जोखिम और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की संभावनाओं में सुधार होना था।

6. घरेलू मोर्चे पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों (एफएई) के अनुसार वास्तविक संवृद्धित सकल मूल्य (जीवीए) वृद्धि का वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत तक होने का अनुमान है, इसका मुख्य कारण कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, खनन और उत्खनन, विनिर्माण तथा लोक प्रशासन तथा रक्षा (पीएडीओ) सेवाओं में कमी होना था।

7. तथापि, सीएओ द्वारा एफएई जारी करने के बाद उपलब्ध सूचना सामान्यतः सकारात्मक रही है। विनिर्माण आउटपुट ने नवंबर में औद्योगिकी उत्पादन (आईआईपी) सूचकांक की वृद्धि को बढ़ावा दिया। लंबी कमजोरी की अवधि के बाद सीमेंट उत्पादन ने नवंबर-दिसंबर में मजबूत वृद्धि दर्ज की जिसने इस्पात उत्पादन में निरंतर अच्छी वृद्धि के साथ नवंबर में इन्फ्रास्ट्रक्चर माल उत्पादन में अभिवृद्धि को बढ़ाया। नए आदेशों से जनवरी में विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में लगातार छठे महीने विस्तार हुआ। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में समग्र कारोबारी भावना के आकलन में तीसरी तिमाही में सुधार हुआ जैसाकि रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) में प्रतिलक्षित हुआ। तथापि, कोयला, कच्चे तेल, इस्पात और विद्युत के उत्पादन में संकुचन/कमी के कारण

दिसंबर में कोर क्षेत्र वृद्धि में कमी आई। गेहूं, तिलहन और मोटे अनाज के मामले में रकबा पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। परिणामस्वरूप, रबी फसल के लिए बुआई क्षेत्र में कमी बढ़कर 2 फरवरी को (-)1.5 प्रतिशत हो गई जो 29 दिसंबर 2017 को (-)1.0 प्रतिशत थी।

8. सेवा क्षेत्र में, कुछ उच्च बारंबारता सूचकों में सुधार हुआ। वाणिज्यिक वाहन बिक्री ने दिसंबर में आठ वर्ष के उच्च स्तर को छुआ। समुद्र, रेल और वायु द्वारा लेकर जाया जाने वाले माल ने भी नवंबर में उच्चतर वृद्धि दर्ज की, किंतु दिसंबर में मिश्रित कार्यनिष्पादन दर्शाया। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री ट्रेफिक तथा विदेशी पर्यटकों के आगमन जैसे अन्य सूचकों में नवंबर-दिसंबर में तेज गति से बढ़ोतरी हुई। सेवाओं के पीएमआई में क्रमिक रूप से दिसंबर और जनवरी में विस्तार हुआ जिसका कारण उच्चतर कारोबारी गतिविधि रही।

9. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तन द्वारा आकलित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में लगातार छठे महीने में बढ़ी जिसका कारण मजबूत प्रतिकूल आधार प्रभाव था। नवंबर में तुरंत बढ़ने के बाद खाद्य कीमतें दिसंबर में आंशिक रूप से कम हो गईं जो मुख्य रूप से मौसमी नरमी को दर्शाती हैं, हालांकि दलहन की कीमतों में निरंतर कमी के साथ सब्जियों की कीमतें नरम रही। अनाज मुद्रास्फीति दिसंबर में स्थिर कीमतों के साथ नरम रही। तथापि, खाद्य के कुछ घटकों - अंडे, मांस और मछली; तेल और वसा; तथा दूध में वृद्धि हुई। ईंधन और लाइट समूह की मुद्रास्फीति जिसने नवंबर में तेज वृद्धि दिखाई थी, दिसंबर में कुछ नरम हो गई जिसका कारण विद्युत, एलपीजी और केरोसिन मुद्रास्फीति में नरमी थी।

10. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर में और बढ़ गई, ऐसा मुख्य रूप से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) अवार्ड के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के उच्चतर आवास किराया भत्तों (एचआरए) के लागू होने के बाद आवास मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण हुआ। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल तथा इसके सामान में मुद्रास्फीति में

वृद्धि हुई। घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों में अपूर्ण पास-थ्रू को प्रतिलक्षित करते हुए, परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दिसंबर में मंद रही। वस्त्र और फुटवेयर, घर के सामान और सेवाओं, मनोरंजन तथा शिक्षा में भी मुद्रास्फीति कम हुई।

11. रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए परिवार सर्वेक्षण से आकलित परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं आगे के तीन महीनों और आगे के एक वर्ष के लिए उच्च बनी रही, हालांकि एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशा में थोड़ी सी कमी आई। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) में प्रतिक्रिया देने वाली फर्मों ने तीसरी तिमाही में इनपुट मूल्य दबावों और बिक्री मूल्यों में वृद्धि की रिपोर्ट की। इसकी पुष्टि विनिर्माण और सेवा फर्मों द्वारा भी की गई जिन्हें पीएमआई द्वारा पोल कराया गया। संगठित क्षेत्र की मजदूरी वृद्धि स्थायी रही जबकि ग्रामीण मजदूरी वृद्धि में कमी आई।

12. प्रणाली में चलनिधि अधिशेष मोड में बनी हुई है किंतु यह स्थिर रूप से तटस्थता की ओर बढ़ रही है। भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) दिसंबर-जनवरी के दौरान रेपो दर से 12 आधार अंकों के नीचे ट्रेड हुई जबकि नवंबर में यह रेपो दर से 15 आधार अंक नीचे थी। दिसंबर और जनवरी के कुछ दिनों में, सरकारी खर्च में कमी और ज्यादा कर संग्रह के कारण प्रणाली में कमी की स्थिति बनी जिसने रिज़र्व बैंक के लिए चलनिधि उपलब्ध कराना आवश्यक कर दिया। 16 दिसंबर 2017 से शुरू होने वाले दो सप्ताहों के दौरान रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में ₹388 बिलियन की औसत दैनिक निवल चलनिधि उपलब्ध कराई। तथापि, पूरे दिसंबर के लिए रिज़र्व बैंक ने ₹316 बिलियन (निवल दैनिक औसत आधार पर) अवशोषित की। चूंकि जनवरी के चौथे सप्ताह में फिर से प्रणाली में कमी की स्थिति बन गई, तो रिज़र्व बैंक ने ₹145 बिलियन की औसत निवल चलनिधि उपलब्ध कराई। जनवरी के लिए, सामान्य रूप से रिज़र्व बैंक ने ₹353 बिलियन (निवल दैनिक औसत आधार पर) अवशोषित की।

13. व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात में नवंबर और दिसंबर में फिर से उछाल आया। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, अभियांत्रिकी सामान और रसायन की इस वृद्धि में तीन-चौथाई हिस्सेदारी रही, बने बनाए कपड़ों के निर्यात में कमी आई। इसी अवधि के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आयात वृद्धि क्रमिक रूप से बढ़ी जिसमें एक-तिहाई से अधिक वृद्धि पेट्रोलियम (कच्चे तेल

और उत्पाद) से हुई जिसका मुख्य कारण उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें रहीं। पिछले तीन महीनों में गिरावट के बाद दिसंबर में सोने का आयात मूल्य और मात्रों दोनों मामलों में बढ़ गया। मोती और बहुमूल्य नगीना, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा कोयला गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ता रहे। आयात वृद्धि के निर्यात वृद्धि से अधिक होने से दिसंबर माह का व्यापार घाटा 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

14. हालांकि क्रमिक आधार पर वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा तेजी से कम हुआ, फिर भी यह एक वर्ष पहले के अपने स्तर से उच्चतर था जिसका कारण व्यापार घाटे का व्यापक होना था। जबकि निवल प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में एक वर्ष पहले के इसके स्तर से अप्रैल-अक्टूबर 2017 में नरमी आई, निवल विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह में वर्ष 2017-18 (1 फरवरी तक) में उछाल रहा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 फरवरी 2018 को 421.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

परिदृश्य

15. दिसंबर द्विमासिक संकल्प में वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति का 4.3-4.7 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया जिसमें एचआरए में वृद्धि के प्रभाव को भी शामिल किया गया। वास्तविक परिणामों के मामले में, हेडलाइन मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही में औसतन 4.6 प्रतिशत रही जिसका मुख्य कारण नवंबर में खाद्य कीमतों में असाधारण वृद्धि थी। यद्यपि, कीमतें दिसंबर में सहज हो गईं, सर्दियों की मौसमी खाद्य मूल्य नरमी साधारण से कम थी। पेट्रोल और डीजल की घरेलू पंप कीमतें जनवरी में तेजी से बढ़ी जिन्होंने कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में पिछली वृद्धि के पास-थ्रू के पीछे रहना दर्शाया। इन कारकों पर विचार करते हुए, मुद्रास्फीति को अब चौथी तिमाही में 5.1 पर अनुमानित किया गया है जिसमें एचआरए प्रभावी भी शामिल है।

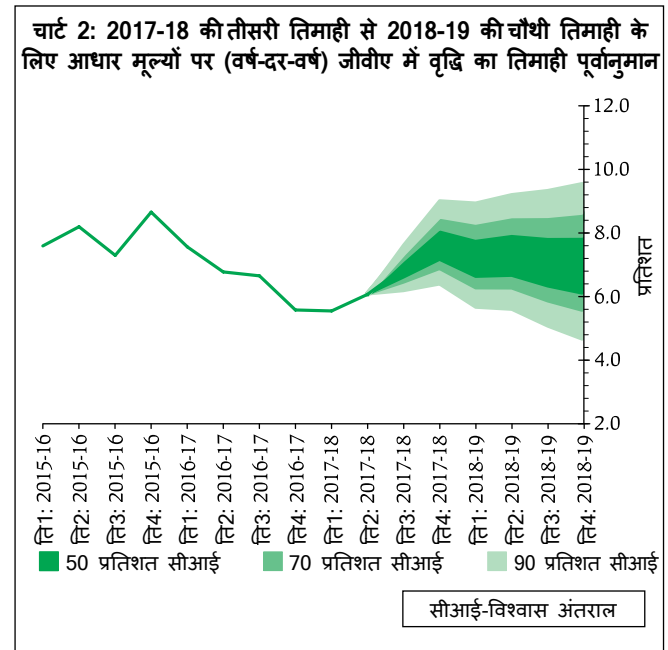
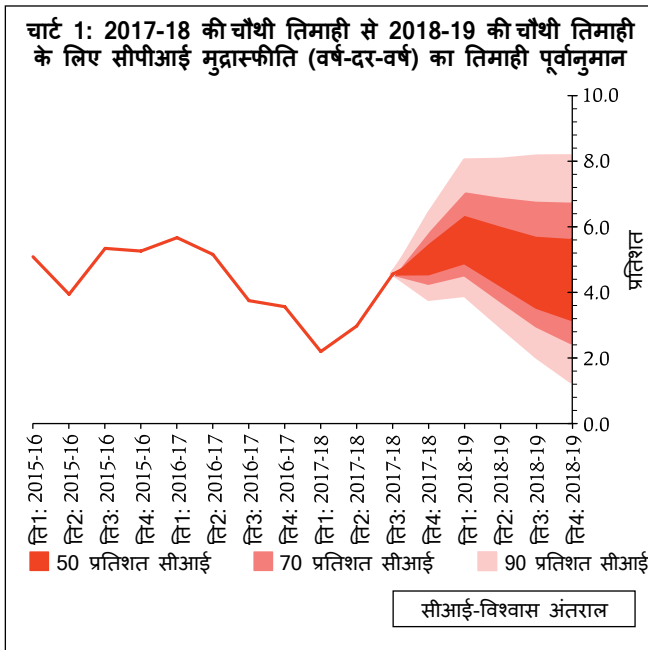
16. चालू वर्ष से परे मुद्रास्फीति परिदृश्य कई कारकों से प्रभावित रहने की संभावना है। सबसे पहला कारक, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अगस्त 2017 से तेजी से बढ़ी हैं, जो मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों द्वारा संचालित होती हैं। दूसरा कारक, गैर-तेल औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में भी एक वैश्विक तेजी देखी गई है। रिज़र्व बैंक के आईओएस में पॉल

करने वाली फर्मों ने निवेश कीमतों के चौथी तिमाही में सख्त होने की उम्मीद की है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के एक परिदृश्य में, बढ़ती निवेश लागत उपभोक्ताओं तक आगे बढ़ने की संभावना है। तीसरा, मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान मानसून पर निर्भर करेगा, जिसे सामान्य माना जा रहा है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2018-19 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान पहली छमाही में 5.1-5.6 प्रतिशत की सीमा में रहने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के घटते सांख्यिकीय एचआरए प्रभाव और दूसरी छमाही में 4.5-4.6 प्रतिशत की कमी और बढ़ते जोखिम शामिल है। (चार्ट 1)। सरकार द्वारा सामान्य मानसून और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन की धारणा को देखते हुए, सातवें सीपीसी के एचआरए प्रभाव के कम हो जाने और नरम खाद्य मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के साथ, दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में मजबूत अनुकूल आधारभूत प्रभावों के चलते सुधार अनुमानित है।

17. विकास के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए 2017-18 के लिए जीवीए विकास 6.6 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। चालू वर्ष से परे, विकास का परिदृश्य कई कारकों से प्रभावित होगा। सबसे पहले, जीएसटी कार्यान्वयन स्थिर हो रहा है, जो आर्थिक गतिविधि के लिए अच्छा है। दूसरा, निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्रेडिट की छूट में सुधार, प्राथमिक पूंजी बाजार से बड़े

संसाधन जुटाने और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में सुधार के रूप में प्रतिबिंबित हो गए है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिए बड़े दबावग्रस्त उधारकर्ताओं को संदर्भित किया जा रहा है। इससे क्रेडिट प्रवाह और नए निवेश की मांग में सुधार होना चाहिए। चौथा, हालांकि वैश्विक विकास में सुधार के कारण निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है, विशेष रूप से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, कुल मांग पर प्रभाव के रूप में कार्य कर सकती है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2018-19 के जीवीए विकास का कुल अनुमान समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ - पहली छमाही में 7.3-7.4 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 7.1-7.2 प्रतिशत की सीमा में 7.2 प्रतिशत है (चार्ट 2)।

18. एमपीसी नोट करती है कि मुद्रास्फीति दृष्टिकोण ऊपर की ओर की कई अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए बढ़ाने का विचलनात्मक प्रभाव 2018-19 की आधार-रेखा के ऊपर प्रमुख मुद्रास्फीति को आगे बढ़ा सकता है और संभावित रूप से दूसरे दौर के प्रभाव पैदा कर सकता है। दूसरा, वैश्विक विकास में तेजी घरेलू मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ कच्चे तेल और कमोडिटी कीमतों पर और दबाव डाल सकता है। तीसरा, केंद्रीय बजट 2018-19 ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन



मूल्य (एमएसपी) पर पहुंचने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का प्रस्ताव रखा है, हालांकि इस स्तर पर मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव का सही परिमाण पूरी तरह से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। चौथा, केंद्रीय बजट में कई मदों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। पांचवीं, केंद्रीय बजट में बताई गई राजकोषीय गिरावट मुद्रास्फीति की धारणा पर असर डाल सकती है। मुद्रास्फीति पर सीधे प्रभाव के अलावा, राजकोषीय गिरावट से व्यापक समग्र-वित्तीय प्रभाव पड़ता है, विशेषकर विस्तृत अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत पर जो पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इससे मुद्रास्फीति का पोषण हो सकता है। छठे, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा घरेलू वित्तीय विकास और मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के संगम से वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो बाह्य निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए, आने वाले महीनों में उभरते मुद्रास्फीति परिदृश्य के विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

19. गंभीरता कम करने वाले भी कुछ कारक हैं। सबसे पहले, क्षमता के उपयोग में कमी बनी हुई है। दूसरा, तेल की कीमतें हाल की अवधि में दोनों तरफ बढ़ी हैं और उत्पादन की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा स्तरों से संभावित रूप से नरम हो सकती हैं। तीसरा, ग्रामीण वास्तविक मजदूरी वृद्धि नरम है।

20. तदनुसार, एमपीसी ने नीति रेपो दर को अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख को जारी रखने का फैसला किया है। एमपीसी टिकाऊ आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति को

4 प्रतिशत के करीब रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

21. एमपीसी नोट करती है कि अर्थव्यवस्था सुधार पथ पर है, जिसमें निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार के प्रारंभिक संकेत शामिल हैं। वैश्विक मांग में सुधार हो रहा है, जिससे घरेलू निवेश गतिविधि को मजबूत करने में मदद होनी चाहिए। ग्रामीण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर केंद्रीय बजट का ध्यान भी एक स्वागत योग्य गतिविधि है, क्योंकि यह ग्रामीण आय और निवेश को समर्थ करेगी और बदले में कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को वृद्धि प्रदान करेगी। नकारात्मक पक्ष में, सार्वजनिक वित्त में गिरावट से निजी वित्तपोषण और निवेश के बाहर हो जाने का जोखिम है। समिति का मानना है कि नवीन सुधार को सावधानी से संगठित करने की और अनुकूल और स्थिर समग्र-वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से एक निरंतर उन्नत मार्ग पर वृद्धि दर्ज किए जाने की जरूरत है।

22. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. विरल वी. आचार्य और डॉ. उर्जित आर. पटेल ने मौद्रिक नीति निर्णय के पक्ष में वोट किया। डॉ. माइकल देबब्रत पात्र ने नीति दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के लिए वोट किया। मौद्रिक नीति समिति के कार्यवृत्त 21 फरवरी 2018 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

23. एमपीसी की अगली बैठक 4 और 5 अप्रैल 2018 को होना निर्धारित है।

भाषण

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना और प्रबंध करना
विरल वी. आचार्य

भारत के आर्थिक सुधार: अपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में चिंतन
विजय जोशी

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना और प्रबंध करना*

विरल वी. आचार्य

मैं सर्वप्रथम आप सबको खुशहाल और स्वस्थ नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।

मुझे अपने वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) और उनकी आयोजन समिति का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज भारतीय बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझने और उसके बेहतर प्रबंधन के बारे में बात करूंगा। फिर भी, शुरुआत में कहीं और से करूंगा, और अक्सर ऐतिहासिक रूप से शुरुआत के लिए यह अच्छी जगह रही है।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में विकसित देशों सहित अनेक अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी ऋणों के प्रति बैंक एक्सपोजर काफी बढ़ा है, जिससे बैंकों के तुलनपत्रों का सरकारी ऋणों के साथ जुड़ाव गहराया है। माना जाता है कि इस स्थिति के पीछे अनेक महत्वपूर्ण चालक काम कर रहे हैं:-

ए. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अपवादात्मक रूप से समायोजनकारी मौद्रिक नीति के साथ ही संकट के बाद सामान्यतः वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में आई गिरावट ने सुरक्षित स्वर्ग अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी ऋण रखने की स्वाभाविक मांग उत्पन्न की है।

बी. बैंकों के लिए बासल पूंजी विनियमावली के अधीन होम कंट्रीज तथा कुछ करेंसी यूनियनों में सरकारी बांड एक्सपोजरों पर कोई संकेंद्रण सीमाएं न लगाने के अलावा, शून्य प्रतिशत जोखिम भार जारी है। इससे सरकारी बांड समान जोखिम वाली अन्य आस्तियों की तुलना में अधिक आकर्षक बन जाते हैं। सरकारी बांडों की तरलता तथा उनका केंद्रीय बैंकों द्वारा पुनर्वित्त के लिए संपार्श्विक के

रूप में पात्र होना उनकी इस आकर्षकता में वृद्धि ही करता है।

सी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) विनियमावली (बासल III के अंतर्गत) में भी बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) धारण करें। यद्यपि एचक्यूएलए के रूप में पात्र अन्य प्रतिभूतियां हैं, किंतु सरकारी बांडों को धारण करने की लागत और सहजता के कारण वे सर्वाधिक आकर्षक हैं।

हालांकि सरकारी बांड किसी भी समय अन्य लिखतों से अधिक सुरक्षित और तरल हैं, किंतु वे वैसे ही बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकारी ऋणों पर ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम दोनों ही गतिशील प्रकृति के हैं, और वास्तव में ये जोखिम शांत दिखने वाले आरंभिक चरणों से भ्रामक रूप से बदल सकते हैं।

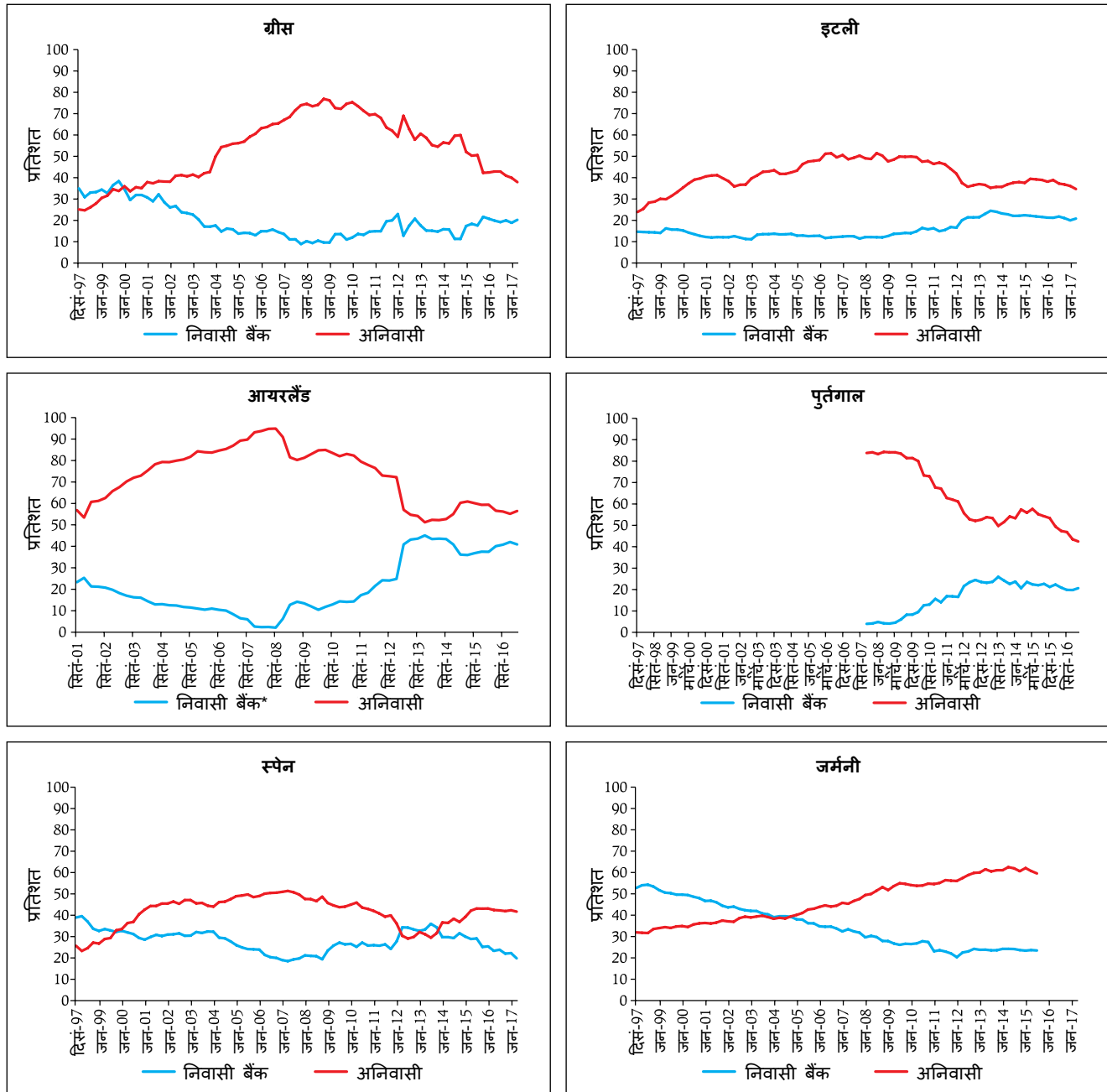
सरकारी ऋण-बैंक संबंध और यूरोज़ोन सरकारी ऋण संकट

सरकारी ऋण बैंक संबंध के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषतः यूरोप का ध्यान आकर्षित किया है। ऋण - संकट का सामना करने वाले देशों (ग्रीस, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन, या जीआईआईपीएस) में निवासी बैंकों का घरेलू सरकारी ऋणों के प्रति एक्सपोजर संकट के दौरान और बाद में काफी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के सरकारी ऋणों में बढ़े हुए एक्सपोजर में अधिक जोखिमपूर्ण सरकारों, अर्थात् जीआईआईपीएस के प्रति पक्षपात दिखाई देता है। इसमें निवासी बैंकों का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि अनिवासी बैंकों का कम हो रहा है; निवासी बैंकों की धारिता उच्च स्तर पर बनी हुई है (चार्ट 1)।

बैंकों द्वारा घरेलू सरकारी ऋण की वृद्धि धारिता ने उस दायरे के यूरोपियन देशों में सरकारी ऋण संकट को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। जनवरी 2007 से लेकर सितंबर 2008 के अंत में पहले बैंक बेल-आउट तक बैंक उधारों के कीमत-लागत अंतर में लगातार वृद्धि हुई, जबकि सरकारी उधार कीमत-लागत अंतर निम्न स्तर पर रहा। सितंबर- अक्टूबर 2008 के दौरान विकसित देशों के बीच

* यह व्याख्यान डॉ. विरल वी आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 जनवरी 2018 को फिम्डा द्वारा होटल ताजमहल पैलेस, मुंबई में आयोजित भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) वार्षिक भोज 2018 के अवसर पर दिया गया।

चार्ट 1: जीआईआईपीएस और जर्मनी के लिए निवासी बैंकों एवं अनिवासीयों द्वारा सरकारी बॉन्डों की धारिता



जर्मनी के आंकड़े 'जनरल गवर्नमेंट डेट' पर आधारित हैं और इसमें सरकारी बॉन्ड और ऋण दोनों शामिल हैं।
 *आयरलैंड में 'निवासी बैंक', बैंक ऑफ आयरलैंड की धारिता को अलग नहीं करते हैं।
 स्रोत: मेल्जर एंड पिसानी-फेरी (2012) में विकसित सरकारी बॉन्ड होल्डिंग्स के ब्रूजेल डाटाबेस मार्च 2017 तक अद्यतन

बैंक बेल-आउट एक व्यापक वैशिष्ट्य बन गए, और बैंक उधार कीमत-लागत अंतर में अत्यंत गिरावट होने के साथ-साथ सरकारी उधार कीमत-लागत अंतर में तदनु रूप वृद्धि हुई। वास्तव में, बैंक बेल-आउट ने ऋण जोखिम को वित्तीय क्षेत्र से अंतरित कर सरकारों को दे दिया (आचार्य, देशलर

और शनबल, 2012; 2015)। फिर भी, और विशेषतः 2010 में ग्रीक चूक के बाद यूरोपियन परिधि में समष्टि आर्थिक चिंताओं के कारण सरकारी स्प्रेड का फैलाव जर्मन बंड्स पर भी हुआ जिससे बैंक को काफी मूल्यांकन हानि हुई और उनकी ऋण शोधन क्षमता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

इसके साथ ही, सरकारी बांडों पर बढ़ते हुए प्रतिफल ने बैंकों को अपने घरेलू सरकारी एक्सपोजरों का संचय करने को ललचाया। अल्पकालिक निधियों, विशेषतः जमाराशि और मुद्रा बाजारों में लगातार पहुंच के साथ ही जीआईआईपीएस तथा कुछ जीआईआईपीएस से इतर देशों में भी बैंकों ने जीआईआईपीएस सरकारी बांडों में निवेश बढ़ाया ताकि भावी प्रतिलाभ बढ़ने की आशा में जर्मन बंड्स की खरीद की ओर आगे बढ़ा जा सके (आचार्य और स्टिफेन, 2015)। अपर्याप्त पूंजी वाले बैंकों के पुनरुत्थान के लिए जुए के रूप में यह "कैरी ट्रेड" विशेष रूप से आकर्षक था, जिसमें किसी अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता के बिना त्वरित कोष-लाभों का प्रभावी अनुसरण किया जा सकता था, किंतु यदि यह प्रतिफल संवाहक व्यापार (कैरी) और भी ज्यादा फैलता, तो आर्थिक जोखिम भी दोगुने हो जाते....और ऐसा हुआ। ग्रीक चूक और जीआईआईपीएस देशों में परिणामी सोवरीन ऋण संकट ने यह दर्शाया कि सरकारी ऋण में अत्यधिक एक्सपोजर वाले बैंक सोवरीन ऋण लागत में उतार-चढ़ाव से सर्वाधिक प्रभावित हुए और उन्हें संबंधित बाजार के बड़े हुए वित्तपोषण परिणामों का सामना करना पड़ा।

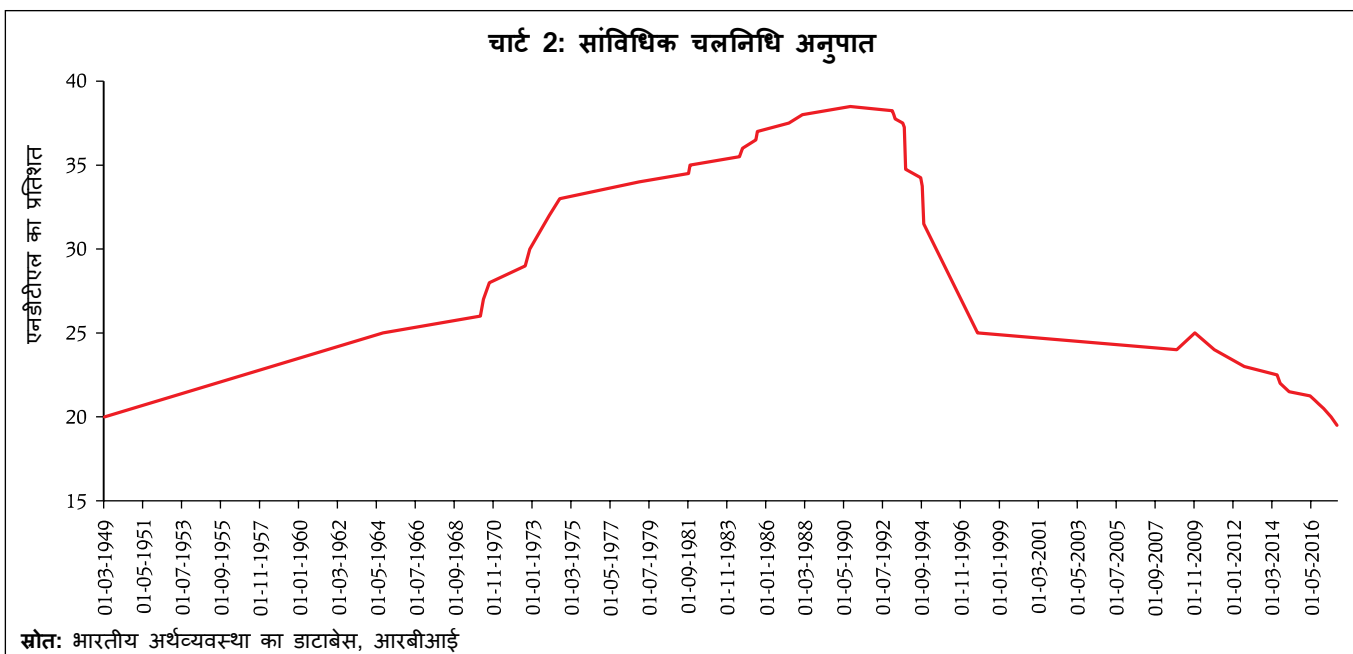
ऐसे सरकारी ऋण- बैंक संबंधों से एक दुधारी फीडबैक समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि घरेलू सरकारी बांडों के प्रति बैंकों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, सरकारी बांड प्रतिलाभ में किसी प्रतिकूल गतिविधि या सोवरीन घटना घटित होने से बैंक के अपर्याप्त पूंजीकरण और बेल-आउट की शुरुआत

हो सकती है, जिसमें और अधिक सरकारी उधार लेना और सरकारी ऋण प्रतिलाभ बढ़ना निहित है, और इससे बैंक की पूंजी का और अधिक हास और आगे और बेल-आउट करना आवश्यक होगा, और यह चलता रहेगा (आचार्य देशलर और शनबल, 2012; 2015)।

इस प्रकार, घरेलू सरकारी ऋणों में निहित जोखिमों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर को समझना और उसका उचित प्रबंध करना केवल बैंकिंग क्षेत्र के लाभों और पूंजी संबंधी मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में यह समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता से संबंधित है।

भारतीय संदर्भ

भारत में बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के निर्धारण और लोक ऋण के समर्थन में बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के चलते सरकारी ऋणों और बैंकों के तुलनपत्रों का संबंध सुदृढ़ रहा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम चलनिधि आस्तियां (मूलतः सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूति तथा राज्य विकास ऋण (एसडीएल)) कहलाने वाली उप-सरकारी प्रतिभूतियों, दोनों में बनाए रखें। यह अनुपात ऐतिहासिक रूप से 38.5 प्रतिशत तक ऊंचा रहा है, किंतु अब क्रमिक रूप से घट कर 19.5 प्रतिशत रह गया है (चार्ट 2)।



इसे बासल III के अंतर्गत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार बनाने के लिए लगातार घटाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप बैंक उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल की बड़ी संख्या के कारण सरकार की उधार लेने की लागत, जो मुद्रास्फीति, राजकोषीय या अन्य घरेलू अथवा वैश्विक समष्टि आर्थिक गतिविधियों के कारण बढ़ सकती है, के पुनर्मूल्यन के प्रति एक्सपोज होते हैं। अंतः में (i) भारतीय बैंकों के इस ब्याज दर जोखिम के प्रति एक्सपोजर के महत्व; (ii) बैंकों द्वारा अपने कोष परिचालनों की और अधिक ध्यान और संसाधन लगाने पर बल देने; तथा (iii) बैंकों द्वारा अपने जोखिम का प्रबंध करने हेतु उपलब्ध विकल्पों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना

आइए, पहले सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं। जब अंतर्निहित ब्याज दरों में कोई (मामूली) बदलाव आता है, जैसे सरकार की उधार लेने की लागत में, तब किसी बांड पोर्टफोलियो के लिए (अनुमानित) कीमत समीकरण को देखने से ब्याज दर जोखिम बड़ी आसानी से समझ में आता है:

$$\Delta P = -P \times D \times \Delta Y,$$

जहां Δ परिवर्तन का द्योतक है;
P पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य है;

D "अवधि"का द्योतक है, जो कि पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता का माप है; तथा Y अंतर्निहित ब्याज दर (या पोर्टफोलियो प्रतिफल) का द्योतक है।

दूसरे शब्दों में, निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य तीन कारकों का कार्य है:

- क. P द्वारा निर्दिष्ट पोर्टफोलियो का आकार
- ख. D द्वारा निर्दिष्ट अवधि, जो पोर्टफोलियो के अंतर्गत बांडों के नकद प्रवाहों की भारित औसत परिपक्वता दर्शाती है।
- ग. ΔY द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल में वृद्धि।

उदाहरणार्थ 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति बेंचमार्क प्रतिफल में 0.1 प्रतिशत या 10 आधार अंक (बीपीएस) वृद्धि होने पर 1 ट्रिलियन आकार के 10 वर्ष की अवधि वाले किसी पोर्टफोलियो के मूल्य में 10 बिलियन की गिरावट होती है।

आइए, हम वर्तमान और ऐतिहासिक भारतीय संदर्भ में इनमें से प्रत्येक कारक पर विचार करते हैं।

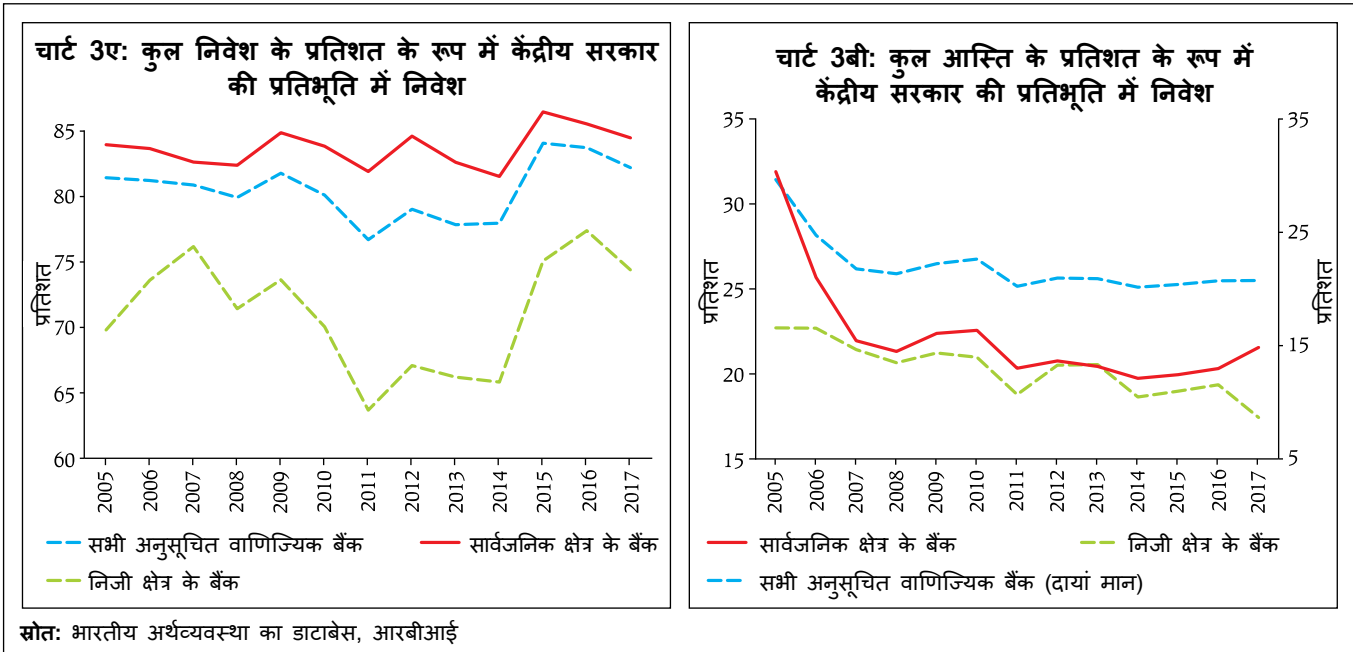
पोर्टफोलियो का आकार¹

बकाया सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत (जून 2017) है। वित्त वर्ष 2016-17 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कुल निवेश का लगभग 82 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूति में था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए तदनु रूप आंकड़ा इससे कुछ अधिक, यानी 84 प्रतिशत है। 2014 से यह एक्सपोजर उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है (चार्ट 3ए)।

सरकार के समेकित ऋण/जीडीपी अनुपात में अपेक्षाकृत स्थिरता के बावजूद सरकारी प्रतिभूति का निवेशक आधार मुख्यतः घरेलू संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी बांडों की मांग की तुलना में अक्सर अतिरिक्त पूर्ति की स्थितियां होती हैं, विशेषतः भारतीय बैंकों द्वारा धारित अतिरिक्त एसएलआर के उच्च स्तर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय बैंकों की सरकारी ऋण धारिता के उच्च स्तर का एक कारण यह है कि भारतीय परिवेश में अपेक्षाकृत अति-पूर्ति के मामले में वे ही अवशिष्ट धारक होते हैं, क्योंकि उनके निवेश अधिदेशों के कारण अन्य प्रमुख संस्थागत निवेशक श्रेणियों, यथा बीमा और पेंशन निधियों की क्षमता सीमित होती है। आजकल दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि रिज़र्व बैंक के चलनिधि निपटान परिचालनों में बैंकिंग प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि पूर्णतः जमा नहीं की जाती, जिससे अवधि जोखिम न्यूनतम हो जाता। बल्कि अतिरिक्त चलनिधि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है क्योंकि पूंजी की कमी का सामना कर रहे बैंक के लिये घरेलू सरकारी कर्ज अल्प कालिक के लिये अत्यधिक आकर्षक होते हैं, चाहे उसके लिये लंबी अवधि के लिए ही क्यों न इंतजार करना पड़े (जैसा कि मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है, यूरोपियन संदर्भ में भी यही मामला बनता है)।

इसके परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्र में सरकारी प्रतिभूति एक्सपोजर का आकार, और इसीलिए, उसका ब्याज दर जोखिम पूर्णार्थ में अधिक है, और जब इसे कुल आस्तियों के अनुपात में गिना

¹ विधि के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूति) तथा राज्य विकास ऋणों (एसडीएफ), दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है। निवेश बही में ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के अनुसार दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तथापि, सरलता के लिए इस व्याख्यान में दिए गए आंकड़े और चार्ट केवल सरकारी प्रतिभूति से संबंधित हैं। एसडीएल को शामिल करने से समान्य निष्कर्ष बदलेंगे नहीं, और चूंकि ये ब्याज दर जोखिम में योगदान देते हैं, उन्हें मजबूती ही प्रदान करेंगे।

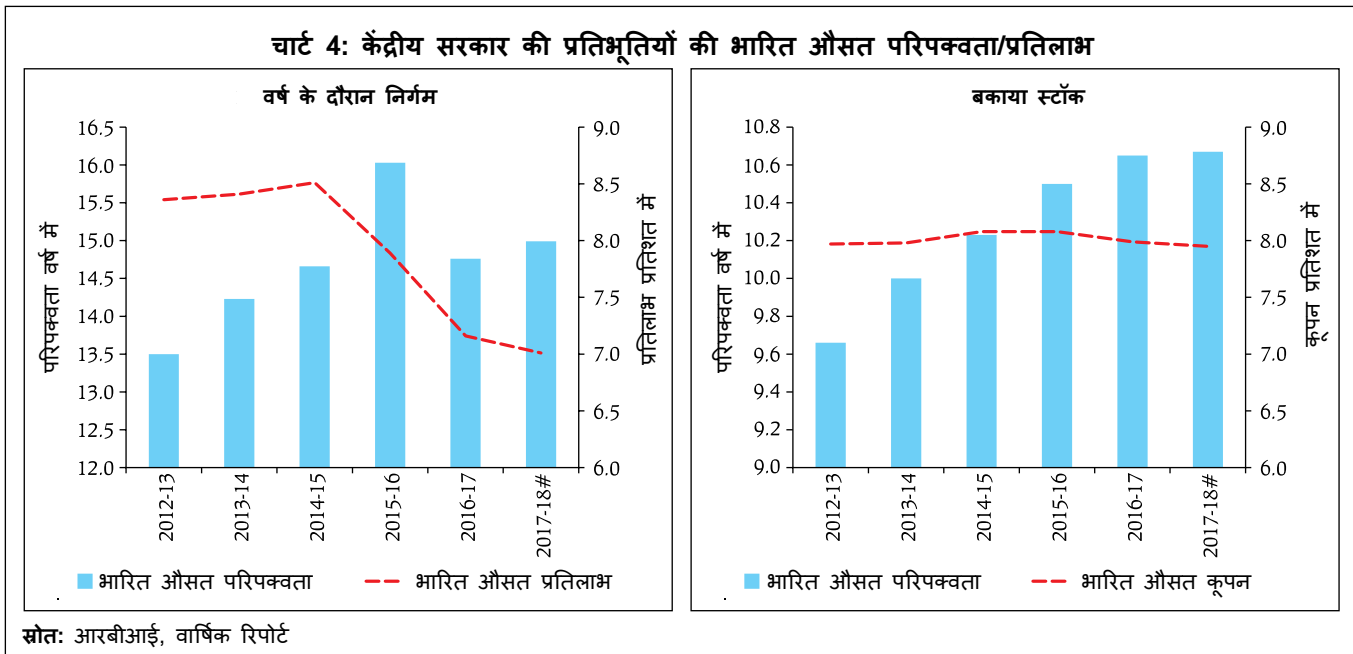


जाता है तब निजी बैंक की तुलना में सरकारी बैंकों में यह अपेक्षाकृत अधिक है (चार्ट 3बी)।

निवेश बही की अवधि और सरकारी प्रतिभूति की परिपक्वता संरचना

बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो में अत्यधिक ब्याज दर एक्सपोजर का कारण केवल उनकी धारिता का

आकार नहीं है, बल्कि प्राथमिक निर्गम की परिपक्वता अवधि में वृद्धि भी है। सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता वर्ष 2012-13 के 9.66 वर्ष की तुलना में लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 में 10.67 वर्ष हो गई है (चार्ट 4)। पिछले पाँच वर्ष के दौरान वार्षिक निर्गम की औसत प्रवृत्ति उच्च, अर्थात् लगभग 15 वर्ष रही है।



सरकारी प्रतिभूति की इस बदलती हुई परिपक्वता संरचना का बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) तथा ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)। बैंक सामान्यतः उनके द्वारा अधिगृहीत प्रतिभूतियों को परिपक्वता अवधि तक धारण करने के इरादे से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अनुषंगियों में धारित इक्विटी जैसे कुछ अपवादों को छोड़ कर एचटीएम के अंतर्गत केवल ऋण प्रतिभूतियां धारण करने की अनुमति है। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियां धारण करने से बैंकों को मूल्यन में परिवर्तन से बचाव उपलब्ध होता है। तथापि, एचटीएम बही में धारिता अधिकतम सीमा के अधीन है।

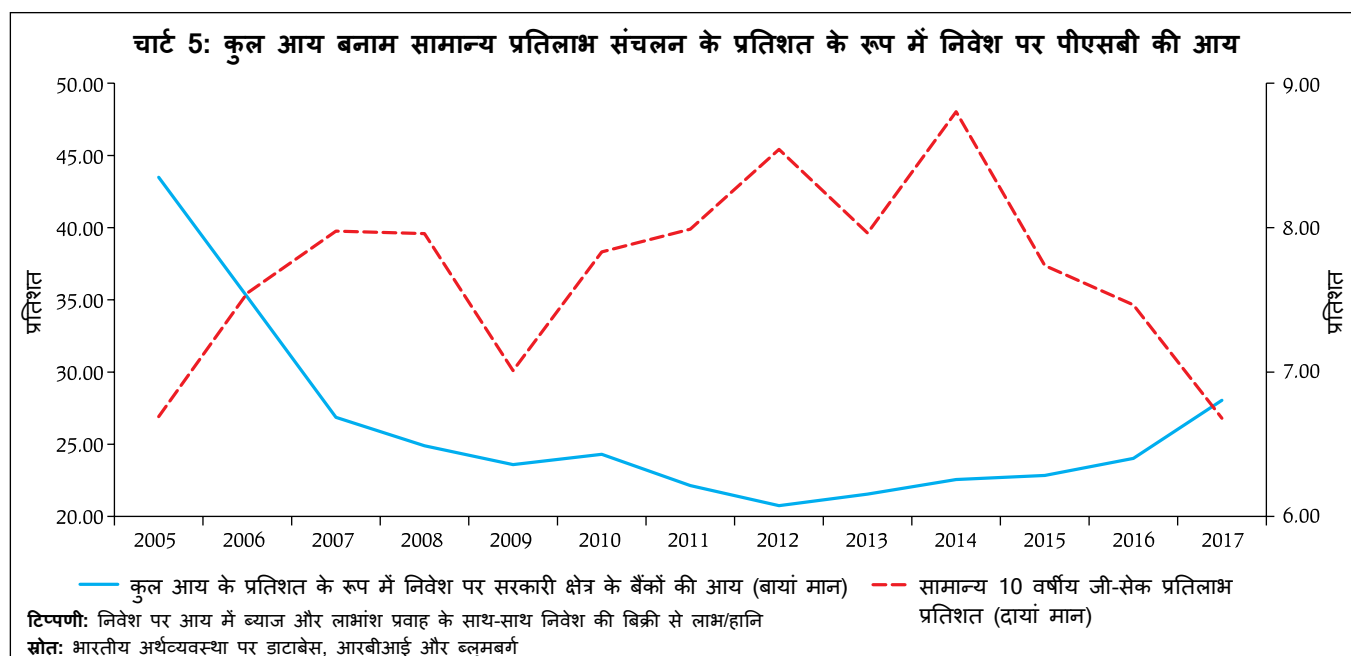
एफएस और एचएफटी श्रेणियां मिल कर बैंक की ट्रेडिंग बही बनाती है। बैंकों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता, पूंजी की स्थिति आदि के आधार पर एफएस और एचएफटी के अंतर्गत धारिता की सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इन दोनों बहियों में धारित प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य पर दर्शाया जाना अपेक्षित है। एचएफटी बही को एफएस से अधिक नियमित रूप से मार्क टु मार्केट किया जाना अपेक्षित है। निवेश के मूल्यन की बारंबारता विशिष्ट रूप से बैंकों की निवेश बही की संरचना की निर्धारक है। इसके परिणामस्वरूप, सितंबर

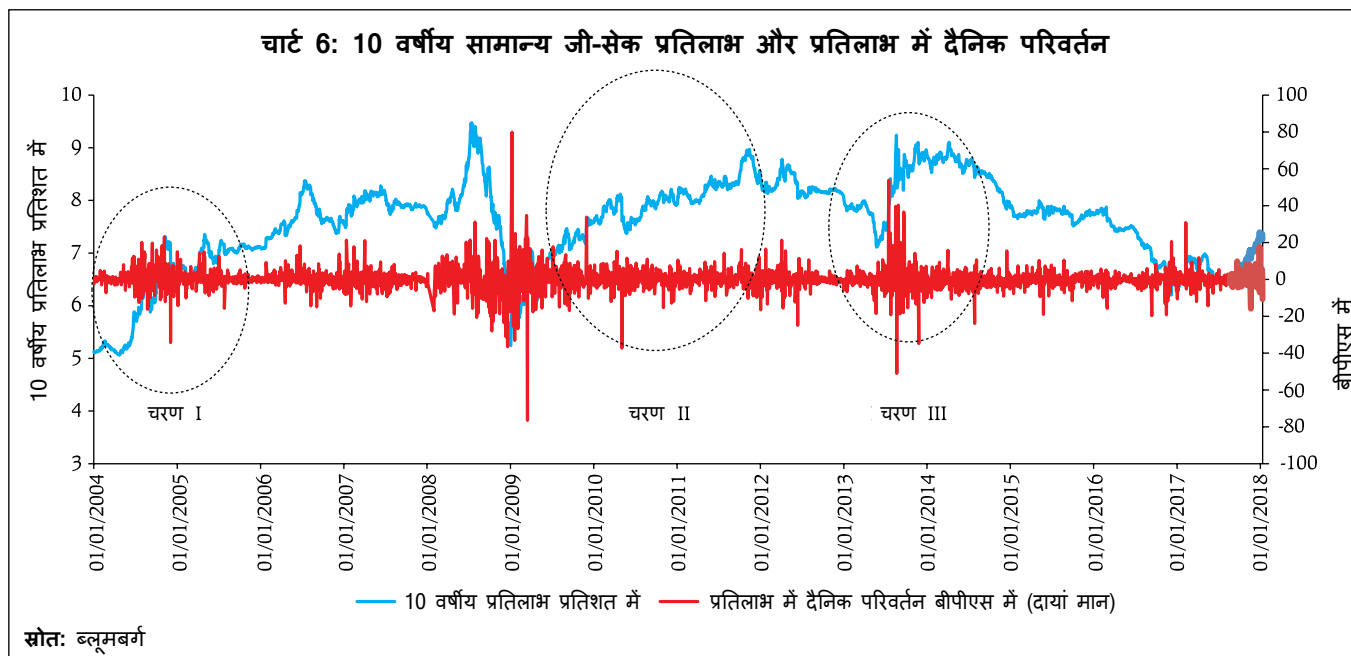
2017 (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, दिसंबर 2017) को एचटीएम, एफएस तथा एचएफटी का हिस्सा क्रमशः 55.4 प्रतिशत, 42.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत रहा। वर्तमान में बैंकों की एफएस बही की औसत संशोधित अवधि लगभग 2.9 वर्ष है। निजी क्षेत्र के बैंकों के 2.0 वर्ष की तुलना में पीएसबी के लिए यह 3.5 वर्ष के उच्च स्तर पर है।

निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों की अपेक्षाकृत लंबी अवधि और संकेंद्रण के साथ ही बैंकों की आय और पूंजी प्रतिकूल प्रतिलाभ गतिविधियों के प्रति एक्सपोज होते हैं, विशेषतः जब पिछले पांच वर्षों से निवेश आय का हिस्सा बढ़ रहा है। चार्ट 5 में इस तथ्य को सारगर्भित रूप से दर्शाया गया है कि बैंकों की निवेश आय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है - हाल के वर्षों में सामान्यतः प्रतिलाभ कम हुए हैं, और परिणामतः निवेश आय बढ़ी है। बदले में, और इस अवधि के दौरान, विशेषतः पीएसबी में मंद क्रेडिट संवृद्धि को देखते हुए निवेश आय ने बैंक के अर्जनों का निर्धारण करने में पुनः महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरु किया है।

प्रतिलाभों की गतिविधियां-निरंतर प्रतिलाभ वृद्धि के चरण

भारत में सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों ने नियमित अंतरालों पर लगभग 200 बीपीएस की अनवरत वृद्धि के सांयोगिक चरण देखे हैं। पिछले 15 वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिलाभ के तीन प्रमुख चरण चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं:-





- ए) चरण I - जब एक लंबी उछाल के बाद 2004 की दूसरी छमाही में ब्याज दर चक्र 5.00 प्रतिशत से बढ़कर 7.00 प्रतिशत हुआ;
- बी) चरण II - वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, जब प्रतिलाभ दिसंबर 2005 में 5.25 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2011 तक लगभग 8.80 प्रतिशत हुआ; तथा
- सी) चरण III - टेपर टैन्ट्रम प्रकरण के दौरान, जब मई 2013 के अंत में प्रतिलाभ लगभग 7.25% से दिसंबर 2013 में अंत में 9 प्रतिशत से कुछ कम तक बढ़ा।

यह समय - क्रम और सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ गतिविधियों के ये प्रासंगिक चरण दर्शाने के पीछे मेरा मुद्दा यह है कि जब सरकारी बांड प्रतिलाभ तेजी से बढ़ते हैं, और बैंकों के निवेश लाभ कम होते हैं, तब बैंकों को बार-बार आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों (एफएसआर) में बैंकों की पूंजी और लाभप्रदता पर ऐसी बड़ी ब्याज दर गतिविधियों के प्रभाव को नियमित रूप से दर्शाया गया है। बैंकों को इस जोखिम को भलीभांति जान और समझ लेना चाहिए। शायद वे जानते हैं और मुद्दा वास्तव में उन प्रलोभनों का है, जिसके कारण वे इस जोखिम की उपेक्षा करते हैं। अब मैं इस पर आता हूँ।

चित आया, तो मैं जीता, पट आया तो विनियामक भुगतेश
सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों में निरंतर वृद्धि के ये प्रासंगिक चरण किस प्रकार खेले गए?

चरण 1 के दौरान विनियामक धैर्य की जोरदार गुहार के जवाब में बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) लेखांकन श्रेणी के अंतर्गत अधिदेशित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 25 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतिधारण करने की अनुमति दी गई थी। विनियम ने बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में अन्य लेखांकन श्रेणियों में से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियां परिवर्तित करने हेतु सक्षम किया। ये ऐसी विशेषता है, जो अब वार्षिक पैमाना बन गया है।

सितंबर 2013 से मार्च 2014 तक छः माह के लिए मूल्यांकन हानियों की मान्यता के आस्थगत के अतिरिक्त चरण III में भी इसी प्रकार का एकबारगी अंतरण दिया गया।

चरण II में आरबीआई द्वारा खुले बाजार में नियमित रूप से खरीद के द्वारा प्रतिलाभों में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को काफी हद तक कम किया गया, जिसका नियोजन दीर्घ-कालिक सरकारी प्रतिभूति प्रति लाभों के लिए करने के बजाए विशिष्ट रूप से टिकाऊ चलनिधि प्रबंध करने और मुद्रा बाजार दरों को एक दिवसीय नीतिगत दरों के समीप लाना सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

ये उस तरह के उपाय भी हैं, जिन्हें बढ़ते हुए प्रतिलाभों के वर्तमान चरण में अपनाने के लिए कुछ बैंकों ने रिजर्व बैंक से पुनः अनुरोध किया है, जहाँ अगस्त 2017 के अंत में लगभग 6.50 प्रतिशत बढ़कर अब प्रतिलाभ लगभग 7.45 प्रतिशत हो गए हैं।

बैंकों के ब्याज दर जोखिम का प्रबंध हर बार और बार-बार उनका विनियामक नहीं कर सकता है। विनियामक वित्तीय स्थिरता के हित में ऐसी कठोर और मुश्किल स्थिति के बीच फंस जाता है और अक्सर सहायता करता है। तथापि, बैंकों के ब्याज दर जोखिम को कम करने हेतु तथ्यों पर आधारित विनियामक छूट का नियमित प्रयोग सरकारी प्रतिभूति बाजार में कुशल कीमत खोज तथा सरकारी प्रतिभूति निर्गमकर्ता के लिए प्रभावी बाजार अनुशासन की दृष्टि से वांछित नहीं है। न ही यह बैंकों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन संस्कृति का विकास करने से सुसंगत है। चित में जीता, पट विनियामक भुगतानों जैसे विषम विकल्पों का सहारा लेना स्टैरॉइड्स (रसायनों) का सहारा लेने जैसा है। ये लत लगाने जैसा है, जिसके दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणाम पुनः पूर्व दशा में आने के रूप में सामने आते हैं। यद्यपि आकस्मिक गहन समस्या से उबरने के लिए उनका प्रयोग न्यायोचित है। इसलिए, बैंकिंग प्रणाली के लिए बेहतर होगा कि अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूती का निर्माण करे, अर्थात् आंतरिक रूप से बल दें और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कुशल प्रक्रियाएं बनाएं।²

अब मैं इस पर विचार करूंगा कि इसे हासिल करने के लिए बैंकों द्वारा क्या किया जा सकता है।

² बैंकों के लिए ब्याज दर जोखिम पर और अधिक फोकस करने के अन्य कारण भी हैं, जिन्हें मैंने सरलता और संक्षिप्तता के कारण छुआ ही नहीं है। उदाहरणार्थ, बैंक न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम का सामना करते हैं, बल्कि बैंकिंग बही में भी जोखिम होती है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों से अपेक्षित है कि वे संपूर्ण तुलनपत्र के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन (ΔEVE) तथा निवल ब्याज आय (ΔNI) की गणना करें, न कि केवल बैंकिंग बही के लिए। तथापि बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) में वैश्विक बैंकों के बीच वैश्विक सामंजस्य, पारदर्शिता तथा तुलनीयता बढ़ाने की दृष्टि से बैंकों से अपेक्षित होगा कि आगे चलते हुए आईआरआरबीबी की गणना अलग से करें तथा संशोधित बीसीबीएस मानकों के आधार पर इसका प्रकटीकरण करें। इसी प्रकार, निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक अध्ययन दल की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि अस्थिर दर वाले ऋणों को किसी हाइव बैंचमार्क से संबद्ध किया जाए। इसकी शुरुआत होने पर बैंक उच्चतर बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज होंगे, जिसके कारण ब्याज दर जोखिमों का अधिक सक्रिय प्रबंधन आवश्यक हो जाएगा।

बैंकों के ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन

बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते हुए ब्याज दर एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए सरकार-बैंक संबंध पर दोनों तरफ से ध्यान देना आवश्यक है। जहां सरकारी बांड बाजार में दीर्घकालिक निवेशक सहभागिता, देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों को गहन करना और सरकारी ऋण संरचना का बैंक के तुलनपत्रों की विविक्षा के प्रति संवेदनशील बने रहना आवश्यक है, वहीं बैंकों को भी तुलनपत्र पर ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने के लिए उसके आकार और अवधि का सक्रियता से प्रबंध करना होगा तथा जोखिम अंतरण के लिए बाजारों तक पहुँच बनाना आवश्यक होगा।

वांछित विकल्प उस बाँड कीमत समीकरण से मिलेगा, जिसे मैंने पहले ही बताया है:

$$\Delta P = -P \times D \times \Delta Y,$$

इस प्रकार, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन विकल्पों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- ए. पी को संबोधित करने वाले उपाय, यथा बैंकों के सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो का आकार
- बी. डी को संबोधित करने वाले उपाय, यथा अवधि जोखिम तथा
- सी. प्रतिफल में संभाव्य बड़े परिवर्तनों वाले परिदृश्यों में मूल्यांकन प्रभाव को संबोधित करने वाले उपाय।

बैंकों में सरकारी प्रतिभूतियों के आकार का समाधान करने वाले उपाय

बैंकों में सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो का आकार मुख्यतः बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धी आस्तियों के बीच चुने गए तुलनपत्र विकल्पों का कार्य है। यह मानते हुए कि सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो ब्याज दर जोखिम के अधीन है, शुरुआत में ही निम्नलिखित रूपरेखा के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन रणनीति बनाई जा सकती है:

1. बैंक का बोर्ड कोष प्रमुख तथा मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के साथ विचार-विमर्श करके पोर्टफोलियो के लिए जोखिम सीमाओं का अनुमोदन उस पूंजी के अनुसार कर सकता है, जिस पर जोखिम लिया जा सकता है। इस निर्दिष्ट जोखिम पूंजी का रूपांतरण, किसी कॉर्पोरेट बजट की ही तरह एक जोखिम रणनीति में होना चाहिए और उसे इस तरह संरक्षित किया जाना चाहिए कि वह केवल आसानी से लाभ उठाने लायक

- अनुपालन सीमा के बजाए बदलते हुए जोखिमों के प्रति समायोजित हो जाए।
2. यह निर्दिष्ट जोखिम पूंजी, जिसे जोखिम पर मूल्य अथवा प्रत्याशित हानि विधि के अंतर्गत बांड प्रतिलाभों के लिए उच्च आत्मविश्वास स्तर की अनुगामी घटनाओं के रूप में मॉडल बनाया जा सकता है, किसी उचित दबाव परिदृश्य के अंतर्गत नष्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अत्यंत कम संभावना की स्थिति को छोड़ कर, बैंक को ट्रेजरी कार्यों के लिए आवंटित पूंजी को खोना नहीं चाहिए।
 3. जैसा कि मैंने प्रासंगिक उतार-चढ़ाव के चरण दर्शाते हुए स्पष्ट किया है, प्रतिलाभ गतिविधियों की गैर-स्थिरता को देखते हुए (यह जोखिम, कि जोखिम में परिवर्तन होगा, या दूसरे शब्दों में, प्रतिलाभ उतार-चढ़ाव अनेक संभावनाओं में से चुना गया हो), बैंकों को ऐतिहासिक दबाव परिदृश्य को भी शामिल करना चाहिए। इन ऐतिहासिक दबाव परीक्षणों में भी ट्रेजरी कार्यों के लिए आवंटित पूंजी नष्ट नहीं होनी चाहिए।
 4. इसके अतिरिक्त, बैंकों को विपरीत दबाव परीक्षण भी करने चाहिए, अर्थात् सवाल पूछें, जैसे किस प्रकार की सरकारी-प्रतिभूतियां प्रतिलाभ गतिविधियां, क्या प्रतिलाभ लोच ढलान पर न्यूनतम, किंतु आदर्श समांतर उपाय आवंटित पूंजी को नष्ट कर देंगे? जी हाँ, आरबीआई द्वारा ऐसे उल्टे दबाव परीक्षणों की सिफारीश की गई है, और इन्हें बोर्ड-स्तरीय जोखिम चर्चाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है।
 5. तथापि, कोई भी दबाव परीक्षण परिपूर्ण नहीं है; और न ही कोई जोखिम उपाय, जैसे कि जोखिम पर मूल्य या प्रत्याशित हानियां, जो ऐतिहासिक वितरण का प्रयोग करते हैं, भावी प्रतिफल गतिविधियों के स्वरूप का पूरी तरह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बैंकों को लचीलेपन के लिए भी सुदृढ़ जोखिम नियंत्रण प्रणालियां अपनाना आवश्यक हैं। इसमें संकेद्रण सीमाएं शामिल हो सकती हैं, अतएव बैंक या तो सरकारी प्रतिभूतियों में आस्तियों के आंतरिक रूप से सहमत कुल अनुपात से ज्यादा एक्सपोजर नहीं करते हैं, या फिर यह अतिरिक्त एसएलआर बैंक द्वारा निवेश के लिए पूंजी आवंटन में जोखिम की शर्तों के अनुसार होना चाहिए।
 6. ट्रेजरी स्तरीय प्रोत्साहन संबंधी मुद्दों को आगे संबोधित करने की दृष्टि से बैंक गत्यात्मक हानि रोधक सीमाएं लगाने पर विचार कर सकते हैं। आगे की हानियों से बचने के लिए एक बार निर्दिष्ट जोखिम पूंजी के एक विशिष्ट प्रतिशत को पार करने के बाद किसी जोखिम में वृद्धि को धीमा किया जाना चाहिए, या संभव हो, तो रोक ही देना चाहिए (यह प्राप्त पूंजी हानि की सीमा पर निर्भर करेगा), न कि प्रतिभूतियों के रोटेशन के द्वारा या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनदेखा करके अनुचित लाभ उठाना चाहिए। इसके बजाए, मुख्य जोखिम अधिकारी के द्वारा प्राप्त हानियों और अवशिष्ट जोखिम के बारे में बोर्ड को सूचित करना चाहिए तथा निवेश पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर करते हुए, उसमें निहित जोखिम को एक समयबद्ध और क्रमिक रूप में कम किया जाए।
 7. इसके अतिरिक्त, कोष-प्रधान तथा सभी महत्वपूर्ण जोखिम-लेनेवालों के लिए कैरियर प्रोत्साहन के रूप में यथार्थ परिणामों के अनुसार नकद भुगतान किया जाना चाहिए; और जो बैंक पूंजी को अनुमोदित स्तरों की तुलना में अत्यधिक सीमाओं तक रखते हैं और बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को अस्थिरता के कगार तक ले जाते हैं, और जब खराब या शून्य जोखिम प्रबंधन के कारण उनके दाँव गलत हो जाते हैं, तब उन्हें जवाबदेह माना जाना चाहिए। सभी उतार-चढ़ाव "ब्लैक स्वान" अर्थात् अनपेक्षित रूप से घटित होनेवाली प्रभावकारी घटनाओं के कारण नहीं होती, जिनमें जोखिम उठाने वाले समर्थन पाने के योग्य माने जाएं।
 8. अंत में, हरबार जब सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ में लगातार वृद्धि दिखाई देती है, तब सामान्यतः ऐसी निराशाजनक बकवास सुनाई देती है कि बाजार की गतिविधियां तर्कहीन हैं। बाजार की तार्किक या तर्कहीन गतिविधियों को अत्यधिक आवृत्ति के कारण पृथक कर पाना केवल कठिन ही नहीं है, बल्कि ऐसे ऐलान इस बात का संकेत भी हैं कि ऐसी बकवास करते हुए सरकारी बाँडों में दाँव लगानेवाले लोगों को बाजार गतिविधियों के चालकों के बारे में कुछ भी अंदाज नहीं है। क्या ऐसा समय बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो जोखिमों की लगाम खींचने का सही समय नहीं है?

ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किंतु ब्याजदर जोखिम का निर्धारण, उसके प्रबंध के लिए प्रोत्साहन तथा उसके कार्यान्वयन के लिए ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक कार्यनीति बनाने के लिए बैंक अभिशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

बैंकों में अवधि जोखिम का समाधान करने वाले उपाय

कितने बैंक अपनी अवधि जोखिम का बेहतर प्रबंध करते हैं?

फिलहाल इस जोखिम का प्रबंध जितनी कुशलता से किया जा रहा है, उसमें अभी बहुत कुछ वांछनीय है। हालांकि सरकारी प्रतिभूति जारीकर्ता द्वारा परिपक्वता संरचना के चयन तथा गौण बांड बाजार में तरलता के कारण अवधि जोखिम प्रबंधन बाधित होता है, किंतु बचाव (हेजिंग) बाजारों की भी सुविधा लेने से इस जोखिम का प्रबंध अधिक फुर्ती से किया जा सकता है। पीएसबी में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का लगभग 70.6 प्रतिशत हिस्सा है। तथापि हेजिंग बाजारों में उनकी सहभागिता सीमित अथवा नगण्य है। गौण बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग में उनका हिस्सा 33 प्रतिशत है, जबकि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) और ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) खण्डों के हेजिंग क्रियाकलापों में उनका हिस्सा क्रमशः 4.61 प्रतिशत & 13.40 प्रतिशत है।

आइए, मैं विस्तार से बताता हूँ। आरबीआई ने 1999 में ओटीसी बाजार में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी की शुरुआत की, यथा ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) तथा वायदा दर करार (एफआरए)। भारतीय बाजारों में वायदा दर करार (आईआरएफ) सबसे पहले 2003 में शुरु किए गए, किंतु 2014 में शुरु किए गए मौजूदा बांड वायदा बाजारों में ही वाजिब कार्यकलाप देखे गए। ब्याज दर उत्पादों में तरलता सामान्यतः कम ही रही है। ब्याज दर वायदा बाजार में खुला ब्याज और दैनिक परिमाण सामान्यतः ₹20-30 बिलियन के बीच होता है, जबकि ओवरनाइट इन्डेक्स स्वैप (ओआईएस) ब्याज दर स्वैप बाजार में यह परिमाण लगभग ₹150 बिलियन है। इसके अलावा, बैंकों का केवल कुछ भाग ही ओटीसी बाजार में सक्रिय है। इस प्रकार दैनिक बांड बाजार के ₹400-500 बिलियन के औसत परिमाण की तुलना में ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार काफी क्षीण हैं। इन बाजारों में चलनिधि को बढ़ाने हेतु इन बैंकों द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजारों वायदा और स्वैप, दोनों में बेहतर सहभागिता आवश्यक है, जो कि बैंकों द्वारा अपने अत्यधिक अवधि जोखिम को कम करके भार दूसरों पर

डालने के लिए आवश्यक है। जैसे-जैसे अधिक बचावकर्ता (हेजर्स) इन बाजारों में पहुँचेंगे, बाजार निर्माताओं के लिए इन कार्यकलापों के लिए अधिक पूंजी आरक्षित करने को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ब्याज दर जोखिम साझा करने का एक सुचक्र शुरु होगा, जो समयानुसार और अधिक जोशीले व्युत्पन्नी बाजार निर्माण करेगा।

दूसरे शब्दों में, बैंकों में कोष संबंधी कार्यों का तत्परता से आधुनिकीकरण करना, बोर्ड द्वारा सावधानी से संवीक्षा किया जाना, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंध व प्रथाओं से युक्त होना तथा विनिर्दिष्ट रूप से ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य वाले हेजिंग लिखतों के प्रयोग में प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

अब मैं इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि बैंकों को प्रतिफल में बड़े परिवर्तनों का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिए।

प्रतिफल में संभाव्य बड़े परिवर्तनों का प्रबंध करने के उपाय

हमारे ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजारों के शुरुआती चरण को देखते हुए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि लिखतों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बाहुल्य के साथ प्रतिफल में बड़े परिवर्तन के प्रति एक्सपोजरों का प्रबंध करें। सभी विकल्प सामने रखे जाने चाहिए। बैंकों में ऐसे विस्तृत जोखिम प्रबंधन में कमी का एक अक्सर उद्धृत कारण यह है कि प्रतिफल में बड़े परिवर्तनों को निष्प्रभावी कर सकने वाले हेजिंग बाजारों में उस आकार या गहनता या तरलता का अभाव है, जो बड़े बैंकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। यह तर्क कुछ हदतक ठीक है, परंतु बड़े बैंकों द्वारा सहभागिता का अभाव ही इन बाजारों को अतरल और छोटा बनाता है।

आरबीआई बाजारों के विकास - ट्रेडिंग, निपटान और रिपोर्टिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उत्पादों की शुरुआत; ईजिंग प्रक्रियाएं आदि के लिए उचित वातावरण निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु बाजार के साथ व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है।

भारत का सरकारी प्रतिभूति बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्विवाद रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हमने सरकारी प्रतिभूतियों, फोरेक्स तथा व्यापार स्वैप में प्रत्याभूत निपटान उपलब्ध कराया है। अधिविक्रय की सुविधा और वायदा और स्वैप बाजारों की उपलब्धता के बावजूद ऐसा लगता है कि अधिकतर बैंकों के निवेश कार्यकलापों में मुख्यतः दो

चरण निहित हैं - खरीदना और अच्छी आशा रखना। किंतु आशा करना कोष-डेस्क की प्रमुख ट्रेडिंग रणनीति नहीं होनी चाहिए।

आरबीआई ने लगभग एक वर्ष पहले मुद्रा बाज़ार फ्यूचर्स के लिए भी अनुमति दे दी है। पहले की निर्धारित विधि से ये निर्देश काफी अलग हैं। विनिमयालयों को उत्पादों को बनाने और शुरू करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हमें अभी तक अनुमोदनार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

इसी प्रकार, कुछ समय पहले ब्याज दर ऑप्शनो को भी अनुमति दी गई है, पर बाज़ार में अभी तक शुरुआत नहीं हुई। वर्षों पहले आरबीआई ने जारी बाज़ार और पंजीकृत ब्याज और प्रधान प्रतिभूतियों की अलग ट्रेडिंग (स्ट्राइप्स) शुरू की थी, किंतु इनमें से कोई भी आकर्षक नहीं बना।

क्या इससे ये समझा जाए कि ब्याज दर उत्पाद किसी भी सहभागी के काम के नहीं हैं? या यह कि बैंकों के वर्चस्व वाले बाज़ार जोखिम प्रबंध विकल्पों का प्रयोग करने के अभ्यस्त नहीं हैं; बल्कि जब प्रासंगिक प्रतिलाभ अपना कुरूप सिर उठाने लगते हैं, तब वे विनियामक धैर्य की आशा रखते हैं?

समापन

सारांश में, बाज़ार की स्वतंत्रता का मतलब केवल विनियामक द्वारा व्यवसाय प्रक्रियाओं को सरल करना, नए उत्पादों की शुरुआत करना और नये बाज़ार निर्मित करना नहीं है। इसके लिए सहभागियों द्वारा लगातार विकासशील बाज़ार स्थितियों और उत्पादों के अनुसार स्वयं को पुनः कुशल करने हेतु पहल करना भी आवश्यक है। बाज़ार का विकास बाज़ार सहभागियों और विनियामकों के बीच एक दुतरफा परस्पर सक्रिय प्रक्रिया है। हम आशा करते हैं कि फिम्डा आगे चल कर बैंकों को संभाल कर अपनी भूमिका निभा सकता है।

अंत में, यह आशादायी है कि फिम्डा ब्याज दर बाज़ारों में अपने सदस्यों के कार्यकलापों के लिए आचार संहिता बना रही है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा हाल ही में वैश्विक विदेशी मुद्रा संहिता को अपनाने के साथ ही जब फिम्डा ये कूट संहिता अपना लेगा, तब बांड, मुद्रा और संबंधित व्युत्पन्नी बाज़ार सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अधीन होगा। मैं आशा करता हूँ, कि ये प्रक्रिया तेज़ी से की जाएगी और फिम्डा सदस्य चालू तिमाही के अंत तक एक सार्वजनिक वेबसाइट पर हस्ताक्षर के द्वारा इस संहिता को अपना लेंगे।

संदर्भ

Viral V. Acharaya, Itamar Drechsler, and Philipp Schnabl (2012), "A tale of two overhangs: the nexus of financial sector and sovereign credit risks," *Financial Stability Review*, Banque de France, April 2012.

Viral V. Acharaya, Itamar Drechsler, and Philipp Schnabl (2015), "A Pyrrhic Victory? Bank bailouts and sovereign credit risk," *Journal of Finance*, 69(6), 2689-2739.

Viral V. Acharaya and Sascha Steffen (2015), "The "greatest" carry trade ever? Understanding Eurozone bank risks," *Journal of Financial Economics*, 115, 215-236.

Bruegel database of sovereign bond holdings developed in Merler and Pisani-Ferry (2012) (updated as of March 2017)- Silvia Merler and Jean Pisani-Ferry, "Who's afraid of sovereign bonds", *Bruegel Policy Contribution* 2012, February 2012 <http://bruegel.org/publications/datasets/sovereign-bond-holdings/>

भारत के आर्थिक सुधार: अपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में चितन*

विजय जोशी

प्रस्तावना

गवर्नर पटेल जी और दोस्तो,

मेरे विचारों में भारतीय रिज़र्व बैंक का विशेष स्थान तब से रहा है जब मैं यहां चौतीस वर्ष पूर्व विशेष परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा था। वह समय मेरे जीवन में बेहद आनंद का समय था। बैंक में उस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए मैंने लोक नीति के बारे में जो कुछ सीखा वह कितनी ही विद्वता भरी पुस्तकों और लेखों से मिली सीख की तुलना में कहीं अधिक था। श्रीमान एल.के. झा के असाधारण रूप से उल्लेखनीय कार्यकाल का मिशन भी लोक नीति ही था। निस्संदेह वह स्वतंत्र भारत के अग्रगण्य लोक सेवकों में से थे और सचमुच बेहतरीन व्यक्ति थे। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य का व्यापक हस्तक्षेप हुआ करता था। किंतु, केंद्रीयकृत योजना तैयार किए जाने और मात्रात्मक नियंत्रणों के बहाने इन हस्तक्षेपों का सामना करने के मामले में वह बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री और बेहद चतुर प्रशासक थे। परिणामस्वरूप, वह आर्थिक सुधारों के घटित होने से पहले ही उनके तरफदार बन गए थे। इसलिए, मैं उनके नाम से संचालित व्याख्यानमाला में भाषण करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने हेतु गवर्नर पटेल जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इनके कार्यभार संभालने के बाद से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुत से गंभीर प्रकार के दबावों का सामना किया है। उनके कुशाग्र-बुद्धि, रचनात्मक एवं कृतसंकल्प नेतृत्व के साथ ही साथ पक्के इरादे के चलते भारत की स्थिरता के स्तंभ के रूप में इस संस्था की छवि में निखार आया है।

आज का मेरा व्याख्यान समय सीमाओं से बंधा ही रहने वाला है। बात ऐसी है कि एक समय राष्ट्रपति डुमैन

अपने आर्थिक सलाहकारों से इतने खिन्न थे और उन्होंने कहा : 'मेरे सभी अर्थशास्त्री कहते हैं कि 'एक तरफ ऐसा है' तो 'दूसरी तरफ वैसा है'। मुझे एक तरफ की पक्की बात करने वाला अर्थशास्त्री चाहिए ! "आज की समय सीमा के मद्देनजर, मैं एक तरफ की ही पक्की बात करने वाला अर्थशास्त्री बनूंगा। बारीकियों एवं विशिष्टताओं के लिए आप मेरी हाल की किताब, 'इंडियाज लॉन्ग रोड - द सर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी' का अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें इस व्याख्यान के विषय को अधिक गहनता और विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है।¹

इस बात में कोई संशय नहीं है कि पिछले तीन दशकों में भारत का कार्यनिष्पादन बहुत बढ़िया रहा है, और मैं देश की सफलता का गान आसानी से घंटा भर तक कर सकता हूँ। हालांकि, मैं आज के व्याख्यान में सफलता के पात्र के आधे भरे होने के स्थान पर आधे खाली रहने पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। भारत में अभी भी इसकी एक बिलियन से अधिक की आबादी का एक चौथाई हिस्सा अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहा है, और इसके दो तिहाई लोग इतने गरीब हैं जिनके पास संतोषप्रद जीवन जीने के लिए बहुत सीमित अवसर उपलब्ध हैं। भारत को अगले दो दशकों में उच्च-आय वाला देश बनने के लिए, समय के दौरान, बहुत तीव्र और समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करना होगा। 'बहुत-तीव्र वृद्धि' से मेरा आशय वर्ष में 8 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि से है। 'समावेशी वृद्धि' कहने का मेरा तात्पर्य ऐसी वृद्धि से है जिसमें सभी लोग व्यापक रूप से साझेदार हों। इस कार्य की दुरुहता को संयत कर देने वाले इस तथ्य पर विचार करते हुए समझा जा सकता है कि दुनिया भर के 200 देशों में से आधे दर्जन से भी कम देशों ने ही दो या अधिक दशकों तक निरंतर बहुत-तीव्र एवं समावेशी वृद्धि हासिल किया है, और उनमें से लगभग सभी तीव्र-वृद्धि की लघु दौड़ में तानाशाही के अधीन थे। क्या लोक-तांत्रिक भारत चीन या दक्षिण कोरिया की तरह कार्य कर सकता है ? यह एक जबर्दस्त सवाल है। हालांकि, वर्तमान संदर्भ यह है कि भारत की वृद्धि दर में वृद्धि के विपरीत मंदी के संकेत दिखाई दिए हैं। कुछ अस्थायी और विशेष कारक इसमें शामिल हैं, किंतु मुद्दा यह भी है कि 'आंशिक सुधार मॉडल', जो 1991 से कार्यशील है, के परिणाम कमी को दर्शाने वाले रहे हैं। भारत में उत्पादकता

* 11 दिसंबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में, पंद्रहवीं एल.के. झा व्याख्यानमाला के तहत प्रोफेसर विजय जोशी, ऐमिरेट फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड का भाषण। इसमें व्यक्त किए गए मतों और विचारों का संबंध सिर्फ लेखक से है।

¹ विजय जोशी (2016), 'इंडियाज लॉन्ग रोड - द सर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी', पेंग्विन रेंडम हाउस, नई दिल्ली, एवं ऑक्सफोर्ड प्रेस, न्यूयॉर्क देखें।

वृद्धि के इंजन को पूरी क्षमता से कार्यशील बनाए रखने के लिए तेजी से मौलिक सुधारों के एक और दौर की तत्काल जरूरत है।

अपेक्षित सुधारों की सूची लंबी है किंतु मेरे विचार से राज्य, बाजार और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन कायम रखने के लिए उनमें एक साझा विचार होना चाहिए। थोड़े उदारीकरण के बाद भी भारत पुराने तरीके के समाजवाद से पूरी तरह उबर नहीं पाया है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के माध्यमों पर राज्य का स्वामित्व होने के प्रिय विचार, और बाजार के परिचालनों में राज्य के स्वच्छाचारी हस्तक्षेप की विशेष प्रवृत्ति शामिल है। हमें आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र में तब्दील होने के लिए अभी काम करना बाकी है। इससे, राज्य के अपने मूलभूत कार्य प्रतिस्पर्धी ढंग से पूर्ण करने के साथ निजी स्वामित्व और बाजार कार्यप्रणाली पर अधिक निर्भरता की ओर गमन करते हुए *साझा* संपन्नता के समाजवादी दबाव, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर जोर दिए जाने के स्वतंत्र-प्रजातांत्रिक विचारों का पता चलता है। इन मूलभूत कार्यों के अंतर्गत समष्टि आर्थिक स्थिरता, चुस्त विनियमन, बाजार की विफलताओं में सुधार, आय का दक्षतापूर्वक पुनर्वितरण, और लोक सेवा की प्रभावी आपूर्ति शामिल हैं।

सामाजिक-लोकतांत्रिक कार्यक्रम आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में क्या संकेत देता है? समय-सीमा को देखते हुए मुझे चयनात्मक होना होगा। मैं उन पांच क्षेत्रों का जिक्र करूंगा, जिनमें लंबी अवधि तक बहुत-तीव्र और समावेशी वृद्धि हासिल करने के लिए मौलिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है: राज्य का स्वामित्व, रोजगार सृजन, गहन राजकोषीय समायोजन, शिक्षा की गुणवत्ता, और सरकार की क्षमता।

I. राज्य का स्वामित्व

भारत में स्वतंत्रता के उपरांत, और विशेषरूप से श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री-काल में प्रमुख रूप से राजनीतिक कारणों से, बहुत सी आर्थिक गतिविधियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा, राज्य के स्वामित्व को बाजार की विफलताओं में सुधार करने, निवेश-योग्य अधिशेष में वृद्धि करने, और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश के उपाय के रूप में न्यायसंगत ठहराया गया। इसके परिणाम स्पष्ट रूप से असंतोषप्रद रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकर्ताओं के लिए विविध प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, और इनको राज्य के बहुल वित्तीय स्रोतों का सहारा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत

नवोन्मेष करने, लागत में कटौती करने और उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद पर प्रतिक्रिया देने को प्रोत्साहित करने या दण्डित करने के प्रावधान नहीं थे। इसके साथ ही, अन्वेषण ऐजेंसियों की ओर से अनुत्पादक खोज-बीन किए जाने की भरमार थी, जिसके कारण प्रबंधक जोखिम विमुख होने लगे और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन बसर करने की चाहत रखने लगे। राष्ट्रीयकृत उद्योगों और सरकार के बीच के संदेहपूर्ण संबंधों के चलते दक्षता से भी समझौता किया गया, जिसके कारण परिचालनगत मुद्दों के साथ ही साथ बोर्ड की नियुक्तियों में भी राजनीतिक हथ-कंडे अपनाए जाने लगे। सरकार के साथ 'समझौता पत्र' के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पर्यवेक्षण से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई है। निजी क्षेत्र को अनुमति दिए जाने से एक सीमा तक इसमें सुधार हुआ है। इसके बाद भी, सफलता पूर्णता से परे रही है। ऐसा होने का कारण यह है कि तार्किक प्रतिस्पर्धा के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी कंपनियों के लिए सरकार समान शर्तें निर्धारित करे, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन अपेक्षानुरूप नहीं होने पर उनका समाप्त हो जाना भी शामिल हो। आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार इस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं है।

इसके परिणाम हाल ही के *सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण*, में देखे जा सकते हैं, जिसे पढ़ना² अवसाद भाव से भर देता है। 2015/16 में 244 केंद्रीय गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से एक तिहाई ने घाटा उठाया; और घाटा उठाने वाले 78 उद्यमों में से आधे से अधिक लगातार तीन वर्षों तक घाटे में रहे। एयर इंडिया और दो दूरसंचार कंपनियों सहित बहुत से उद्यम ऐसे हैं जो हमेशा से घाटे में रहे हैं; और कोल इंडिया जैसी कुछ लाभप्रद कंपनियां भी हैं, जिनका निष्पादन कार्यदक्षता की वजह से नहीं बल्कि एकाधिकारात्मक स्थिति के चलते अच्छा रहा है। समग्र रूप से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लाभप्रदता में पिछले 10 वर्षों के दौरान निरंतर गिरावट आई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अलावा राज्य के स्वामित्व वाले लगभग 1000 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी हैं, जिनमें से दो तिहाई घाटे में चल रहे हैं, जिनमें विद्युत वितरण करने वाली कर्जखोर (जॉबी) कंपनियां भी शामिल हैं। केंद्रीय और राज्य के नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का समग्र घाटा वार्षिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक प्रतिशत के बराबर होता है।

² भारत सरकार का *लोक उद्यम सर्वेक्षण*, 2015/16, खंड I देखें।

अब तक, आनुक्रमिक भारतीय सरकारें 51 प्रतिशत स्वामित्व पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देती रही हैं और निजीकरण (हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः एयर इंडिया की नीति-विषयक बिक्री के बारे में विचार किया जा रहा है) के बारे में सिर्फ बातें ही करती रही हैं। होने वाली अधिकांश बिक्रियों ने तथाकथित 'विनिवेश', अर्थात् राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के लघु हिस्सों की बिक्री का रूप ले लिया है। निजीकरण के विपरीत विनिवेश किए जाने से प्रबंधकीय प्रोत्साहनों एवं स्वायत्ता में परिवर्तन के पूरे फायदे नहीं मिल पाते। सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं छोड़ने की स्थिति में बिक्री मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना भी अवश्यभावी है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुषंगियों की बिक्री निश्चित रूप से अहितकर मूल्यों पर की गई है। यही वह समय है जब सरकार ने निजीकरण के बड़े कार्यक्रम को थामा हुआ है, कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों के संबंध में जो घाटा उठा रहे हैं या मामूली लाभ में कार्य कर रहे हैं। यह विशेषरूप से व्यापार योग्य सामानों के उद्योग पर प्रयोज्य है जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारत्मक मूल्यन किए जाने और उपभोक्ताओं के शोषण को रोका जा सकता है। निजीकरण से न सिर्फ उत्पादकता में उच्चतर वृद्धि होने की संभावना है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनर्जक उद्यमों की बिक्री किए जाने से राज्य के स्वामित्व में भविष्य में होने वाले प्रतिलाभों की तुलना में अधिक राजकोषीय लाभ होने की भी गुंजाइश है। सरकार द्वारा इस लाभ को सामाजिक रूप से लाभप्रद उन गतिविधियों में प्रयोग में लाया जा सकता है जिन्हें निजी क्षेत्र सामान्यतः टालता है, जैसे ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सिंचाई सुविधाओं का विकास।³ जिन गैर-व्यापार योग्य उद्योगों में प्रतिस्पर्धा लाया जाना मुश्किल है, वहां पर निजीकरण का मामला उतना स्पष्ट नहीं है। किंतु, मेरे विचार से भारत के व्यापार योग्य क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देने का मामला निर्णायक अवस्था में है।

क्या बैंकिंग का मामला विशिष्ट है ? मैं ऐसा नहीं मानता। बैंकिंग प्रतिस्पर्धा की सहज अनुगामी है। इसमें कोई 'नैसर्गिक एकाधिकार' नहीं होता है, इसलिए यह राज्य के स्वामित्व का प्राकृतिक विषय नहीं है। बेशक, इस विचार में कुछ सच्चाई है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक

जमाकर्ताओं में भरोसा जगाते हैं, जिसके माध्यम से वित्तीय बचत को प्रोत्साहन मिलता है और खातों से तीव्र-निकासी की संभावना कम होती है। हालांकि, भारत में इस विचार की संभावना को राज्य के स्वामित्व की कमियों द्वारा दृढ़तापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की गुणवत्ता दोगुने दर्जे की है। वैश्विक ऋण संकट के बाद से स्थिति और खराब हुई है : सार्वजनिक क्षेत्रों के दबावपूर्ण अग्रिम अब कुल अग्रिमों के लगभग 16 प्रतिशत के तुल्य हैं, जबकि निजी बैंकों के संदर्भ में यह लगभग 4.5 प्रतिशत है (सारणी 1 देखें)। अन्य वित्तीय और उत्पादकता संकेतकों के बारे में भी यही बात प्रयोज्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कार्य निष्पादन उनके अभिशासन के तरीकों का परिणाम है, जैसा कि बैंक अभिशासन से संबंधित नायक समिति की रिपोर्ट में भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है।⁴ इसके बदले में, खराब अभिशासन की उत्पत्ति सरकार द्वारा बैंक के बोर्डों को कमजोर किए जाने से होती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत इस स्थिति में सुधार होना असंभव साबित हो चुका है।

जैसा कि यहां उपलब्ध श्रोता जानते हैं, बैंकिंग समाधान अध्यादेश से मजबूती प्राप्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निदेशित किया है वे 12 बड़े खातों हेतु कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवालिया के आवेदन प्रस्तुत करें, जो अनर्जक आस्तियों के लगभग 25 प्रतिशत के तुल्य हैं। रिज़र्व बैंक ने बहुत से अन्य खातों की भी पहचान की है जिनका अगर सीमित समय-सीमा के अंदर समाधान नहीं किया जाता है तो उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, भारत सरकार ने पुनर्पूजीकरण के एक बड़े कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बहाल करने की दिशा में काफी कारगर हो सकता है। यह प्रक्रिया बैंकों द्वारा उनके तुलन-पत्र परिमार्जन के दौरान महत्वपूर्ण 'हेयरकट' के रूप में हो सकती है।⁵

यह बहुत प्रशंसनीय बात है। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कमजोर अभिशासन की मूल समस्या पुनर्पूजीकरण के बाद भी रहेगी, और भविष्य में इसके पहले जैसे होने की

³ यू. कपिला, *इंडियन इकोनॉमी सिन्स इन्डिपेंडेंस* (21वां संस्करण), अकेडमिक फाउंडेशन; एवं विजय जोशी (पूर्व उल्लिखित कार्य/पुस्तक में), अध्याय 7 में विजय केलकर (2010), "ऑन स्ट्रैटिजिक फॉर डिसेइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन" देखें।

⁴ भारतीय रिज़र्व बैंक (2014), *बैंक बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : डॉ. पी.जे. नायक)।

⁵ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के विश्लेषण के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला स्मृति व्याख्यानमाला, 17 नवंबर के अंतर्गत वाई.वी. रेड्डी (2017), "सार्वजनिक बैंकिंग का भविष्य" देखें।

बहुत संभावना रहेगी। इसलिए बैंक अभिशासन का मूलभूत सुधार अनिवार्य हो गया है, और इस संदर्भ में निजीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथमतः, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ अव्यवहार्य बैंकों को 'सीमित' बैंक बनाया जाना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ व्यवहार्य बैंकों के अभिशासन में राज्य की नियंत्रणकारी हिस्सेदारी सहित मौलिक सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ व्यवहार्य बैंकों का शीघ्रतापूर्वक निजीकरण किया जाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने और इस प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार लाने के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा के लिए स्पष्टरूप से निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों की आवश्यकता है। प्रथम अनिवार्यता बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को निरस्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कंपनी अधिनियम के अधीन लाना होगा। ऐसा किए जाने से सरकार को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी हद तक स्वामित्व घटाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। निजीकरण करने, अर्थात् नियंत्रण सौंपने के लिए, सरकार को व्यावहारिक रूप में अपने हिस्से को 25 प्रतिशत या उससे भी कम स्तर पर ले जाना होगा। यद्यपि, संक्षिप्त संक्रमण अवधि के लिए सरकार अपने तथाकथित 'सोने के अंडे/गोल्डन शेयर' अपने पास रख सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि निजी बैंक भी लापरवाह और दोषी हो सकते हैं, इसलिए सरकारी और निजी -दोनों तरह के बैंकों का कड़ाई से विनियमन किए जाने की जरूरत होगी। ऐसा करने में, भारत को सामान्य रूप से सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करना होगा।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अलग-अलग रखने के पूर्व के सभी प्रयास निरर्थक रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली की बेहद दबावपूर्ण वर्तमान परिस्थितियों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खस्ता-हाल होने के प्रति जनता सचेत हो गई है। यह स्थिति आमूलचूल परिवर्तन लाने का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करा रही है। वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए।

II. रोजगार सृजन

बहुत से टीकाकार अब 'रोजगार' को देश के समक्ष मुख्य दीर्घावधिक चुनौती मानते हैं। मूल समस्या 'अच्छे रोजगारों' की कमी की है, जिनकी श्रम उत्पादकता अधिक हो और इससे अच्छी आय प्राप्त हो। इस तरह के रोजगार व्यापकरूप से संगठित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में फंसे हुए हैं। मैं अब इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ कि *कम-कुशल* श्रमिकों

के लिए संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि कैसे की जाए। मैं *कम-कुशल* श्रमिकों पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि भारत एक बड़ी छलांग लगाकर *उच्च-कुशल* अर्थव्यवस्था में तब्दील नहीं हो सकता है। अधिकांश श्रमिकों के लिए शीघ्रतापूर्वक उच्च-प्रौद्योगिकी वाले रोजगार की चाहत करना चांद मांगने जैसा होगा। आशावादी मान्यताओं के साथ भी, भारत की आधी श्रम शक्ति आज से शुरू करके 10 वर्षों के बाद भी सिर्फ उच्चतर माध्यमिक या उससे भी कम स्तर तक ही शिक्षित होगी; और श्रम शक्ति का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ प्राथमिक शिक्षा या उससे कम स्तर तक ही शिक्षित होगी।⁶ फंतासी की दुनिया में नहीं बल्कि वास्तविकता के धरातल में देखा जाए तो, असंगठित क्षेत्र में पहले से विद्यमान या जनांककीय वृद्धि के कारण श्रम शक्ति में शामिल होने वाले अल्प शिक्षित और कम कुशल लोगों के लिए करोड़ों की संख्या में उत्पादक रोजगार सृजन के लिए भारत मजबूर है। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत की पूंजी एवं कुशलता की प्रधानता वाली गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हो सकती थी और इसे जारी रहना चाहिए। ये गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, इनमें से बहुत सी गतिविधियां प्रतिस्पर्धी हैं भी। किंतु, भारत में समावेशी प्रकार की *अतिरिक्त* वृद्धि की तत्काल जरूरत है, जो संगठित क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम-कुशलता वाले रोजगार में विस्तार के माध्यम से ही संभव हो सकती है। प्रश्न है कि श्रम प्रधान उत्पादों के लिए मांग कहां से आएगी? इसका उत्तर है कि इस मांग का कुछ हिस्सा भारत के विशाल आंतरिक बाजार से आएगा और कुछ हिस्सा वैश्विक बाजार, जो बहुत विशाल है, से भी आएगा। रोजगार वृद्धि में श्रम-प्रधान वस्तुओं के निर्यात की भूमिका प्रमुख होने वाली है। भारत में स्वचालित ढंग से यह अवस्था समाप्त होने के लिए अभी एक या डेढ़ दशक का समय शेष है। रोजगार की समस्या के समाधान के लिए किसी और जादुई समाधान का दावा करना व्यर्थ है।

रोजगार की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तीव्र वृद्धि होना अपने आप में समाधान का हिस्सा होती है। मजदूरी में छूट उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह स्वतः स्पष्ट है कि हमें आधारभूत संरचना एवं ऋण बाधाओं, भूमि-अधिग्रहण की बाधाओं, कौशल की बाधाओं, तथा 'कारोबार करने की सहूलियत' में नौकरशाही की अनेक और दुष्कर अड़चनों को दूर करना होगा, जो फर्मों की वृद्धि को रोकती हैं, विशेषरूप से उन छोटी फर्मों की वृद्धि को जो संख्या की दृष्टि से उद्योग और सेवाओं में प्रभुत्व रखती हैं। निर्यात प्रोत्साहन के गंभीर कार्यक्रम की भी जरूरत है, ऐसा

⁶ विश्व बैंक (2011), *दक्षिण एशिया में अधिक तथा बेहतर रोजगार* देखें।

विशेषरूप से भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला में शामिल होने के लिए आवश्यक है। कारोबारी सुविधा, व्यापार उदारीकरण (एक पक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के माध्यम से), एवं वास्तविक तटीय आर्थिक जोनों, जहां पर फर्मों को मुक्त व्यापार परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, का भी सक्रियता पूर्वक अनुसरण करना होगा। हालांकि, इनमें से किसी भी नीति के महत्व को कम करके बताए बिना, मैं आज रोजगार प्रधान वृद्धि को सहारा प्रदान करने के लिए नीतिगत व्यवस्था के दो अन्य पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।

पहला पहलू है श्रम बाजार सुधार⁷। संगठित क्षेत्र में कम-कुशलता वाले श्रमिकों की मांग कमजोर होने के पीछे प्रमुख कारण भारत के श्रम कानून और उनका विनियमन है, जो संसार के सबसे कठोर प्रकार के हैं। उनका अधिनियमन वर्षों पहले सदेच्छा पूर्वक किया गया था, किंतु वे पूरी तरह से रोजगार-विनाशक और श्रम-विरोधी साबित हुए हैं। साधारण रूप से, वे सिर्फ संगठित क्षेत्र के वर्तमान श्रमिकों, जो अल्प संख्यक हैं, के हितों का संरक्षण करते हैं जबकि बहुसंख्यक श्रमिकों के हितों का उनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सौ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली किसी भी फर्म के लिए सरकार की पूर्वानुमति के बगैर रोजगार में कटौती करना वैधानिक ढंग से असंभव है। यह अधिनियम किसी उद्यम के भीतर भी श्रमिकों के पुनर्नियोजन को भी बहुत कठिन बना देता है, जो उतनी ही खराब स्थिति को दर्शाता है। दूसरा वैधानिक रास्ता है कि ठेका श्रमिक रखे जाएं। किंतु ठेका श्रम रोजगार की घटिया गुणवत्ता के रूप में परिणत होती है। इसके अलावा, ठेका श्रम अधिनियम के तहत 'मुख्य/कोर' गतिविधियों के लिए ठेका श्रमिक नियुक्त करने की मनाही है; और 'मुख्य/कोर' गतिविधियों की परिभाषा को प्रशासनिक विवेक पर छोड़ दिया गया है। उनके गतिरोध के रूप में अड़चनों और निहित अनिश्चितताओं के अंतर्गत इन बहुत सी बंदिशों के कारण प्रत्यक्ष रूप से श्रम की प्रभावी लागत बढ़ जाती है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दी जाती है। परिणामस्वरूप, घरेलू और विदेशी कंपनियों को श्रम प्रयोग को न्यूनतम रखने और श्रम-प्रधान उद्योग में निवेश को टालने के लिए सभी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है (इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उन उद्योगों को प्राप्त नहीं होता है जो कम-कुशल श्रम का प्रयोग करते हैं)। श्रम-प्रधान उद्योगों द्वारा निर्मित बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात हेतु बड़ी संख्या में श्रमिकों

को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है। चीन में इस तरह की कंपनियों के बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं, और बांग्लादेश तथा वियतनाम में भी इनका चलन बढ़ रहा है किंतु भारत में इनकी उपस्थिति बहुत कम है। श्रम कानूनों को पूर्णतः संशोधित किए बिना इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परंतु, स्पष्ट तौर पर बदले में लाभों के बगैर मजबूत सुरक्षा वाले रोजगार को छोड़ने के लिए ट्रेड यूनियन तैयार नहीं होंगी। इसलिए, श्रम-बाजार में किए जाने वाले सुधार तभी संभव हो सकेंगे जब रोजगार समापन पर दिए जाने वाले लाभों को अधिक उदार बनाने, समग्र रूप से बेहतर सुरक्षा प्रबंध, और रोजगार की तलाश एवं प्रशिक्षण की अधिक प्रभावी योजनाओं की शर्तों को समझौता के एक भाग के तौर पर ट्रेड यूनियनों से समझौता-वार्ता में शामिल किया गया हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो *पक्के रोजगार* में कमी लाने के बदले आय सुरक्षा में दृढ़ता की बात की जाए। इस प्रकार के समझौता-वार्ता में यूनियन और राज्य सरकारों, दोनों द्वारा उच्च-स्तरीय नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी।

श्रम-प्रधान वृद्धि से संबंधित नीतिगत पैकेज का दूसरा पहलू, जिस पर मैं आज अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, विनिमय दर प्रबंधन है, जो भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारत की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) का मध्यावधिक उद्भव बहुत विचित्र है (सारणी 2 और चार्ट 1 एवं 2 देखें)। 1993/94 से 2004/05 तक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर +1-5 प्रतिशत के बहुत संकीर्ण दायरे में रही, जो लगभग अपरिवर्तित रुझान को दर्शाता है। हालांकि, 2004/05 से 2017/18 तक इसमें महत्वपूर्ण वास्तविक वृद्धि हुई है। सचमुच, 2008/09 के वैश्विक संकट के नौ वर्षों के बाद वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि दर का रुझान लगभग 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या निर्यात, विशेषरूप से श्रम-प्रधान निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने की जरूरत को देखते हुए, मजबूती से बढ़ती हुई वास्तविक प्रभावी विनिमय दर का होना बुद्धिमानी है? निर्यात में तीव्र वृद्धि के बगैर वहनीय तीव्र वृद्धि को हासिल करने वाले किसी देश के बारे में सोच पाना काफी कठिन है। किंतु, भारत की निर्यात वृद्धि धीमी गति से होती रही है। निस्संदेह, वैश्विक व्यापार की धीमी वृद्धि ने वर्तमान दशक में अन्य देशों के समान भारत के निर्यात को भी नुकसान पहुंचाया है। किंतु, इस अवधि के दौरान वैश्विक निर्यात में भारत के हिस्से में, जिसे वैश्विक व्यापार में वृद्धि से संबद्ध किए जाने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः अविचल रही है। क्या वास्तविक विनिमय दर आंशिक रूप से इसकी जिम्मेदार है।

⁷ जगदीश भगवती एवं अरविंद पनगरिया, *व्हाई थोथ मैटर्स*, पब्लिक अफेयर्स, अध्याय 8; एवं विजय जोशी (पूर्व उल्लिखित कार्य/पुस्तक में), अध्याय 5 देखें।

वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि के रुझान का एक संभावित औचित्य यह है कि इससे अन्य उन्नत देशों की तुलना में भारत की तीव्र उत्पादकता वृद्धि का सामान्य रूप से पता चलता है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत में मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन (पॉलिसी ट्रेक्शन) लागू किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक सुपरिचित कथन है कि - बेला बलास्सा एवं पॉल सैम्युअलसन के मत्थे मढ़ दो, अर्थात् स्वदेश में विदेशों की तुलना में गैर-व्यापारिक वस्तुओं की अपेक्षा व्यापारिक वस्तुओं की उत्पादकता वृद्धि अधिक होने की संभावना है तो वहाँ पर मापित वास्तविक विनिमय दर की वृद्धि सामान्यवस्था में होगी (पारंपरिक तरीके से परिभाषित वास्तविक विनिमय दर को 'मापित वास्तविक विनिमय दर' कहते हैं, जबकि सांकेतिक विनिमय दर सूचकांक को कम करने के लिए समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है)। इस कथन का अर्थ यह है कि विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, मापित वास्तविक विनिमय दर की स्वदेश में हुई वृद्धि से उसकी व्यापार-योग्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में आई कमी को सामान्यतः, और विशेषरूप से उसके निर्यात में कमी का पता नहीं चलता है। किंतु, बलास्सा-सैम्युअलसन परिकल्पना के अनुभवजन्य प्रयासों के परिणाम अस्पष्ट और मिलीजुली प्रकृति के रहे हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि - गैर-व्यापारिक उद्योगों की तुलना में व्यापारिक उद्योगों की उत्पादकता वृद्धि तीव्र गति से होती है, की मान्यता सामान्य रूप से सही न हो, अथवा यह मान्यता किसी अवधि के लिए सही हो और किसी अन्य अवधि के लिए सही न हो। आखिरकार, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं, जिनका अधिकांश हिस्सा गैर-व्यापारिक क्षेत्र में है, में बहुत तीव्र तकनीकी प्रगति हुई है। इसके अलावा, इसका कोई कारण नज़र नहीं आता कि श्रम-अधिशेष वाले देशों में बलास्सा-सैम्युअलसन वास्तविक वृद्धि होने की संभावना क्यों है अथवा वे अपेक्षित क्यों हैं; और इसके अनुरूप हमें ज्ञात है कि पूर्वी-एशिया के बहुत से तीव्र गति से वृद्धिशील देशों में वास्तविक विनिमय दर

⁸ यदि बलास्सा-सैम्युअलसन परिकल्पना को अनुभव-जन्य मान्यता होती, तो तेजी से विकासशील पूर्वी एशियाई देशों में अमेरिकी डॉलर के प्रति द्विपक्षीय वास्तविक विनिमय दर वृद्धि की प्रवृत्ति बरकरार रहती। उनमें से अधिकांश (1960 से तीन दशकों तक जापान इसका अपवाद रहा है) के संबंध में ऐसा नहीं हुआ है। इससे यह पता चलता है कि इन देशों ने समय के दौरान व्यापार योग्य वस्तुओं के मामले में कम से कम अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी या शायद उसमें सुधार किया। संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए मैं डॉ. कामाख्या त्रिवेदी का आभारी हूँ।

वृद्धि बने रहने की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।⁸ इसलिए यह संदेहास्पद है कि भारत की परिस्थितियों में विनिमय दर नीति के मार्गदर्शन हेतु बलास्सा-सैम्युअलसन परिकल्पना विश्वसनीय है या नहीं (इसका प्रभाव यह है कि भारत की मापित वास्तविक विनिमय दर वृद्धि से इसके निर्यात सहित व्यापारिक वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट का सही संकेत मिलता है।) मेरा सुझाव है कि भारत की वर्तमान स्थिति को समझने से संबंधित सिद्धांत बलास्सा-सैम्युअलसन परिकल्पना नहीं है बल्कि इसे 'डच डिज़ीज' परिकल्पना सही बयां करती है। भारत के तथाकथित डच डिज़ीज के शिकार होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विनिर्माण तथा सेवाओं, विशेषरूप से व्यापारिक तथा श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवाओं, के लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए पूंजीगत अंतर्वाह के द्वारा विनिमय दर का मसला उठ रहा है।

यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वास्तविक विनिमय दर वृद्धि रोकना सच में एक छलावा हो सकता है।⁹ नीतिगत लिखतें वास्तविक विनिमय दरें नहीं बल्कि सांकेतिक विनिमय दरें हैं। घरेलू मुद्रास्फीति में तेजी होने पर सांकेतिक गिरावट को रोकने का प्रलोभन होता है, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति नियंत्रण के क्रम में वास्तविक वृद्धि होने दी जाती है। मुझे आशंका है कि इसी विचार के चलते 2009 एवं 2010 की उच्च मुद्रास्फीति के प्रति विनिमय दर की नीतिगत प्रतिक्रिया निर्धारित की गई थी। इसका प्रतिकूल पक्ष यह था कि वास्तविक वृद्धि से उसके बाद चालू खाता घाटा बढ़कर 2011 और 2012 में सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत के खतरनाक स्तर से भी अधिक हो गया था, जिसके विभिन्न हानिकारक असर देखे गए। मैं, इससे यह सीख लेना चाहूँगा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण का दायित्व सामान्यतः मौद्रिक और राजकोषीय नीति को सौंपा जाना चाहिए, न कि विनिमय दर नीति को। इस प्रकार से विनिमय दर को बाहरी लक्ष्य हासिल किए जाने हेतु स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बेशक, मौद्रिक नीति और विनिमय दर नीति को पृथक किया जाना मुद्रास्फीति नियंत्रण के विशुद्ध सिद्धांत से अलग बात है। किंतु, इसे वास्तविक हस्तक्षेप एवं लक्षित पूंजीगत नियंत्रणों के प्रयोग से संभव बनाया गया है। ये नीतियां विशेष रूप से उस स्थिति में उपयागी होती हैं जब कि हमारे समक्ष अस्थिर विदेशी पूंजी के बड़े अंतर्वाह जैसा कोई प्रलोभन होने की वजह से सांकेतिक और वास्तविक

⁹ भारत की विनिमय दरों के विश्लेषण के लिए विजय जोशी (2016), (पूर्व उल्लिखित कार्य/पुस्तक में), अध्याय 8 देखें।

विनिमय दर को बढ़ने दिया जाता है। इन बड़े अंतर्वाहों को अस्थायी समझे जाने की सीमा तक, वास्तविक वृद्धि न मानने के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है। निश्चित रूप से, यहां दुविधाएं हैं। सटीक हस्तक्षेप के लिए उचित प्रकार की लिखतें (उपकरण) होना भी आवश्यक है। ये भारत में मौजूद अवश्य हैं लेकिन इन्हें मजबूत किए जाने की जरूरत है जैसा कि मौद्रिक नीति ढांचे पर पटेल समिति की रिपोर्ट में भी सही प्रकार से तर्क दिया गया है।¹⁰ सटीक हस्तक्षेप करने की एक सर्वज्ञात सीमा यह भी है कि इसकी कुछ लागत हो सकती है जो कि आर्थिक और अर्द्ध-राजकोषीय भी हो सकती है। इसलिए उचित यह है कि सटीक हस्तक्षेपों के साथ ही लक्षित पूंजी-अंतर्वाह नियंत्रणों और/या मुद्रा आधारित विवेकपूर्ण नियंत्रणों को संयुक्त किया जाए। इनमें से कुछेक विधियों को एक बार हटाने के बाद पुनः लागू कर पाना कुछ मुश्किल होता है परंतु कुछ अन्य ऐसे होते हैं जैसे कि कर, विथहोल्डिंग कर और कुछ निश्चित प्रकार के गैर-एफडीआई अंतर्वाहों पर आरक्षित अपेक्षाओं को लागू करना, जिन्हें परिस्थिति के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।¹¹ इन विविध उपायों की लागत रोजगार, निर्यातों और संवृद्धि के संबंध में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले फायदों की तुलना में काफी कम होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह है विनिमय दर नीति। जैसे कि मौद्रिक नीति दीर्घावधि और विविध अंतरालों के साथ परिचालित होती है वैसे ही प्रतिस्पर्धी विनिमय दर नीति भी मौजूद होनी चाहिए ताकि एक संतुलित समय-सीमा के भीतर इसके प्रभाव को मापा जा सके।

विनिमय दर नीति पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से किसी बाहरी व्यक्ति को परहेज रखना चाहिए जब तक

¹⁰ मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने से संबंधित रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. ऊर्जित पटेल), देखें भारतीय रिज़र्व बैंक (2014)।

¹¹ जॉनाथन ऑस्ट्रे एवं अन्य देखें (2011), 'मैनेजिंग कैपिटल इनफ्लो: व्हाट टूल्स टु यूज़?' आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट 11/06 और आतिश घोष एवं महावश कुरैशी (2016), 'व्हाट इज इन नेम? दैट व्हिच वी कॉल कैपिटल कंट्रोल?' आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/16/25।

¹² 'विनिमय दर हस्तक्षेप' के लिए यू.एस. ट्रेजरी की 'निगरानी सूची' में रखे जाने से बचना संभावित 'अनिवार्यता' है। मैं नहीं समझता के सूची में रख दिया जाना कहीं इतना अधिक महत्वपूर्ण है। लगातार जीडीपी के तीन प्रतिशत के चालू खाता शेष अधिशेष बनाए रखने से भारत अभी कोसों दूर है। जो कि एक मानदंड रखा गया है 'हस्तक्षेपकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए। किसी भी मामले में तीव्रतर निर्यात वृद्धि हासिल करने लिए चालू खाता अधिशेष उत्पादित करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए अपितु रोजगार-समन्वित वृद्धि होना चाहिए और निष्पादन के आधार पर आयातों में और छूट प्रदान करनी चाहिए। आयातों में छूट के साथ ही जीडीपी की उच्चतर वृद्धि निर्यात को बढ़ावा देगी। इस बात का कोई कारण नहीं है कि निर्यात और आयात में वृद्धि का परिणाम चालू खाता अधिशेष होना चाहिए।

कि उसे सभी नीतिगत बाध्यताओं की जानकारी न हो और निश्चित ही किसी सार्वजनिक भाषण में मैं किसी समुचित आंकिक कीमत या विनिमय दर पथ के संबंध में कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ।¹² फिर भी मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि भारत में किस प्रकार महत्वपूर्ण वास्तविक विनिमय दर को बढ़ते जाने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि ए) देश के रोजगार और वृद्धि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्यातों को मुख्य स्थान प्रदान किया गया है और बी) इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विशाल चालू खाता घाटा जोखिम को बढ़ा सकता है और आर्थिक बहाली में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। मेरा समग्र दृष्टिकोण यह है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण अंतर्वाहों और अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा (हॉट मनी) के प्रति झुकाव में कुछ कमी करनी चाहिए और हाल के वर्षों की तुलना में वास्तविक विनिमय दर को स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए।

यह दोहराए जाने की जरूरत है कि निर्यात प्रोन्नयन और रोजगार निर्माण लिए आपस में अन्योन्यश्रित नीतियों के एक समग्र पैकेज की आवश्यकता होगी और जिसमें मुद्रा विनिमय नीति किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद भी मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इस प्रकार के पैकेज के सहायक घटक के रूप में भी प्रतिस्पर्धी वास्तविक विनिमय दर की आवश्यकता होगी। अब मैं अपने तीन शेष मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा।

III. गहन राजकोषीय समायोजन

भारत ने वस्तुओं और सेवाओं हेतु बाजारों में घरेलू और बाह्य स्तरों पर काफी छूट प्रदान की है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना भी एक सकारात्मक कदम है। यद्यपि विभिन्न कर दरों और जीएसटी में छूटों के संबंध में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है फिर भी एक प्रभावी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाने के संबंध में एक पहल की गई है जिससे अंततः वास्तविक रूप में भारत एक सामान्य बाजार बन सकेगा।¹³

फिर भी, वस्तुओं और सेवाओं हेतु बाजारों में मौजूद बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। शायद सबसे कुख्यात समस्या मूल्य नियंत्रणों से संबंधित है। खाद्य सामग्रियों, ईंधन जैसे कि केरोसीन और कुकिंग गैस

¹³ डिजाइन संबंधी समस्याओं के कारण तो जीएसटी को लागू करना प्रभावित हुआ ही इसके अतिरिक्त विभिन्न करों और छूटों ने भी अपना असर डाला: देखें इंदिरा राजारमन (2017), 'फरदर रिफार्म आर नौडेड फॉर जीएसटी टु सक्सीड', मिंट 03 नवंबर।

और अन्य कई महत्वपूर्ण इनपुट जैसे कि खाद, बिजली, पानी, और रेल किराया आदि पर अभी भी मूल्य नियंत्रण मौजूद हैं। इन नियंत्रणों के कई बुरे प्रभाव होते हैं। सबसे पहले तो वे संसाधन आबंटन को प्रभावित करते हैं। चूंकि प्रभारित मूल्य उत्पादन लागत से कम होते हैं इसलिए इनकी आपूर्ति में निवेश हतोत्साहित होता है और निष्फल उपभोग को बढ़ावा मिलता है। दूसरे वे राजकोषीय बोझ का निर्माण करते हैं क्योंकि इसके लिए राज-सहायता (सब्सिडी) अपेक्षित होती है, जो कि स्पष्ट रूप से बजट से मिलती है या अप्रत्यक्ष रूप से हानियां या उत्पादों के लिए घटे हुए लाभ के रूप में होती है। तीसरे यह काफी बड़े स्तर पर प्रतिगामी होती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रति यूनिट उपभोग पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अधिक लाभ उन्हें प्रदान करती है जो ज्यादा उपभोग करते हैं अर्थात् सम्पन्नों को। सब्सिडी में कई स्थानों पर लीकेज भी होता है और राशि जो कि गरीबों के लिए उद्देश्यित होती है उसका फायदा बिचौलियों द्वारा उठाया जाता है। सब्सिडी को हटाने और लागत-प्रदर्शित करने वाली कीमतों को प्रभारित करने से निवेश और वृद्धि में बढ़ोतरी होगी जबकि वितरण संबंधी चिंताओं का सामना सीधे नकद अंतरण द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सकता है जो क्रमिक रूप से अब व्यवहार्य हो रहा है। सब्सिडी को समाप्त करने से निर्मित होने वाली राजकोषीय बचत सब्सिडी के गरीब लाभार्थियों तक पर्याप्त रूप में लाभ पहुंचाने से कहीं अधिक होगी।

केन्द्र और राज्य की 'गुणवत्ता-विहीन' सब्सिडी का मात्रात्मक आकार काफी बड़ा है। हाल में सावधानी-पूर्वक किया गया एक अध्ययन इस प्रकार की कुल सब्सिडी के 2011-12 में जीडीपी के 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाता है।¹⁴ मेरी गणना यह दर्शाती है कि हाल में किए गए परिवर्तनों ने इस कुल को कम करके जीडीपी के लगभग 6 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। तथापि, यदि कुछ अन्य वांछित उपायों को भी शामिल कर दिया जाए जैसे कि निष्क्रिय कर छूटों को समाप्त करना, गैर-निष्पादन करने वाले राज्य उद्यमों की बिक्री कर देना, एक सीमा से अधिक कृषि योग्य आय को कर के दायरे में लाना और खराब तरीके से बनाए और क्रियान्वित किए जाने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को समाप्त करना (प्रभावी को जारी रखते हुए) तो राजकोषीय गुंजाइश जीडीपी के 6 प्रतिशत से कहीं अधिक होगी, जो हां, यह जीडीपी के 10 प्रतिशत जितनी बड़ी भी हो सकती है। इस प्रकार, सैद्धांतिक रूप में पर्याप्त

राजकोषीय गुंजाइश बन सकती है जिसका उपयोग न केवल गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को हटाने परंतु: i) आधी आबादी या पूरी आबादी के लिए मूल आय में सहायता का वित्त पोषण करने (ताकि गरीबों को चिह्नित करने की समस्या से बचा जा सके); ii) सार्वजनिक निवेश में बड़ी वृद्धि करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य देख-भाल जैसे वांछित सामाजिक खर्चों; और iii) राजकोषीय घाटे को कम करने में इसके योगदान के प्रति किया जा सकता है।¹⁵ संसाधनों के आवंटन में सुधार के साथ ही साथ मूल्य नियंत्रणों को हटाने से समग्र रूप में योजना, विविध प्रकार से समन्वित विकास को प्रोत्साहित करेगी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि 'गहन राजकोषीय समायोजन' आमूल-चूल कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अतीव सामंजस्य की आवश्यकता होगी। इसे कई राजनीतिक बाधाओं का भी सामना करना होगा। परंतु इसका पुरस्कार अति विशाल होगा क्योंकि इस प्रकार के कई रचनात्मक कार्य हैं जहां कि इस राजकोषीय बचत का उपयोग किया जा सकता है।

IV. प्राथमिक शिक्षा

प्रत्येक देश जिसने तीव्र दीर्घावधि दौड़ लगाई है उसने अपनी मानव-पूंजी में क्रमिक रूप से सुधार किया है। इस उद्देश्य के लिए सभी स्तरों पर शिक्षण और प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया जाना वांछित है परंतु प्राथमिक शिक्षा, जो कि शिक्षा प्रणाली का आधार होती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से भारत ने यद्यपि स्कूलों में नामांकन में काफी उल्लेखनीय प्रगति की है फिर भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता घटिया है और गिरती जा रही है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में 2016 की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा V (सामान्य आयु 11 वर्ष) में आधे से कम बच्चे कक्षा II (सामान्य आयु 7 वर्ष) की एक साधारण कहानी बर्नाकुलर में पढ़ पाते हैं; और कक्षा V के केवल एक चौथाई बच्चे एक अंक की संख्या से 3 अंक की किसी संख्या को विभाजित कर पाते हैं।¹⁶

यह समस्या पढ़ाने के तरीके से उत्पन्न होती है। प्रणाली का अधिकतम जोर इस बात पर रहता है कि प्रत्येक वर्ष 'पाठ्यक्रम को समाप्त' कर लिया जाए, चाहे बच्चे

¹⁴ देखें सुदीप्तो मुंडले और शतादु सिकंदर, (2017), 'बजट सब्सिडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 14 इंडियन स्टेट्स', आइडियाज फॉर इंडिया, 14 मार्च।

¹⁵ देखें विजय जोशी (2016), पूर्व उल्लिखित अध्याय 6 और 10; और विजय जोशी (2017), 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट फॉर इंडिया: ए प्रोजेक्ट' इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, खंड 11 (2)। मेरी गणना यह दर्शाती है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट सेट एक स्तर का निर्माण करेगा जो तैडुलकर की गरीबी रेखा और गरीब की मौजूदा औसत आय के बीच के अंतर के बराबर होगा और जो जीडीपी का लगभग 3.5 प्रतिशत बैठेगा।

¹⁶ देखें, प्रथम एजूकेशनल फाउंडेशन (2017), एन्युल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (रूरल), 2016।

वास्तव में उसे समझ पाएं अथवा नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि वितरण के शीर्ष पर स्थित बच्चों की एक छोटी संख्या ही उससे ताल-मेल बैठा पाती है और शेष सभी पिछड़ जाते हैं और क्रमिक रूप से उनकी रुचि घटती जाती है। दूसरी मुख्य समस्या अध्यापकों की ओर से प्रतिबद्धता में कमी है। अध्यापकों की गैर-हाजिरी भरपूर है। सरकारी अध्यापकों का वेतन अच्छा है और वे अत्यधिक यूनियनबाजी करते हैं, बड़ी चूक होने पर भी किसी अध्यापक को बर्खास्त कर पाना असंभव है। निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन तीव्र हैं और अध्यापक अधिक प्रयास करते हैं। निजी स्कूलों में सीखने के अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है कि लोग अपने विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं और निजी स्कूलों द्वारा शुल्क लेने के बावजूद वे उनके लिए सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यदि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से सस्ते हैं क्योंकि वे अध्यापकों को सरकारी स्कूलों के समकक्ष अध्यापकों की तुलना में कहीं कम वेतन देते हैं।

दुर्भाग्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2010) में भी गलत शिक्षा नीति को ही ध्यान में रखते हुए इनपुट पर जोर दिया गया है न कि सीखने पर।¹⁷ विशेष रूप से यह अध्यापक के उत्तरदायित्वों के गंभीर मुद्दे पर टाल-मटोल करता है। एक विवादपूर्ण भावी दिशा यह हो सकती है कि वाउचर प्रणाली को लागू किया जाए जिसमें माता-पिता को शिक्षा वाउचर प्रदान किए जाएंगे इस विकल्प के साथ कि वे अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल का चुनाव करें या फिर निजी स्कूल का, जिसमें सरकार की भूमिका केवल समग्र विनियमन तक सीमित हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सभी स्कूलों को प्रति-विद्यार्थी अनुदान मिलेगा न कि एकमुश्त अनुदान और यदि सरकारी स्कूल बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बंद होना पड़ेगा। मेरा झुकाव इस दृष्टिकोण के प्रति है आदर्शवादिता को लेकर नहीं अपितु व्यावहारिक आधार पर। आज हम जहां हैं वहां से प्रारंभ करें तो यह देखना कठिन है कि केवल आंतरिक सुधारों के आधार पर सरकारी स्कूलों में सुधार लाया जा सकता है जब तक कि प्रतिस्पर्धा और बंदी की कारगर धमकी न दी जाए। चाहें जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि जब तक भारत अपनी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाता है इसके आर्थिक विकास को गंभीर झटका लगने

वाला है और यह सुधार चाहें वाउचर व्यवस्था से प्रतिस्पर्धी प्रणाली के द्वारा लाया जाए अथवा मौजूदा ढांचे के भीतर आमूल-चूल परिवर्तन कर लाया जाए।

V. सरकार की क्षमता

सरकार और बाजार के बीच संबंधों को दुरुस्त करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सरकार में सुधार करना आवश्यक है। साधारण रूप में आर्थिक सुधार के घटक को 'सरकार द्वारा वापस लेने' की सोच मानना न केवल अपूर्ण है अपितु भ्रामक भी है। सरकार कितना छोड़ सकती है या कार्य को किस सीमा तक निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है इसकी कुछ सीमाएं हैं। कुछ ऐसी मूल्यपरक वस्तुएं हैं जिन्हें केवल सरकार द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है।

बढ़ती हुई मांग के सापेक्ष भारत सरकार की क्षमता में गिरावट आ रही है क्योंकि सुविधाहीन समूहों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं और अर्थव्यवस्था जटिल तथा तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत में सरकार के भली प्रकार से कार्य न कर पाने के कारण हो सकते हैं: अपने मुख्य कार्यों को संपादित कर पाने संबंधी क्षमता में कमी होना और सरकार-व्यापार एवं सरकार-नागरिक संबंधों में भ्रष्टाचार का बोल-बाला होना। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिस पर विमर्श के लिए मेरे पास समय नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भ्रष्टाचार के समाधान का एक मुख्य घटक चुनावों के वित्तपोषण संबंधी सुधारों को लागू करना है। इसके बजाय, मैं संक्षिप्त रूप में, सरकारी क्षमता संबंधी कुछ अन्य मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श करना चाहूंगा।¹⁸

मात्रात्मक पहलू की बात करें तो इस बात की कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि यद्यपि सरकार में अत्यधिक नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) मौजूद है, जैसा कि व्यापार सहजता में आने वाली अड़चनों से मालूम पड़ता है, फिर भी यहां स्टाफ की कमी है। 25 वर्ष पूर्व की तुलना में सरकारी क्षेत्र में रोजगार अब काफी कम है जबकि अर्थव्यवस्था में काफी विस्तार हुआ है। यहां तक कि पिछले दो दशकों में प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस बल में इसके 25 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। जी20 देशों के बीच भारत में प्रति व्यक्ति न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे कम है। न्यायपालिका में रिक्त पदों

¹⁷ देखें कार्तिक मुरलीधरन (2013), 'प्रायोरिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी इन इंडियाज़ 12थ फाइव इयर प्लॉन'। इंडिया पॉलिसी फोरम 2012/13 खंड 9; जीन ड्रेज़ एंड अमर्त्य सेन (2013), 'एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कन्ट्राडिक्शन्स', पेंग्विन बुक्स। अध्याय 5 : और विजय जोशी (पूर्व उल्लिखित), अध्याय 9.

¹⁸ देखें टी. एन. निनान (2015), दि टर्न ऑफ दि टॉरटाइज़, पेंग्विन रैंडम हाउस, चप्टर्स 5, 8, 9 एंड 10; देवेश कपूर, प्रताप मेहता एंड मिलन वैष्णव (2017), रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस: और विजय जोशी (पूर्व उल्लिखित), चैप्टर 11.

की घटना हतप्रभ करने वाली है: सर्वोच्च न्यायालय में 13 प्रतिशत, उच्च न्यायालयों में 29 प्रतिशत और जिला अदालतों में 21 प्रतिशत। गुणात्मक पहलू का विचार करें तो स्थित वैसी ही खराब है। पुलिस बल अपराध को रोकने के बजाय औपनिवेशिक प्रथा के अनुसार ही भीड़ नियंत्रण करने में फंसा हुआ है। इसमें राजनीति गहरे तक पैवस्त है, यहां तक कि शीर्ष जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। न्यायपालिका के पास लंबित मामलों की विस्तृत सूची है: 2015 में 32 मिलियन मामले लंबित थे जिसमें से लगभग 25 प्रतिशत मामले 5 वर्षों से लंबित थे और 10 प्रतिशत मामले पिछले 10 वर्षों से लंबित थे। शीर्ष प्रशासनिक सेवा 'सामान्य' बनी हुई है जिसके पास कोई पेशेवर कुशलता या क्षैतिज प्रवेश का मार्ग नहीं है और यह स्टाफ-स्थानांतरणों और पद पर तैनाती द्वारा गंभीर राजनैतिक हस्तक्षेप की शिकार हो गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सरकार की मुख्य सेवाओं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मामले में निचले स्तरों पर उत्पादकता एकदम कम है।

एक अन्य क्षेत्र जहां मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की बड़ी कमी देखने को मिलती है, वह है विनियमन। यह एक जटिल क्षेत्र है जिसने विश्लेषणात्मक सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाओं में कई प्रकार की उन्नतियां देखी हैं। भारत इस दौड़ में अभी पीछे है। हमें कई क्षेत्रों में प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है परंतु हमारे अधिकतर विनियमन निकाय विशेषज्ञता की कमी, स्वतंत्रता की कमी और कमजोर मानव संसाधनों से जूझ रहे हैं। विनियमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और सरकारी-निजी भागीदारी के निर्माण और निगरानी में स्पष्ट रूप से कमियां हैं। विनियामक अक्सर सेवानिवृत्त नौकरशाह होते हैं जो राजनीतिज्ञों के विरुद्ध खड़े होने के लिए अनिच्छुक होते हैं।

स्वतंत्रता के समय भारत ने काफी मजबूत संस्थानों के साथ शुरुआत की थी। परंतु इस नींव पर इमारत खड़ी करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और समस्या अब इस स्तर पर पहुंच गई है जहां इसकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस संबंध में कई समितियों की रिपोर्टें मौजूद हैं परंतु उनमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लगातार लापरवाही जोखिमपूर्ण हो सकती है क्योंकि दीर्घावधि में तीव्र और समन्वित वृद्धि मजबूत संस्थानों के बिना असंभव होगी। एक समस्या का विशेष उल्लेख करना उचित होगा, वह है सरकार में मानव संसाधन का प्रबंधन बहुत खराब है। चयन, प्रशिक्षण और प्रोन्नयन की असंतुष्टि-पूर्ण प्रक्रिया और कार्मिकों की अक्षमता की जवाबदेही, जो कि छोटी बात नहीं है और नागरिकों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की कमी व्यापक रूप से पैवस्त है। सरकारी ओहदेदारों को सार्वजनिक हित साधन के मिशन में किस प्रकार लगाया जाए यह बुनियादी महत्व की एक अनसुलझी समस्या है।

समापन टिप्पणियां

एक अंतिम टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा जो भारत में वांछित सुधार से संबंधित है: भारत को दोनो चाहिए सरकारी हस्तक्षेप हो और नहीं भी। इसे 'सरकारी हस्तक्षेप में कमी' चाहिए क्योंकि अपने तुलनात्मक लाभ की स्थिति से सरकारी हस्तक्षेप कहीं अधिक बढ़ गया है। परंतु इसे 'सरकारी हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता' भी है क्योंकि सरकार उन मुख्य कार्यकलापों को सक्षम रूप से निष्पादित नहीं कर पाती है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं। 'सरकारी हस्तक्षेप में कमी' और 'सरकारी हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता' को किस प्रकार संयुक्त किया जाए भारत के आर्थिक सुधारों की यही मुख्य चुनौती होगी।

मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका शुक्रिया।

सारणी 1
भारतीय बैंकों के दबावग्रस्त अग्रिम

(% कुल अग्रिम)

	मार्च 2008	मार्च 2014	मार्च 2017
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3.5	11.6	15.6
निजी क्षेत्र के बैंक	4.2	4.2	4.6
विदेशी बैंक	3.0	4.0	4.5
सभी बैंक	3.5	9.8	12.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सारणी 2
भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

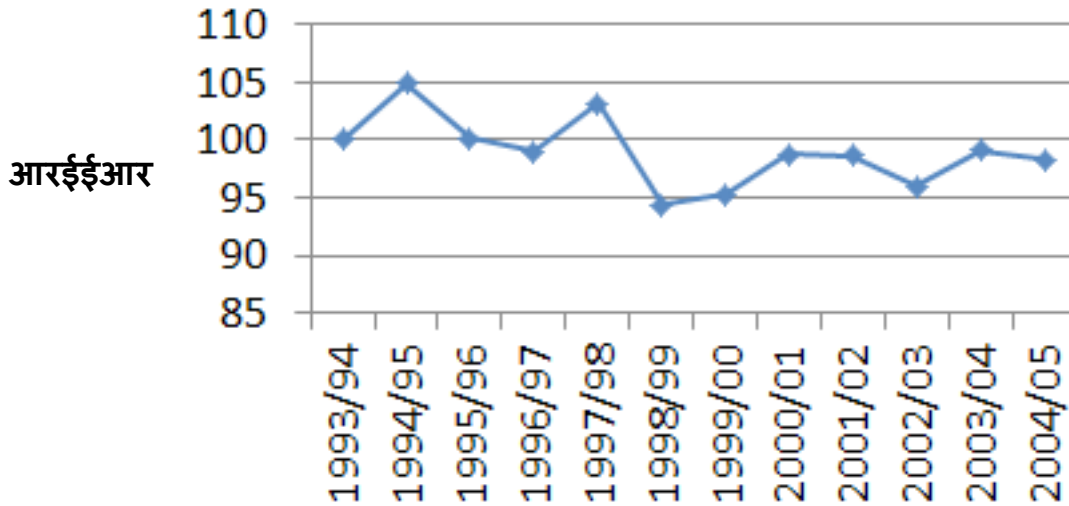
(1993/94 = 100)		(2004/05 = 100)	
1993/94	100.0	2004/05	100.0
1994/95	104.9	2005/06	102.0
1995/96	100.1	2006/07	100.5
1996/97	99.0	2007/08	109.2
1997/98	103.1	2008/09	99.7
1998/99	94.3	2009/10	104.5
1999/00	95.3	2010/11	115.0
2000/01	98.7	2011/12	113.2
2001/02	98.6	2012/13	108.7
2002/03	96.0	2013/14	105.5
2003/04	99.1	2014/15	111.3
2004/05	98.3	2015/16	114.4
		2016/17	116.4
		(एच1) 2017/18	120.5

नोट: आरईआर सूचकांक 36 देशों के द्विपक्षीय निर्यात भागों पर आधारित है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

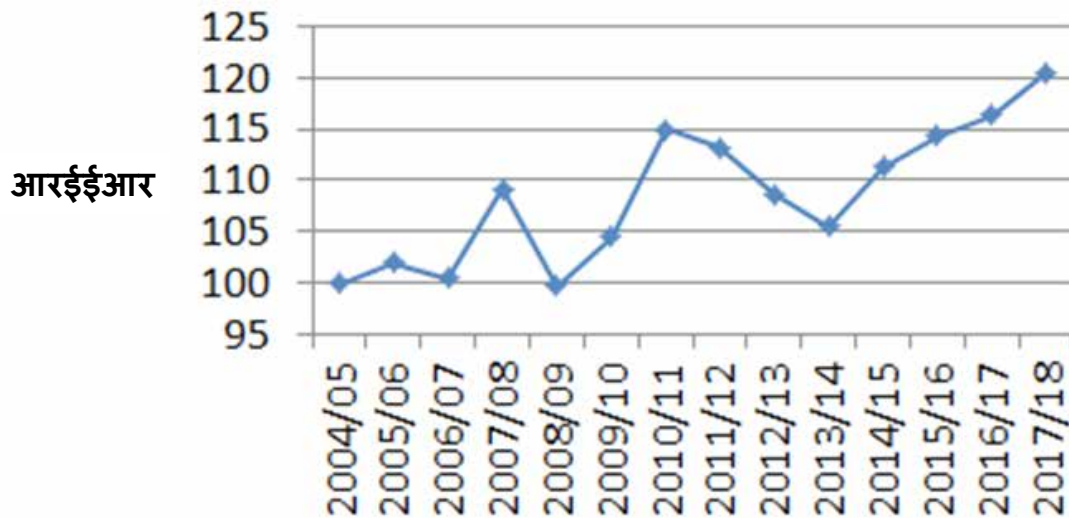
चार्ट 1

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 1993-2004



चार्ट 2

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 2004-2017



लेख

जीडीपी आंकड़ों में सांख्यिकीय विसंगतियां: भारत से प्रमाण

जीडीपी आंकड़ों में सांख्यिकीय विसंगतियां: भारत से प्रमाण*

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के माप में सांख्यिकीय विसंगतियां (एसडी) विश्व भर में एक प्रयोगसिद्ध चुनौती हैं। भारत के जीडीपी आंकड़े में, एसडी अधिक होने के साथ-साथ परिवर्तनशील रही हैं लेकिन राष्ट्रीय लेखों के आधार को बदलकर 2011-12 कर देने के साथ ही कवरेज को बढ़ाने एवं कार्यप्रणाली में सुधार करने से माप संबंधी त्रुटियां कम हुई हैं। वर्तमान में भारत के जीडीपी में एसडी की तुलना अन्य विकसित एवं उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जा सकती है। इस अनुभव को देखते हुए, आलेख के जरिए अनुशंसा की गई है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) भविष्य में एसडी के समाधान के लिए सप्लाई-यूज टेबल्स के उपयोग पर विचार करें।

I. परिचय

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक गतिविधि का अत्यंत महत्वपूर्ण माप है और नीति निर्माताओं, विश्लेषकों एवं शिक्षाविदों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है (चक्रवर्ती, 2016; केओहेन, 2016; झोंग, 2016)। उत्पादन, व्यय और आय पद्धति के जरिए जीडीपी का माप किया जा सकता है। उत्पादन पद्धति में, बाजार कीमतों पर जीडीपी के आंकड़े प्राप्त करने के लिए मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) को निवल उत्पाद करों के साथ जोड़ दिया जाता है। आय पद्धति में, कर्मचारियों को मुआवजा, सकल परिचालनगत अधिशेष/ मिश्रित आय, स्थिर पूंजी का उपभोग, एवं निवल उत्पादन और उत्पाद कर के जोड़ को सकल घरेलू आय (जीडीआई) कहा जाता है। व्यय पद्धति में, बाजार कीमतों पर जीडीपी निकालने के लिए उपभोग व्यय (निजी एवं सरकारी दोनों), निवेश एवं निवल निर्यात (निर्यात में आयात को घटाकर) को जोड़ा जाता है।

तकनीकी रूप से देखें तो पता चलता है कि इन तीन पद्धतियों की मदद से अनुमानित जीडीपी समान होना चाहिए;

* यह आलेख राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव, श्री अवधेश कुमार शुक्ल, श्री बिचित्रानन्द सेठ और श्री कुणाल प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

तथापि, व्यवहार में, ऐसा कदाचित होता है। भिन्न-भिन्न पद्धतियों से निकाले गए जीडीपी के कुल आंकड़ों में पाए गए अंतर एसडी कहलाती हैं जो यूनाइटेड नेशन्स सिस्टम ऑफ नैशनल अकाउन्ट्स 2008 (अब से एसएनए 2008) में स्थान पाती हैं। एसएनए 2008, इस समस्या से निजात पाने के दो पद्धति सुझाते हैं : (i) एसडी का प्रकाशन जीडीपी के कम सटीक प्रकार के साथ किया जाए; (ii) जहां तक हो सके श्रेष्ठ निर्णय करते हुए कि कहां त्रुटियों की संभावना हो सकती है एसडी को दूर किया जाए और तदनुसार उसमें सुधार किया जाए। भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में जीडीपी के आकलन हेतु उत्पादन पद्धति को अधिक सटीक समझा जाता है और एसडी को स्पष्टतया व्यय की तरफ दिखाया जाता है (सीएसओ, 2012)। फिर भी, भारतीय प्रणाली एसएनए 2008 की पहली सिफारिश के सदृश है।

एसडी, जीडीपी वृद्धि की व्याख्या को लेकर उसके घटकों के संदर्भ में विश्लेषकों, शोधकर्ताओं एवं नीतिनिर्माताओं के लिए गंभीर समस्या खड़ी करती है। उदाहरण के लिए, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान, जीडीपी वृद्धि में एसडी का योगदान क्रमशः (+) 14.9 प्रतिशत, (-) 12.7 प्रतिशत एवं (+) 24.2 प्रतिशत था।

पूरे विश्व में, जीडीपी में एसडी के स्रोत, आकार एवं रुझानों के विश्लेषण के अनेकों प्रयास किए गए (बाजदा, 2001; ब्लोम एवं अन्य., 1997; चांग एंड ली, 2015; एलिस, 2014)। इस विषय पर जोशीले बहस होने के बावजूद, विशेष रूप से 2011-12 के आधार वर्ष के साथ राष्ट्रीय लेखों के नव सीरीज़ की उपलब्धता के मद्देनजर, भारतीय संदर्भ में विस्तृत जांच एक कमी है, जिसकी भरपाई करने की कोशिश इस आलेख में की गई है। इस आलेख की विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: भाग II भारतीय जीडीपी आंकड़े में एसडी की अवधारणा, रुझान एवं संरचना पर केन्द्रित है; भाग III एक संक्षिप्त क्रास-कन्ट्री अनुभव पेश करता है; और भाग IV कुछ व्यावहारिक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. भारत के राष्ट्रीय लेखों में एसडी संबंधी अस्वाभाविक तथ्य

भारतीय संदर्भ में, एसडी निम्नांकित विसंगतियों का मिश्रण है, (i) राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एवं उसका विनियोग लेखा, (ii) पूंजी वित्त खाता, और (iii) बाह्य

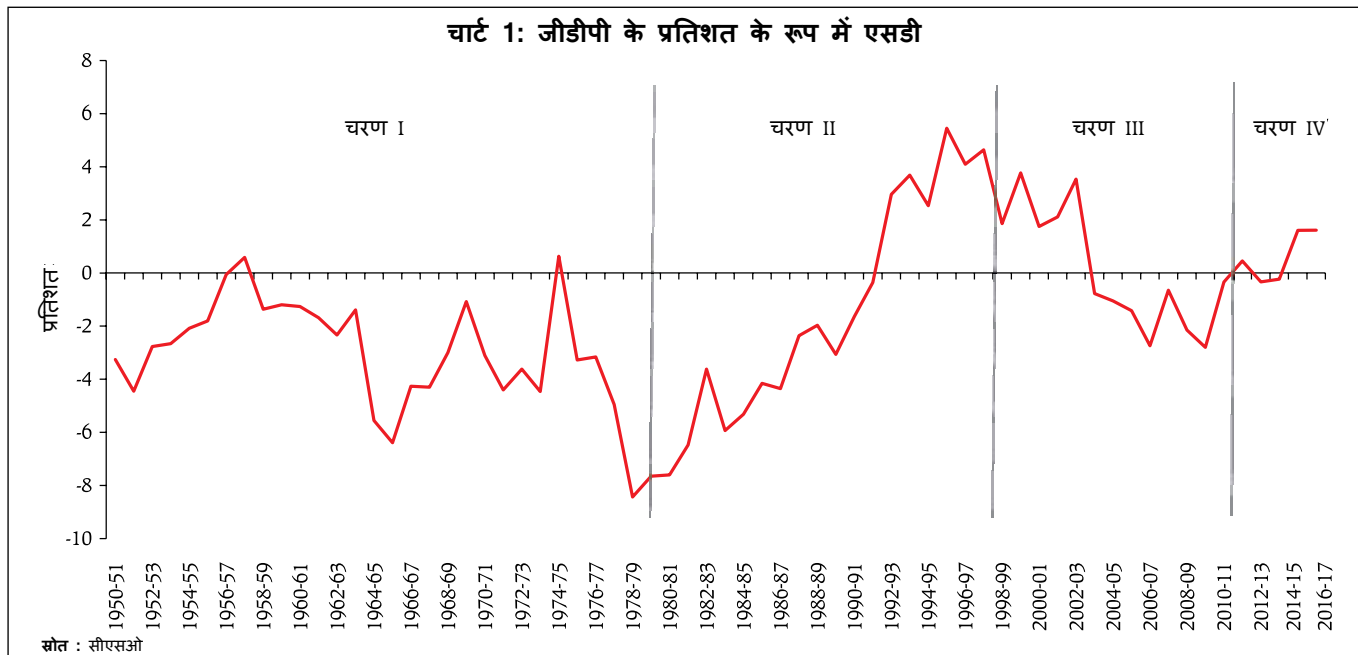
लेनदेन खाता।¹ समेकित विसंगति को व्यय खाता संबंधी जीडीपी में रिपोर्ट किया गया है²।

प्रयोज्य आय एवं उसके विनियोग लेखा को अंतिम उपभोग व्यय (निजी एवं सरकारी दोनों) और बचत के साथ-साथ उत्पादन खाता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अर्थात्, मूल कीमतों पर योजित निवल मूल्य और शेष विश्व से निवल फैक्टर प्रवाह और निवल अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण का जोड़। एसडी, उपभोग एवं बचत से निकाली गई प्रयोज्य आय और उत्पादन पद्धति के बीच का संपूर्ण अंतर होता है।

पूंजी वित्त खाता से सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) एवं सकल बचत के संबंध में जानकारी मिलती है। इन दो पद्धतियों की मदद से जीसीएफ का अनुमान लगाया जाता है: (i) निधि प्रवाह पद्धति के माध्यम से, जिसे सकल बचत

और सीमापार से निवल पूंजी अंतर्वाह के जोड़ से प्राप्त किया जाता है; और (ii) पण्य प्रवाह पद्धति के जरिए, जिसे आस्ति प्रकार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रिवाज के अनुसार, निधि प्रवाह पद्धति के जरिए आकलित जीसीएफ को अधिक दृढ़ माना जाता है, और इन दो पद्धतियों के बीच के अंतर को 'भूल-चूक' के रूप में माना जाता है।

बाह्य लेनदेन खाते के मामले में, एसडी का संबंध पण्य निर्यात और आयात को लेकर आंकड़ों के इन दो स्रोतों - भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) में पाए गए अंतर से है। इन दो पद्धतियों के बीच के अंतर को 'निवल समायोजन' के रूप में माना जाता है। व्यय पद्धति³ का उपयोग कर समेकित एसडी को जीडीपी में दर्शाया गया है। अतः, एसडी से उत्पादन और व्यय पद्धतियों के बीच



¹ http://mospiold.nic.in/Mospi_New/upload/NAS2014/NAS14.htm

² सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखों की सीरीज़ को एसएनए 2008 की तर्ज पर आधार वर्ष 2011-12 के साथ संशोधित किया है। राष्ट्रीय लेखों की नई सीरीज़ (आधार वर्ष: 2011-12) एसडी की समेकित संख्या दर्शाती है।

³ जीडीपी के समेकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया जीवीए और निवल अप्रत्यक्ष करों के जोड़ के माध्यम से प्रत्येक प्रोड्यूसर यूनिट में प्रॉडक्शन गतिविधि का आकलन करना है। यहां पर जीवीए का मूल्य प्रॉडक्शन की प्रक्रिया में उपयोग किए गए आउटपुट मूल्य में इनपुट मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है।

जीडीपी का आकलन उपयोग या व्यय के घटकों को जोड़कर भी किया जा सकता है, अर्थात्, जीडीपी = अंतिम उपभोग + सकल स्थिर पूंजी निर्माण + स्टॉक में बदलाव + बहुमूल्य वस्तुएं + निवल निर्यात। इसे आय पद्धति के माध्यम से आंका जा सकता है, जहां आय को दो प्राथमिक फैक्टर इनपुट के बीच बांटा जाता है, नामतः, पूंजी और श्रमिक। बाजार कीमतों पर जीडीपी = स्थिर पूंजी का उपभोग + कर्मचारी को मुआवजा + परिचालन अधिशेष/ मिश्रित आय + उत्पाद कर में उत्पाद सब्सिडी को घटाकर।

संपूर्ण अंतर का आकलन प्रस्तुत होता है। रिवाज के तौर पर, उत्पादन पद्धति से प्राप्त जीडीपी, जिसे अधिक दृढ़ माना जाता है, को अंतिम जीडीपी के रूप में माना जाता है (सीएसओ, 2012)। विश्लेषणात्मक सुविधा के लिए, अध्ययन अवधि (1950-51 से 2016-17) को चार चरणों⁴ में विभाजित किया जाता है (चार्ट 1)। प्रत्येक चरण की एक अलग विशेषता होती है।

चरण I में, जीडीपी में एसडी का हिस्सा अधिकांशतः नेगेटिव था और यह बिना किसी निश्चित रुझान के घटती-बढ़ती है। चरण II में, तथापि, इसमें बढ़ते रुझान देखे गए लेकिन अपेक्षाकृत रूप से धीमी गति से घटी-बढ़ी। चरण III में विपरीत स्थिति पाई गई जिसमें एसडी शून्य की तरफ बढ़ने लगी, जो आंकड़े की गुणवत्ता के संबंध में सीएसओ के सतत प्रयास को दर्शाता है।

परिमाण के संदर्भ में, औसत एसडी कम रही हैं जो चारों चरणों में जीडीपी का (-) 3.0 प्रतिशत से (+) 0.5 प्रतिशत थी (सारणी 1)। तथापि, जीडीपी में एसडी के हिस्से का परिवर्तन गुणांक दर्शाता है कि वह जीडीपी के अन्य घटकों की अपेक्षा अत्यधिक अस्थिर घटक है।

एसडी के संबंध में प्रयोगसिद्ध विश्लेषण से प्राप्त रोचक अस्वाभाविक तथ्यों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- चार्ट 2ए एवं अनुबंध सारणी में एसडी के संचलन वाले व्यापक दायरे को दर्शाया गया है, जिससे वास्तविक जीडीपी वृद्धि में योगदान⁵ का पता चलता है। यह संख्या (-) 426 प्रतिशत (1957-58 में) से 1514 प्रतिशत (1965-66 में) के अधिकतम दायरे में रहा और सात⁶ वर्षों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में एसडी का

सारणी 1: जीडीपी के व्यय पक्ष की विस्तृत सांख्यिकी

	निजी उपभोग	सरकारी उपभोग	स्थायी निवेश	निर्यात	आयात	सांख्यिकीय विसंगतियां
माध्यम (जीडीपी में हिस्सा)						
चरण I	78.8	8.0	16.9	5.1	6.8	-3.0 (3.0)
चरण II	69.2	11.9	21.7	7.3	9.2	-2.0 (4.1)
चरण III	60.3	11.5	28.6	17.3	21.3	0.5 (1.8)
चरण IV	56.2	10.3	32.3	23.3	26.4	0.5 (0.8)
अस्थिरता (मानक विचलन)						
चरण I	4.9	2.0	2.6	1.2	1.6	2.0
चरण II	4.1	0.7	1.1	1.4	2.1	4.2
चरण III	1.8	0.9	4.2	4.8	6.1	2.6
चरण IV	0.3	0.5	1.7	2.1	4.3	0.9
अस्थिरता (अस्थिरता गुणांक)						
चरण I	6.2	25.0	15.4	23.5	23.5	-66.7
चरण II	5.9	5.9	5.1	19.2	22.8	-210.1
चरण III	2.9	7.8	14.8	27.9	28.6	555.4
चरण IV	0.6	4.4	5.2	9.1	16.2	203.8

टिप्पणी: जीडीपी में शेयर के आधार पर गणना की गई है; शेयर का जोड़ मिलकर 100 प्रतिशत नहीं हो पाएगा क्योंकि जीडीपी के कुछ घटकों को यहाँ रिपोर्ट नहीं किया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ण औसत शेयर हैं।

स्रोत: सीएसओ एवं स्टाफ गणना ।

⁴ चरण I 1950-51 से 1979-80 तक, चरण II 1980-81 से 1997-98 तक, चरण III 1998-99 से 2010-11 तक और चरण IV 2011-12 से है। संदर्भ अवधि की चरणबद्धता आंकड़े में पाए गए चढ़ाव एवं उतार के आधार पर किया गया है।

⁵ जीडीपी वृद्धि में योगदान = $((SD_t - SD_{t-1}) / (Y_t - Y_{t-1})) * 100$

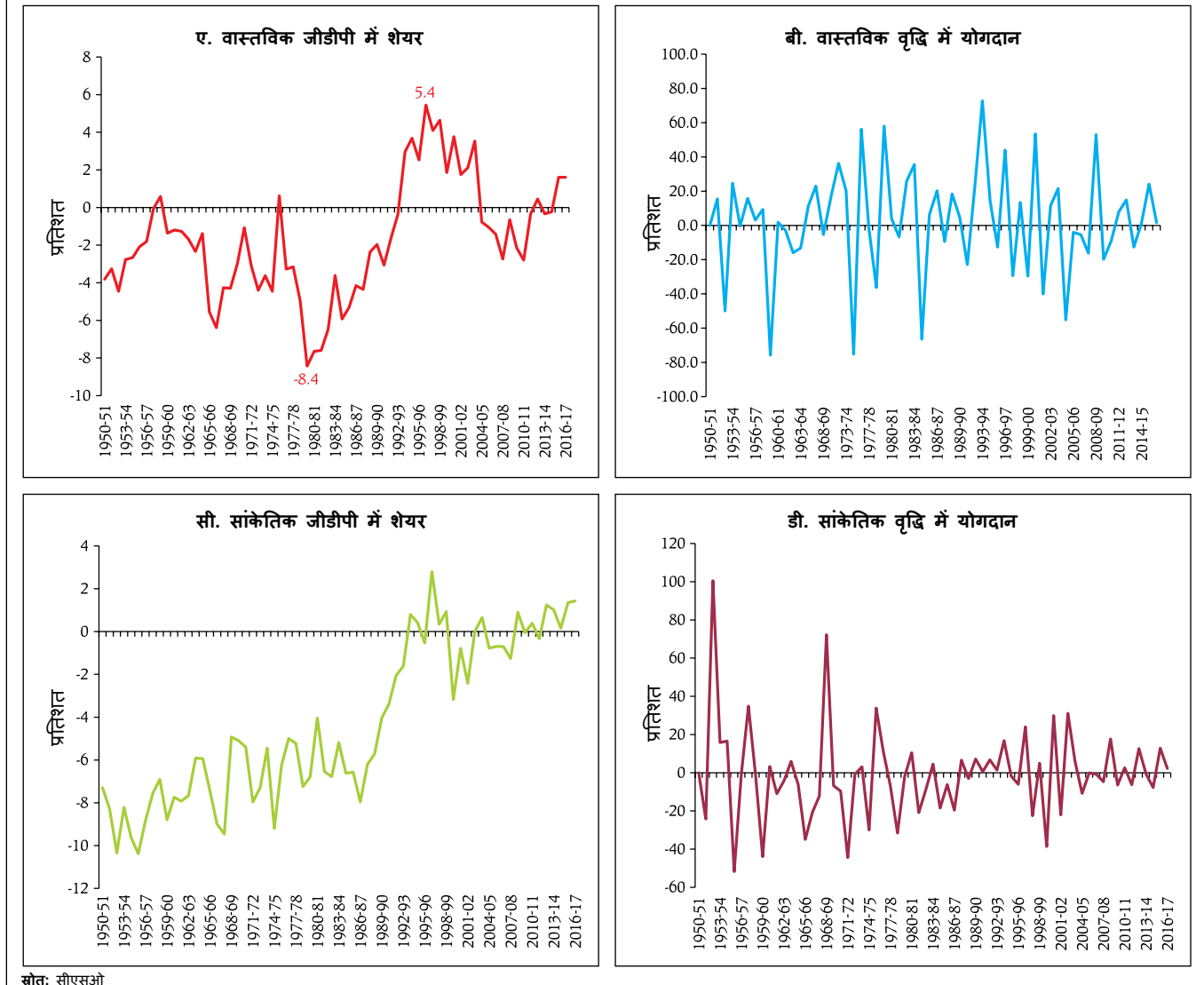
⁶ सात वर्ष इस प्रकार हैं: 1956-57 (-425.7 प्रतिशत), 1964-65 (152.4 प्रतिशत), 1965-66 (1514.0 प्रतिशत), 1970-71 (-126.7 प्रतिशत), 1971-72 (230.6 प्रतिशत), 1975-76 (-238.0 प्रतिशत) एवं 1990-91 (133.1 प्रतिशत)। इन वर्षों को चार्ट में शामिल नहीं किया गया है।

योगदान (+/-) 100 प्रतिशत से अधिक रहा (चार्ट 2बी)।

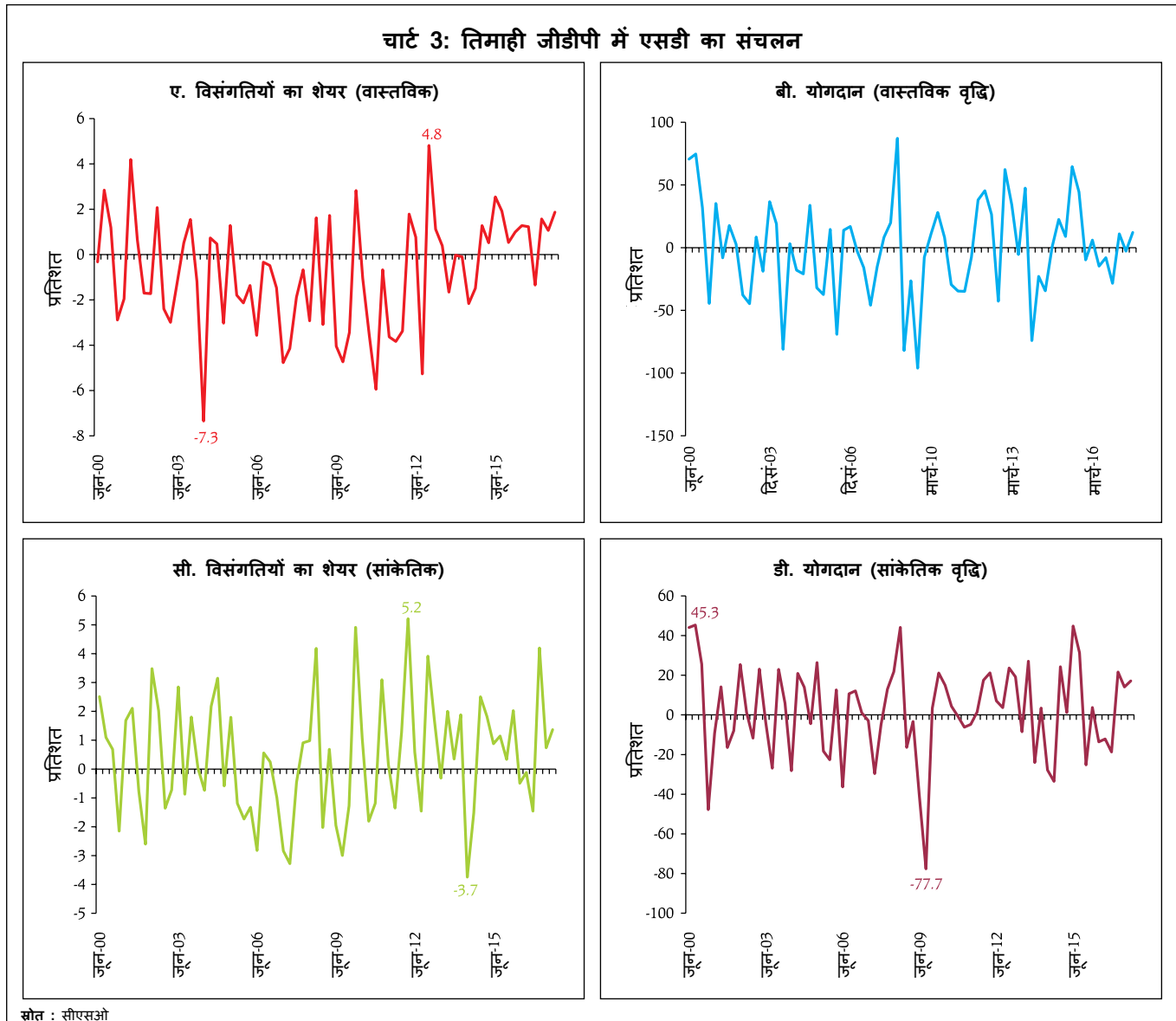
- ii. सांकेतिक कीमतों पर, जीडीपी (चार्ट 2सी) में एसडी का हिस्सा अधिकांशतः नेगेटिव जोन में रहा, जो अभी हाल के वर्षों में ही पॉजिटिव क्षेत्र में आया और समय के साथ योगदान घटा (चार्ट 2डी) - अपस्फीतिक सांकेतिक जीडीपी के लिए समुचित कीमत सूचकांक की अनुपलब्धता का सूचक।

- iii. त्रैमासिक आंकड़े के संदर्भ में, एसडी, सांकेतिक संदर्भों की अपेक्षा वास्तविक संदर्भों में अत्यधिक एवं अधिक परिवर्तनशील हैं, जीडीपी में हिस्सा और वृद्धि में योगदान दोनों के संदर्भ में (चार्ट 3⁷ एवं सारणी 2)।
- iv. इसी प्रकार, जीडीपी में हिस्सा और वृद्धि में योगदान, वार्षिक आंकड़े की अपेक्षा त्रैमासिक आंकड़े के लिए अधिक परिवर्तनशील हैं।

चार्ट 2: बाजार मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी में एसडी का संचलन



⁷ (+/-) 100 प्रतिशत से अधिक के मूल्यों को चार्ट 3बी और 3डी में ट्रन्केट कर दिया गया है।



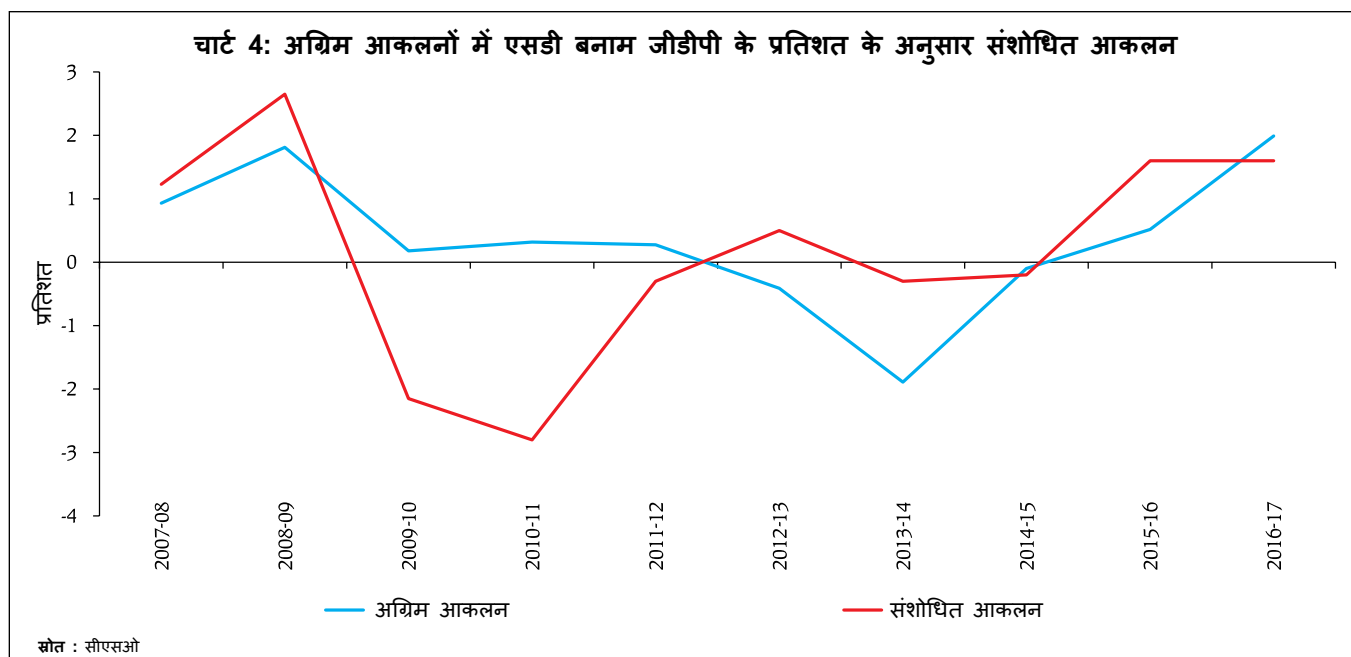
सीएसओ ने 2007-08 से अग्रिम आकलनों में एसडी के संबंध में सूचना का प्रकाशन कार्य शुरू कर दिया है। 2007-08 के बाद से अंतिम संशोधित आकलनों में एसडी के साथ

तुलना दर्शाता है कि एसडी समग्र औसत संदर्भ में बाद वाले से अधिक है (चार्ट 4)।

सारणी 2: तिमाही जीडीपी में एसडी के लिए व्याख्यात्मक सांख्यिकी

मानदंड	वास्तविक मूल्य		सांकेतिक मूल्य	
	शेयर	वृद्धि में योगदान	शेयर	वृद्धि में योगदान
माध्य	-0.5	3.0	0.5	-0.7
माध्य निरपेक्ष	2.2	47.1	1.8	18.2
मानक विचलन	2.6	124.7	2.1	23.5

स्रोत: सीएसओ एवं स्टाफ गणना



III. भिन्न-भिन्न देशों के अनुभव

एसडी भारतीय राष्ट्रीय खातों के लिए विशिष्ट नहीं हैं। भिन्न-भिन्न देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अनेक विकसित एवं उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा ही अनुभव देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) में, एसडी को तिमाही आंकड़े में दर्शाया गया है, लेकिन वार्षिक संख्याओं तक पहुंचने से पहले ही पक्के आंकड़े प्राप्त कर लिए गए थे (सारणी 3)। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इन देशों ने सांख्यिकीय मिलान के संबंध में विस्तृत सुव्यवस्थित टिप्पणियां⁸ जारी की हैं।

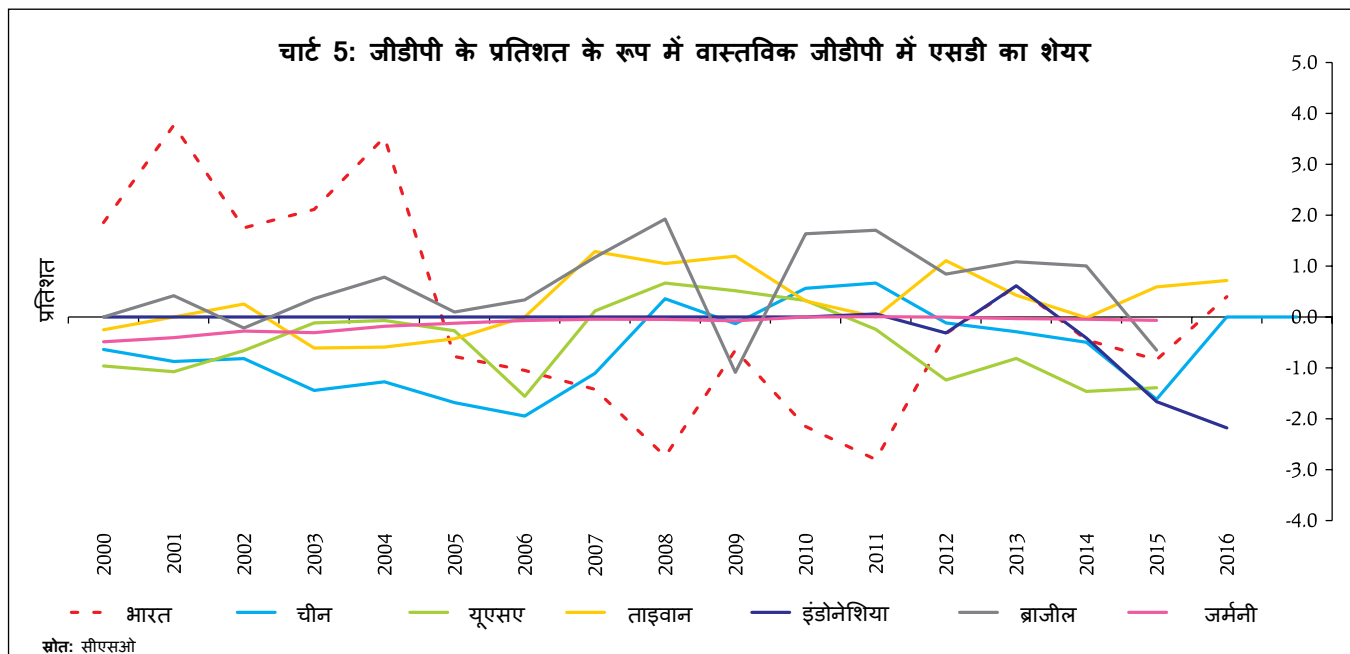
दूसरी तरफ, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएसए), कनाडा और चीन द्वारा एसडी का मिलान नहीं किया जाता है। यूएसए अपने आय खाते में एसडी सम्मिलित करता है, लेकिन कनाडा दोनों तरफ से अंतिम जीडीपी के रूप में जीडीपी के औसत का उपयोग करता है और दोनों आकलनों में एसडी आबंटित करता है। सिंगापुर में, जीडीपी खातों का मिलान प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार होता है। देश के तौर-तरीकों के सर्वेक्षण से मालूम होता है कि एसडी के मिलान के लिए 'सप्लाई-यूज टेबल्स' सर्वाधिक महत्वपूर्ण रास्ता है।

विभिन्न देशों की ऐतिहासिक तुलना से मालूम होता है कि भारत में एसडी अपेक्षाकृत रूप से अधिक है। तथापि,

सारणी 3: राष्ट्रीय खातों में एसडी के साथ बर्ताव : चुनिंदा देश की परिपाटी

देश	एसडी से जुड़ी परिपाटी
यूएसए	जीडीपी (व्यय) और सकल घरेलू आय (जीडीआई) के बीच के अंतर को एसडी के रूप में माना जाता है, जिसे जीडीआई खाते में हिसाब में लिया जाता है। इसे राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों में साफ तौर पर रिपोर्ट किया जाता है। फिर भी, आंकड़ों की गुणवत्ता, समतुलन एवं न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने के माध्यम से एसडी के आकार को कम करने के प्रयास जारी हैं।
यूके	समतुलन पूर्व की विसंगतियों को वार्षिक सप्लाई-यूज समतुलन के जरिए दूर किया जाता है, जीडीपी आउटपुट पद्धति पर आधारित है; विसंगतियों को आय पद्धति और व्यय पद्धति से आकलित जीडीपी में दर्शाया गया है।
कनाडा	आय और व्यय पद्धतियों का औसत जीडीपी होता है। एसडी को जीडीपी के दोनों पक्षों में दर्शाया जाता है। मिलान के लिए वार्षिक पूर्णतः समतुलित सप्लाई-यूज टेबल्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन एसडी को दूर करने के लिए इसे न्यूनतम मानदंड के रूप में पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है।
आस्ट्रेलिया	एसडी को दूर करने के लिए वार्षिक सप्लाई-यूज टेबल्स उपयोग में लाए गए हैं। त्रैमासिक वास्तविक जीडीपी, तीन पद्धतियों का औसत है।
सिंगापुर	उत्पादन पद्धति और व्यय पद्धति के जरिए संकलित जीडीपी के बीच के अंतर को व्यय-आधारित आकलनों की एसडी मद में निर्धारित किया जाता है। जीडीपी की अलग-अलग पद्धतियों (उत्पादन, व्यय और आय) का मिलान पांच साल में एक बार किया जाता है।

⁸ <https://www.ons.gov.uk/.../an-introduction-to-reconciled-estimates-of-gdp.pdf>



हाल की अवधि में, भारत में एसडी घटा और समकक्ष देशों के स्तर के करीब पहुंचा (चार्ट 5)।

IV. निष्कर्ष

जीडीपी का उपयोग आम तौर पर आर्थिक गतिविधि की स्थिति का मूल्यांकन करने के मैट्रिक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह समग्र मांग स्थितियों का तकरीबन सही अनुमान लगाता है और भिन्न-भिन्न देशों के बीच तुलना करने योग्य है। तथापि, भारत में योजित सकल मूल्य (जीवीए) के बेहतर क्षेत्रीय कवरेज एवं गतिविधि के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक इलाकों, जो कुल मिलाकर समग्र आपूर्ति दर्शाती हैं, की व्याख्या करने के संदर्भ में विश्वसनीयता के मद्देनजर इसके उपयोग को लेकर सांख्यिकीविद, शिक्षाविद और नीति निर्माताओं में भारी प्राथमिकता है। जीवीए, प्रोड्यूसर्स की लाभप्रदता का भी बेहतर प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता जिसकी वजह से उत्पादन प्रक्रिया की विश्लेषणात्मक दृष्टि विकृत हो सकती है। परिणामस्वरूप, जीवीए के घटकों के इर्द-गिर्द गतिविधि के उच्च फ्रीक्वेंसी संकेतक विकसित हो गए हैं और जीडीपी के इर्द-गिर्द कम दृढ़ता से। फिर भी, इसी शैली में कहे तो, यह तर्क दिया जा सकता है कि सब्सिडी के होने की वजह से जीडीपी विकृत हो जाती है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय तुलना की मजबूरी की वजह से यह भारत के लिए अनिवार्य होता जा रहा है क्योंकि यह वैश्विक

अर्थव्यवस्था में तेजी से समाहित होता है और वैश्विक वृद्धि में अत्यधिक योगदान देता है।

एक पेशेवर के नज़रिये से देखे तो, भारत में जीडीपी के उपयोग पर बाधा प्रकट करने वाला एक सबसे बड़ा कारक है इसमें सन्निहित एसडी का आकार, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ समकक्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा बड़ा है, जैसा इस आलेख में संकेत किया गया है। हाल में भी, भारतीय राष्ट्रीय खातों में एसडी अस्थिर साबित हुई हैं - स्थिर कीमतों के संदर्भ में और अधिक - जो अंतर्निहित समष्टिआर्थिक स्थिति के सटीक आकलन में विकृति पैदा कर देता है। वास्तव में, माध्यम और अस्थिरता के संदर्भ में जीडीपी बगैर एसडी के जीवीए से तुलनीय है।

इस आलेख के दृष्टिकोण से खुशी की बात यह है कि हाल के वर्षों में कवरेज बढ़ाने एवं आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया के साथ-साथ गणना/आकलन की कार्यप्रणालियों को परिष्कृत करने में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। परिणामस्वरूप, माप संबंधी त्रुटियों को कम कर दिया गया है। इस सुधार की तार्किक परिणति के रूप में जीडीपी को गतिविधि के औपचारिक हेडलाइन माप के रूप में अपनाये जाने के प्रति एक नई रुचि पैदा होने लगी है। यूके में, सप्लाइ यूज टेबल्स का इस्तेमाल आउटपुट, व्यय एवं आय एग्निग्रेट्स के आंकड़े में समायोजन करने के लिए किया जाता है। भारत ने सप्लाइ यूज टेबल्स के प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया है

जिसमें 2011-12 एवं 2012-13 के आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। भविष्य में, सीएसओ, अंतिम जीडीपी आकलनों के मिलान एवं एसडी को दूर करने या अपने समकक्ष वाले देशों के स्तरों के मुताबिक एसडी के आकार और अस्थिरता को कम करने के लिए इन टेबल्स के उपयोग पर विचार कर सकता है।

संदर्भ

Bajada, Christopher (2001). "An Examination of the Statistical Discrepancy and Private Investment expenditure", *Journal of Applied Economics*, Vol. IV, No 1.

Bloem, Adriaan M., Robert Dippelsman, Fenella Maitland-Smith, and Paul Armknecht (1997). "Discrepancies between Quarterly GDP Estimates", IMF WP/97/123.

Central Statistics Office (CSO) (2012). *National Accounts Statistics: Sources and Methods*.

Chakravarty, M. (2016), "'Discrepancies' Drive GDP Growth", Retrieved 14 March 2017, from The Livemint: <http://www.livemint.com/> Opinion/

kvvDHfbryOQjvu2116UcEI/Discrepancies-drive-GDP-growth.html

Chang, Andrew C. and Phillip Li (2015). "Measurement Error in Macroeconomic Data and Economic Research: Data Revisions, Gross Domestic Product, and Gross Domestic Income", Finance and Economics Discussion Series 2015-102. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, <http://dx.doi.org/10.17016/FEDS.2015.102>.

Daniel, Ellis (2014). "An Introduction to Reconciled Estimates of GDP", National Accounts Coordination Division, ONS, 28 March 2014.

Keohane, D. (2016). *Alphaville*. Retrieved 14 March 2017 from The Financial Times: <https://ftalphaville.ft.com/2016/06/01/2164140/discrepancies-and-indian-gdp-data/>.

Zhong, R. (2016). <http://blogs.wsj.com>. Retrieved 7 March 2017, from The Wall Street Journal: <http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2016/06/02/indias-top-statistician-defends-economic-growth-numbers-warts-and-all/>.

अनुबंध

ए1: वर्तमान कीमतों पर वार्षिक जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)					
वर्ष	जीडीपी बाज़ार कीमतों पर (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1		3	4	5	6
1950-51	104.0	-7.6		-7.3	
1951-52	110.5	-9.2	6.3	-8.3	-24.2
1952-53	108.5	-11.2	-1.8	-10.3	100.5
1953-54	118.1	-9.7	8.8	-8.2	15.8
1954-55	111.7	-10.8	-5.4	-9.6	16.6
1955-56	113.7	-11.8	1.8	-10.4	-51.7
1956-57	135.5	-12.0	19.1	-8.8	-0.8
1957-58	139.5	-10.6	3.0	-7.6	34.9
1958-59	155.5	-10.7	11.5	-6.9	-1.1
1959-60	163.8	-14.4	5.4	-8.8	-43.9
1960-61	179.4	-13.9	9.5	-7.7	3.3
1961-62	190.1	-15.1	6.0	-7.9	-11.0
1962-63	204.3	-15.7	7.5	-7.7	-4.3
1963-64	234.6	-13.9	14.8	-5.9	5.9
1964-65	273.7	-16.3	16.6	-5.9	-6.1
1965-66	288.6	-21.5	5.4	-7.4	-34.9
1966-67	326.7	-29.4	13.2	-9.0	-20.8
1967-68	382.6	-36.2	17.1	-9.5	-12.2
1968-69	405.1	-20.0	5.9	-4.9	72.2
1969-70	446.1	-22.8	10.1	-5.1	-6.8
1970-71	476.4	-25.7	6.8	-5.4	-9.7
1971-72	510.0	-40.6	7.1	-8.0	-44.4
1972-73	562.1	-41.0	10.2	-7.3	-0.8
1973-74	684.2	-37.3	21.7	-5.4	3.1
1974-75	807.7	-74.3	18.1	-9.2	-30.0
1975-76	867.1	-54.2	7.4	-6.2	33.9
1976-77	934.2	-46.7	7.7	-5.0	11.2
1977-78	1058.5	-55.3	13.3	-5.2	-6.9
1978-79	1146.5	-83.1	8.3	-7.2	-31.5
1979-80	1257.3	-85.4	9.7	-6.8	-2.1

ए1: वर्तमान कीमतों पर वार्षिक जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (समाप्त)					
वर्ष	जीडीपी बाज़ार कीमतों पर (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6
1980-81	1496.4	-60.4	19.0	-4.0	10.4
1981-82	1758.1	-115.1	17.5	-6.5	-20.9
1982-83	1966.4	-133.3	11.9	-6.8	-8.8
1983-84	2290.2	-118.8	16.5	-5.2	4.5
1984-85	2566.1	-169.8	12.0	-6.6	-18.5
1985-86	2895.2	-190.4	12.8	-6.6	-6.2
1986-87	3239.5	-257.7	11.9	-8.0	-19.6
1987-88	3682.1	-228.4	13.7	-6.2	6.6
1988-89	4368.9	-249.5	18.7	-5.7	-3.1
1989-90	5019.3	-202.8	14.9	-4.0	7.2
1990-91	5862.1	-198.0	16.8	-3.4	0.6
1991-92	6738.8	-138.9	15.0	-2.1	6.7
1992-93	7745.5	-125.0	14.9	-1.6	1.4
1993-94	8913.6	71.0	15.1	0.8	16.8
1994-95	10455.9	43.5	17.3	0.4	-1.8
1995-96	12267.3	-65.6	17.3	-0.5	-6.0
1996-97	14192.8	396.7	15.7	2.8	24.0
1997-98	15723.9	52.8	10.8	0.3	-22.5
1998-99	18033.8	167.8	14.7	0.9	5.0
1999-00	20122.0	-638.8	11.6	-3.2	-38.6
2000-01	21686.5	-170.9	7.8	-0.8	29.9
2001-02	23483.3	-566.9	8.3	-2.4	-22.0
2002-03	25306.6	-0.6	7.8	0.0	31.1
2003-04	28379.0	185.5	12.1	0.7	6.1
2004-05	32422.1	-251.5	14.2	-0.8	-10.8
2005-06	36933.7	-256.5	13.9	-0.7	-0.1
2006-07	42947.1	-303.6	16.3	-0.7	-0.8
2007-08	49870.9	-632.6	16.1	-1.3	-4.8
2008-09	56300.6	506.2	12.9	0.9	17.7
2009-10	64778.3	-37.9	15.1	-0.1	-6.4
2010-11	77841.2	302.3	20.2	0.4	2.6
2011-12	87363.3	-296.2	12.2	-0.3	-6.3
2012-13	99440.1	1225.7	13.8	1.2	12.6
2013-14	112335.2	1143.9	13.0	1.0	-0.6
2014-15	124679.6	186.9	11.0	0.1	-7.8
2015-16	137640.4	1853.2	10.4	1.3	12.9
2016-17	152537.1	2181.4	10.8	1.4	2.2

*: जीडीपी वृद्धि में अंशदान = $((SD_t - SD_{t-1}) / (Y_t - Y_{t-1})) * 100$

टिप्पणी: 2011-12 और उसके बाद के आंकड़े आधार-वर्ष 2011-12 की कीमतों पर, जबकि उसके पहले के आंकड़े आधार-वर्ष 2004-05 की कीमतों पर आधारित हैं।

स्रोत: सीएसओ

ए2: स्थिर कीमतों पर वार्षिक जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)					
वर्ष	जीडीपी बाज़ार कीमतों पर (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6
1950-51	2939.4	-112.1		-3.8	
1951-52	3026.0	-98.7	2.9	-3.3	15.5
1952-53	3105.4	-138.3	2.6	-4.5	-49.9
1953-54	3296.4	-91.3	6.2	-2.8	24.6
1954-55	3455.0	-92.0	4.8	-2.7	-0.5
1955-56	3566.8	-74.3	3.2	-2.1	15.9
1956-57	3765.8	-68.1	5.6	-1.8	3.1
1957-58	3750.3	-2.2	-0.4	-0.1	-425.7
1958-59	4027.5	23.7	7.4	0.6	9.3
1959-60	4133.2	-56.4	2.6	-1.4	-75.8
1960-61	4360.4	-52.2	5.5	-1.2	1.8
1961-62	4522.7	-57.2	3.7	-1.3	-3.1
1962-63	4655.3	-78.4	2.9	-1.7	-16.0
1963-64	4934.3	-115.4	6.0	-2.3	-13.3
1964-65	5302.1	-73.6	7.5	-1.4	11.4
1965-66	5162.3	-286.5	-2.6	-5.6	152.4
1966-67	5159.5	-329.8	-0.1	-6.4	1514.0
1967-68	5563.2	-237.2	7.8	-4.3	22.9
1968-69	5751.7	-247.3	3.4	-4.3	-5.3
1969-70	6127.9	-183.8	6.5	-3.0	16.9
1970-71	6443.9	-69.2	5.2	-1.1	36.3
1971-72	6549.8	-203.4	1.6	-3.1	-126.7
1972-73	6513.5	-286.9	-0.6	-4.4	230.6
1973-74	6728.2	-243.7	3.3	-3.6	20.2
1974-75	6807.9	-303.6	1.2	-4.5	-75.2
1975-76	7430.8	46.5	9.1	0.6	56.2
1976-77	7554.4	-247.6	1.7	-3.3	-238.0
1977-78	8102.5	-256.0	7.3	-3.2	-1.5
1978-79	8565.3	-424.2	5.7	-5.0	-36.3
1979-80	8116.7	-684.5	-5.2	-8.4	58.0

ए2: स्थिर कीमतों पर वार्षिक जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (समाप्त)					
वर्ष	जीडीपी बाज़ार कीमतों पर (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6
1980-81	8663.4	-662.7	6.7	-7.6	4.0
1981-82	9183.7	-698.0	6.0	-7.6	-6.8
1982-83	9502.9	-615.3	3.5	-6.5	25.9
1983-84	10195.6	-368.8	7.3	-3.6	35.6
1984-85	10585.2	-627.8	3.8	-5.9	-66.5
1985-86	11141.3	-592.8	5.3	-5.3	6.3
1986-87	11673.5	-485.2	4.8	-4.2	20.2
1987-88	12136.4	-528.6	4.0	-4.4	-9.4
1988-89	13304.9	-314.1	9.6	-2.4	18.4
1989-90	14096.1	-277.5	5.9	-2.0	4.6
1990-91	14876.1	-455.6	5.5	-3.1	-22.8
1991-92	15033.4	-246.3	1.1	-1.6	133.1
1992-93	15857.6	-56.8	5.5	-0.4	23.0
1993-94	16610.9	491.5	4.8	3.0	72.8
1994-95	17717.0	652.5	6.7	3.7	14.6
1995-96	19059.0	482.4	7.6	2.5	-12.7
1996-97	20497.9	1116.7	7.5	5.4	44.1
1997-98	21328.0	872.8	4.0	4.1	-29.4
1998-99	22647.0	1049.9	6.2	4.6	13.4
1999-00	24650.3	457.4	8.8	1.9	-29.6
2000-01	25597.1	964.2	3.8	3.8	53.5
2001-02	26831.9	470.0	4.8	1.8	-40.0
2002-03	27852.6	588.5	3.8	2.1	11.6
2003-04	30041.9	1060.9	7.9	3.5	21.6
2004-05	32422.1	-251.5	7.9	-0.8	-55.1
2005-06	35432.4	-372.9	9.3	-1.1	-4.0
2006-07	38714.9	-550.0	9.3	-1.4	-5.4
2007-08	42509.5	-1164.7	9.8	-2.7	-16.2
2008-09	44163.5	-287.8	3.9	-0.7	53.0
2009-10	47908.5	-1030.6	8.5	-2.2	-19.8
2010-11	52823.9	-1480.4	10.3	-2.8	-9.2
2011-12	87363.3	-296.2	6.6	-0.3	8.0
2012-13	92130.2	416.4	5.5	0.5	14.9
2013-14	98013.7	-330.6	6.4	-0.3	-12.7
2014-15	105276.8	-244.9	7.4	-0.2	1.2
2015-16	113861.5	1828.4	8.2	1.6	24.2
2016-17	121960.1	1962.3	7.1	1.6	1.7

*: जीडीपी वृद्धि में अंशदान = $((SD_t - SD_{t-1}) / (Y_t - Y_{t-1})) * 100$

टिप्पणी: 2011-12 और उसके बाद के आंकड़े आधार-वर्ष 2011-12 की कीमतों पर, जबकि उसके पहले के आंकड़े आधार-वर्ष 2004-05 की कीमतों पर आधारित हैं।

स्रोत: सीएसओ

ए3: वर्तमान मूल्य पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)						
वर्ष	तिमाही	बाज़ार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	ति1	3530.2	97.5	11.3	2.8	-9.0
	ति2	3326.6	91.8	10.6	2.8	-9.8
	ति3	4129.3	114.0	9.6	2.8	-11.0
	ति4	4285.6	118.3	11.6	2.8	-8.6
1998-99	ति1	3991.8	108.2	13.1	2.7	2.3
	ति2	3900.9	105.7	17.3	2.7	2.4
	ति3	4801.9	130.1	16.3	2.7	2.4
	ति4	4817.5	130.5	12.4	2.7	2.3
1999-00	ति1	4523.2	-57.3	13.3	-1.3	-31.1
	ति2	4361.8	-143.4	11.8	-3.3	-54.0
	ति3	5239.4	-62.2	9.1	-1.2	-44.0
	ति4	5396.0	4.3	12.0	0.1	-21.8
2000-01	ति1	4935.0	124.0	9.1	2.5	44.0
	ति2	4794.6	52.7	9.9	1.1	45.3
	ति3	5633.5	38.6	7.5	0.7	25.6
	ति4	5660.0	-121.9	4.9	-2.2	-47.8
2001-02	ति1	5309.1	89.4	7.6	1.7	-9.2
	ति2	5197.5	109.6	8.4	2.1	14.1
	ति3	6154.6	-47.2	9.2	-0.8	-16.5
	ति4	6128.3	-159.6	8.3	-2.6	-8.0
2002-03	ति1	5744.5	199.9	8.2	3.5	25.4
	ति2	5683.8	115.0	9.4	2.0	1.1
	ति3	6505.9	-88.5	5.7	-1.4	-11.7
	ति4	6611.4	-48.0	7.9	-0.7	23.1
2003-04	ति1	6287.0	179.0	9.4	2.8	-3.9
	ति2	6315.4	-55.1	11.1	-0.9	-26.9
	ति3	7481.1	135.0	15.0	1.8	22.9
	ति4	7462.8	1.9	12.9	0.0	5.9

ए3: वर्तमान मूल्य पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)						
वर्ष	तिमाही	बाज़ार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	ति1	7353.6	-117.4	17.0	-1.6	-28.2
	ति2	7599.4	72.9	20.3	1.0	20.9
	ति3	8575.6	99.4	14.6	1.2	13.9
	ति4	8893.5	-306.4	19.2	-3.4	-4.5
2005-06	ति1	8369.9	150.3	13.8	1.8	26.3
	ति2	8553.4	-101.7	12.6	-1.2	-18.3
	ति3	9762.3	-169.3	13.8	-1.7	-22.6
	ति4	10248.2	-135.7	15.2	-1.3	12.6
2006-07	ति1	9522.6	-268.9	13.8	-2.8	-36.4
	ति2	10041.6	56.1	17.4	0.6	10.6
	ति3	11393.1	28.0	16.7	0.2	12.1
	ति4	11989.8	-118.8	17.0	-1.0	1.0
2007-08	ति1	11264.8	-319.7	18.3	-2.8	-2.9
	ति2	11508.0	-377.9	14.6	-3.3	-29.6
	ति3	13216.5	-61.0	16.0	-0.5	-4.9
	ति4	13881.6	126.1	15.8	0.9	12.9
2008-09	ति1	13334.6	130.9	18.4	1.0	21.8
	ति2	13661.8	571.8	18.7	4.2	44.1
	ति3	14652.9	-296.9	10.9	-2.0	-16.4
	ति4	14651.3	100.4	5.5	0.7	-3.3
2009-10	ति1	14326.5	-280.4	7.4	-2.0	-41.5
	ति2	14976.5	-449.1	9.6	-3.0	-77.7
	ति3	17004.9	-216.1	16.1	-1.3	3.4
	ति4	18470.5	907.6	26.1	4.9	21.1
2010-11	ति1	17441.8	185.9	21.7	1.1	15.0
	ति2	17869.8	-323.8	19.3	-1.8	4.3
	ति3	20451.6	-243.1	20.3	-1.2	-0.8
	ति4	22078.0	683.4	19.5	3.1	-6.2

ए3: वर्तमान मूल्य पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (समाप्त)						
वर्ष	तिमाही	बाजार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	ति1	20435.0	-43.8	18.6	-0.2	-4.8
	ति2	20294.7	-495.3	16.7	-2.4	1.4
	ति3	22448.5	335.5	15.2	1.5	17.5
	ति4	24185.1	-92.6	13.2	-0.4	21.2
2012-13	ति1	22977.4	135.3	12.4	0.6	7.0
	ति2	24201.9	-353.6	19.3	-1.5	3.6
	ति3	25207.2	986.7	12.3	3.9	23.6
	ति4	27053.6	457.3	11.9	1.7	19.2
2013-14	ति1	25495.2	-80.0	11.0	-0.3	-8.6
	ति2	27542.1	551.6	13.8	2.0	27.1
	ति3	28893.2	100.7	14.6	0.3	-24.0
	ति4	30404.8	571.6	12.4	1.9	3.4
2014-15	ति1	29135.9	-1092.0	14.3	-3.7	-27.8
	ति2	30565.8	-463.7	11.0	-1.5	-33.6
	ति3	31753.3	795.1	9.9	2.5	24.3
	ति4	32996.3	602.3	8.5	1.8	1.2
2015-16	ति1	32202.8	281.7	10.5	0.9	44.8
	ति2	33264.7	381.4	8.8	1.1	31.3
	ति3	34444.8	115.2	8.5	0.3	-25.3
	ति4	36908.0	747.2	11.9	2.0	3.7
2016-17	ति1	35549.4	-175.1	10.4	-0.5	-13.6
	ति2	36757.9	-44.1	10.5	-0.1	-12.2
	ति3	38020.4	-554.2	10.4	-1.5	-18.7
	ति4	41509.5	1742.2	12.5	4.2	21.6
2017-18	ति1	38837.8	286.7	9.3	0.7	14.0
	ति2	40223.4	548.7	9.4	1.4	17.1

*: जीडीपी वृद्धि में अंशदान = $((SD_t - SD_{t-1}) / (Y_t - Y_{t-1})) * 100$

टिप्पणी : वर्ष 1997-98 से 2003-04 के आंकड़े आधार-वर्ष 1999-00 की कीमतों पर, 2004-05 से 2010-11 के आंकड़े आधार-वर्ष 2004-05 की कीमतों पर और उसके बाद के आंकड़े आधार-वर्ष 2011-12 की कीमतों पर आधारित हैं।

स्रोत: सीएसओ

ए4: स्थिर मूल्य पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)						
वर्ष	तिमाही	बाजार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	जीडीपी में वृद्धि (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	ति1	4011.3	99.4	3.3	2.5	-18.5
	ति2	3755.2	93.1	4.8	2.5	-11.7
	ति3	4616.5	114.4	3.5	2.5	-16.9
	ति4	4734.4	117.3	4.6	2.5	-12.3
1998-99	ति1	4265.4	141.5	6.3	3.3	16.6
	ति2	4048.4	134.3	7.8	3.3	14.1
	ति3	4870.5	161.6	5.5	3.3	18.6
	ति4	4993.2	165.7	5.5	3.3	18.7
1999-00	ति1	4596.6	-186.1	7.8	-4.0	-98.9
	ति2	4368.0	-83.9	7.9	-1.9	-68.3
	ति3	5200.3	1.5	6.8	0.0	-48.6
	ति4	5355.5	9.8	7.3	0.2	-43.0
2000-01	ति1	4837.5	-15.8	5.2	-0.3	70.7
	ति2	4657.8	132.6	6.6	2.8	74.7
	ति3	5397.8	64.5	3.8	1.2	31.9
	ति4	5414.0	-156.4	1.1	-2.9	-284.1
2001-02	ति1	5023.1	-98.3	3.8	-2.0	-44.4
	ति2	4860.7	204.1	4.4	4.2	35.2
	ति3	5737.4	37.2	6.3	0.6	-8.0
	ति4	5745.3	-97.8	6.1	-1.7	17.7
2002-03	ति1	5277.8	-91.2	5.1	-1.7	2.8
	ति2	5120.5	106.3	5.3	2.1	-37.6
	ति3	5850.6	-140.3	2.0	-2.4	-156.8
	ति4	5922.6	-177.0	3.1	-3.0	-44.7
2003-04	ति1	5536.5	-68.9	4.9	-1.2	8.6
	ति2	5535.2	28.6	8.1	0.5	-18.7
	ति3	6506.7	100.8	11.2	1.5	36.7
	ति4	6448.8	-76.9	8.9	-1.2	19.0

ए4: स्थिर मूल्य पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (जारी)						
वर्ष	तिमाही	बाज़ार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	जीडीपी में वृद्धि (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	ति1	7500.4	-129.3	8.3	-1.7	-81.0
	ति2	7580.8	57.4	8.8	0.8	3.2
	ति3	8503.9	87.0	5.9	1.0	-17.8
	ति4	8837.0	-266.7	10.3	-3.0	-20.8
2005-06	ति1	8192.3	105.1	9.2	1.3	33.9
	ति2	8220.9	-147.2	8.4	-1.8	-32.0
	ति3	9267.0	-197.6	9.0	-2.1	-37.3
	ति4	9752.3	-133.2	10.4	-1.4	14.6
2006-07	ति1	8799.0	-313.7	7.4	-3.6	-69.0
	ति2	9062.7	-30.2	10.2	-0.3	13.9
	ति3	10145.2	-49.0	9.5	-0.5	16.9
	ति4	10708.0	-157.1	9.8	-1.5	-2.5
2007-08	ति1	9750.1	-465.1	10.8	-4.8	-15.9
	ति2	9891.0	-410.1	9.1	-4.1	-45.9
	ति3	11215.3	-210.9	10.5	-1.9	-15.1
	ति4	11653.1	-78.7	8.8	-0.7	8.3
2008-09	ति1	10538.3	-308.2	8.1	-2.9	19.9
	ति2	10557.2	171.0	6.7	1.6	87.2
	ति3	11387.4	-351.9	1.5	-3.1	-81.9
	ति4	11680.6	201.3	0.2	1.7	1018.4
2009-10	ति1	11064.6	-447.1	5.0	-4.0	-26.4
	ति2	11291.8	-534.3	7.0	-4.7	-96.0
	ति3	12322.4	-423.5	8.2	-3.4	-7.7
	ति4	13229.6	374.2	13.3	2.8	11.2
2010-11	ति1	12203.5	-126.7	10.3	-1.0	28.1
	ति2	12384.8	-444.5	9.7	-3.6	8.2
	ति3	13639.8	-810.9	10.7	-5.9	-29.4
	ति4	14595.7	-98.3	10.3	-0.7	-34.6

ए4: स्थिर कीमतों पर तिमाही जीडीपी में सांख्यिकीय विसंगति (समाप्त)						
वर्ष	तिमाही	बाजार मूल्य पर जीडीपी (₹ बिलियन)	विसंगतियाँ (₹ बिलियन)	जीडीपी में वृद्धि (%)	जीडीपी में सां. विसंगति का हिस्सा (%)	जीडीपी वृद्धि में अंशदान*
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	ति1	21028.6	-103.6	8.3	-3.6	-34.8
	ति2	20428.7	-504.4	6.7	-3.8	-7.5
	ति3	22251.4	383.4	6.2	-3.4	38.2
	ति4	23654.6	-71.6	5.6	1.8	45.4
2012-13	ति1	22052.2	168.0	4.9	0.8	26.5
	ति2	21959.5	-1156.7	7.5	-5.3	-42.6
	ति3	23447.7	1128.8	5.4	4.8	62.3
	ति4	24670.8	276.2	4.3	1.1	34.2
2013-14	ति1	23474.0	91.3	6.4	0.4	-5.4
	ति2	23570.8	-391.4	7.3	-1.7	47.5
	ति3	24980.0	-5.5	6.5	0.0	-74.0
	ति4	25989.0	-25.1	5.3	-0.1	-22.9
2014-15	ति1	25337.9	-548.2	7.9	-2.2	-34.3
	ति2	25647.5	-381.0	8.8	-1.5	0.5
	ति3	26506.7	338.4	6.1	1.3	22.5
	ति4	27877.7	145.3	7.3	0.5	9.0
2015-16	ति1	27258.7	693.6	7.6	2.5	64.6
	ति2	27701.0	532.1	8.0	1.9	44.5
	ति3	28427.4	151.6	7.2	0.5	-9.7
	ति4	30422.9	300.8	9.1	1.0	6.1
2016-17	ति1	29418.5	376.0	7.9	1.3	-14.7
	ति2	29788.2	365.8	7.5	1.2	-8.0
	ति3	30407.6	-409.8	7.0	-1.3	-28.3
	ति4	32284.3	506.9	6.1	1.6	11.1
2017-18	ति1	31101.5	330.5	5.7	1.1	-2.7
	ति2	31656.6	592.7	6.3	1.9	12.1

*: जीडीपी वृद्धि में अंशदान = $((SD_t - SD_{t-1}) / (Y_t - Y_{t-1})) * 100$

टिप्पणी : वर्ष 1997-98 से 2003-04 के आंकड़े आधार-वर्ष 1999-00 की कीमतों पर, 2004-05 से 2010-11 के आंकड़े आधार-वर्ष 2004-05 की कीमतों पर और उसके बाद के आंकड़े आधार-वर्ष 2011-12 की कीमतों पर आधारित हैं।

स्रोत: सीएसओ

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	51
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	52
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	53
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	54
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	55
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	55
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	56
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	57
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	58
9	कुल चलनिधि राशियां	58
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	59
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	59
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	60
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	60
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	61
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	62
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	63
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	64
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	65
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	65
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	65
21	थोक मूल्य सूचकांक	66
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	69
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	69
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	70
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	70
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	71
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	72
28	वाणिज्यिक पत्र	72
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	72
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	73

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	74
32	विदेशी मुद्रा भंडार	74
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	74
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	75
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	75
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर)	76
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	76
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	77
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	78
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	79
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	80
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	81
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	82
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	83
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	84
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	85
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	86
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	87

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।
 - = शून्य/नगण्य
 प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंश = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2016-17	2016-17		2017-18	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.1	7.6	6.8	5.6	6.1
1.1.1 कृषि	6.3	2.5	4.1	2.3	1.7
1.1.2 उद्योग	8.7	9.0	6.5	1.5	6.9
1.1.3 सेवाएं	6.7	8.2	7.4	7.8	6.6
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.0	9.8	9.5	8.5	6.0
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.1	7.4	3.0	1.6	4.7
	2016-17	2016		2017	
	1	नव.	दिसं.	नव.	दिसं.
	1	1	2	3	4
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.6	5.1	2.4	8.4	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.3	15.6	15.7	3.0	4.1
2.1.2 ऋण	4.5	6.2	6.0	9.3	11.1
2.1.2.1 गैर-खादयान्न ऋण	5.2	6.5	6.2	9.6	12.0
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	17.4	20.5	33.5	3.6	-6.4
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	-12.9	-16.8	-28.9	30.4	55.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.6	8.1	6.2	8.4	10.6
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	20.50	20.75	20.75	19.50	19.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.3	6.5	5.4	4.7	5.1
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.9	69.3	70.1	73.5	74.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	41.4	1.0	12.9	250.9	161.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.2	30.8	33.9	31.0	30.5
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.4	52.5	77.0	853.3	131.8
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.25	6.25
4.4 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.25	6.25
4.5 आधार दर	9.25/9.60	9.30/9.65	9.30/9.65	8.95/9.45	8.85/9.45
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.75/8.20	8.65/9.00	8.65/9.00	7.70/8.05	7.65/8.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.50/7.00	6.50/7.10	6.50/7.00	6.00/6.75	6.00/6.75
4.8 बचत जमा दर	4.00	4.00	4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारत औसत)	5.97	5.94	6.12	5.89	5.99
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.82	5.94	6.27	6.15	6.19
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.05	6.07	6.35	6.25	6.33
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.14	5.96	6.34	6.28	6.42
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफआईएमएमडीए)	7.00	6.30	6.63	7.25	7.51
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	64.84	68.46	67.95	64.73	63.93
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.25	72.39	71.62	76.72	76.39
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमेरिकी डालर 1-माह (%)	5.09	2.19	3.88	4.26	4.32
3-माह (%)	4.97	3.16	4.15	4.08	4.44
6-माह (%)	4.90	3.67	4.44	4.39	4.47
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.5	3.6	3.4	4.9	5.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.1	2.6	2.2	4.0	4.0
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.7	1.8	2.1	3.9	3.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.4	1.3	0.1	5.3	3.9
6.3.2 ईंधन और पावर	-0.3	2.1	4.2	8.8	9.2
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.3	2.0	2.5	2.6	2.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	0.5	11.9	1.5	20.8	21.0
7.2 निर्यात	5.4	2.6	6.5	30.1	12.5

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2016-17	2017		2018			
		जन.	दिसं. 29	जन. 5	जन. 12	जन. 19	जन. 26
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचालन में नोट	13,101.81	9,921.05	16,676.69	16,793.10	17,002.80	17,076.63	17,129.62
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.12	0.16	0.16	0.15	0.17	0.17	0.17
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	13,101.93	9,921.21	16,676.85	16,793.26	17,002.97	17,076.80	17,129.79
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	675.08	661.77	699.06	683.75	683.75	683.75	683.75
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	12,422.35	9,243.70	15,970.44	16,102.22	16,312.00	16,385.91	16,438.93
1.2.3 रुपया सिक्का	4.50	5.27	7.35	7.28	7.21	7.14	7.11
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	10.46	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	10,389.43	13,044.62	8,505.63	8,186.70	7,789.54	7,868.33	8,124.68
2.1.1.1 केंद्र सरकार	50.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	3,922.70	946.73	946.73	946.73	946.73	946.73
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,087.73	4,341.85	4,883.32	4,485.57	4,488.14	4,523.22	4,566.12
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	55.13	39.07	36.14	38.51	35.78	36.69	38.83
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18.92	16.66	18.48	19.15	19.40	19.38	18.91
2.1.1.7 अन्य बैंक	279.49	253.55	260.05	255.83	257.90	260.26	264.03
2.1.1.8 अन्य	4,897.74	4,469.36	2,359.47	2,439.48	2,040.17	2,080.62	2,288.63
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—
2.1.2 अन्य देयताएं	8,411.18	9,603.41	8,613.90	8,362.12	8,494.87	8,636.42	8,675.15
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,800.61	22,648.03	17,119.52	16,548.82	16,284.42	16,504.75	16,799.84
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.12	0.16	0.17	0.15	0.17	0.17	0.17
2.2.2 विदेश में रखे शेष	10,263.49	14,154.91	8,882.23	8,669.59	8,686.61	8,748.18	8,798.57
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.2 राज्य सरकारें	12.62	18.63	41.42	47.99	52.29	23.90	31.80
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	218.10	132.00	869.66	618.35	334.25	526.27	756.72
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	39.91	24.67	57.77	47.38	49.03	36.02	41.17
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	7,528.11	7,630.87	6,558.20	6,468.81	6,463.54	6,469.07	6,469.59
2.2.6 अन्य आस्तियां	738.26	686.79	710.08	696.56	698.53	701.14	701.82
2.2.6.1 सोना	613.19	601.10	635.74	621.75	621.75	621.75	621.75

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)	
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिपो दर				विक्रय	क्रय		
	1	2	3	4				5	6		7
दिसं. 1, 2017	-	117.99	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-117.44
दिसं. 2, 2017	-	247.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-247.29
दिसं. 4, 2017	30.21	401.59	-	375.35	0.02	-	-	-	-	-	-746.71
दिसं. 5, 2017	29.20	133.18	34.50	322.04	-	-3.38	-	-	-	-	-394.90
दिसं. 6, 2017	29.70	227.08	-	133.23	-	-2.31	-	-	-	-	-332.92
दिसं. 7, 2017	27.95	290.19	-	227.97	-	2.31	-	-	-	-	-487.90
दिसं. 8, 2017	126.67	182.76	22.65	28.50	11.80	-	-	-	-	-	-50.14
दिसं. 11, 2017	74.30	89.48	-	93.37	3.00	3.17	-	-	-	-	-102.38
दिसं. 12, 2017	36.15	205.06	124.00	117.33	-	-	-	-	-	-	-162.24
दिसं. 13, 2017	31.15	190.75	-	169.42	-	-1.10	-	-	-	-	-330.12
दिसं. 14, 2017	30.20	136.87	-	245.12	-	1.10	-	-	0.20	-	-350.49
दिसं. 15, 2017	167.89	41.23	219.75	-	96.61	-	-	-	-	-	443.02
दिसं. 16, 2017	117.07	37.40	-	-	293.40	-	-	-	-	-	373.07
दिसं. 18, 2017	240.22	39.19	556.13	-	22.75	0.70	-	-	-	-	780.61
दिसं. 19, 2017	248.94	138.56	510.06	-	1.00	0.90	-	-	-	-	622.34
दिसं. 20, 2017	101.75	82.92	200.04	-	0.76	1.51	-	-	-	-	221.14
दिसं. 21, 2017	40.10	81.16	-	185.11	16.30	-	-	-	-	-	-209.87
दिसं. 22, 2017	185.45	402.85	92.10	101.31	4.85	-	-	-	-	-	-221.76
दिसं. 26, 2017	107.75	97.81	342.55	-	-	-	-	-	-	-	352.49
दिसं. 27, 2017	254.80	81.45	30.75	-	8.85	-0.05	-	-	-	-	212.90
दिसं. 28, 2017	182.29	330.35	-	-	6.20	-	-	-	-	-	-141.86
दिसं. 29, 2017	78.55	440.07	215.00	250.03	93.15	2.77	-	-	-	-	-300.63
दिसं. 30, 2017	32.99	511.24	-	-	40.25	-	-	-	-	-	-438.00

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	12,351.00	463.00	864.00	5,647.00
1.1 क्रय (+)	71,764.00	4,997.00	2,570.00	6,008.00
1.2 विक्रय (-)	59,413.00	4,534.00	1,706.00	361.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	822.16	34.89	60.55	371.46
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	12,351.00	8,037.00	18,017.00	23,664.00
(बिलियन ₹)	822.17	535.03	1,184.25	1,555.71
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	10,835.00	586.00	30,615.00	29,099.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	582.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	10,456.00	2,498.00	0.00	0.00
1.2 विक्रय (-)	10,456.00	1,916.00	0.00	0.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	-438.00	0.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 दिसंबर 2017 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	3,308	260	3,048
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	6,648	140	6,508
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	21,480	2,723	18,757
4. 1 वर्ष से अधिक	786	0	786
कुल (1+2+3+4)	32,222	3,123	29,099

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2016-17	2017						2018
		जन. 20	अग. 18	सितं. 29	अक्तू. 27	नव. 24	दिसं. 22	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	19.3	–	3.5	194.8	–	5.5	4.9	–
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	14.8	12.3	18.1	19.3	19.4	17.9	20.8	9.8
4 अन्य								
4.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	34.1	12.3	21.5	214.1	19.4	23.3	25.6	9.8

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2016-17	2016	2017		
			दिसं. 23	नव. 24	दिसं. 8
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	12,641.2	7,858.6	15,815.5	16,059.6	16,159.9
1.1 संचलन में नोट	13,101.8	9,185.9	16,344.5	16,570.3	16,717.7
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	243.4	238.7	248.2	248.2	248.5
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	711.4	1,573.5	784.7	766.3	813.7
2 जनता की जमा राशियां	14,178.3	12,087.1	12,495.2	12,574.1	12,927.4
2.1 बैंकों के पास मांग जमा राशियां	13,967.4	11,934.5	12,266.0	12,341.8	12,698.5
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	210.9	152.6	229.2	232.3	228.9
3 एम₁ (1+2)	26,819.6	19,945.7	28,310.7	28,633.7	29,087.3
4 डाकघर बचत बैंक जमा राशियां	920.6	937.5	968.8	968.8	968.8
5 एम₂ (3+4)	27,740.2	20,883.2	29,279.6	29,602.6	30,056.2
6 बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां	101,099.8	100,112.1	103,162.4	104,153.9	103,638.0
7 एम₃ (3+6)	127,919.4	120,057.8	131,473.1	132,787.6	132,725.3
8 कुल डाकघर जमा राशियां	2,562.1	2,549.6	2,717.2	2,717.2	2,717.2
9 एम₄ (7+8)	130,481.4	122,607.4	134,190.3	135,504.8	135,442.5

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		दिसं. 23	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,566.1	38,111.9	40,039.7	41,045.3	39,391.7
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	6,208.1	36.6	4,474.1	5,287.0	3,868.4
1.1.1 सरकार पर दावे	7,512.0	7,788.8	6,603.4	6,564.8	6,552.1
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	7,499.4	7,751.8	6,574.3	6,529.9	6,531.3
1.1.1.2 राज्य सरकारें	12.6	36.9	29.0	34.9	20.8
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	1,303.9	7,752.1	2,129.2	1,277.8	2,683.7
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,303.5	7,751.7	2,128.8	1,277.4	2,683.3
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	32,358.0	38,075.2	35,565.6	35,758.2	35,523.3
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	84,114.9	78,653.9	85,124.7	85,986.7	86,701.7
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	72.9	54.4	80.6	77.0	86.9
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	84,042.0	78,599.6	85,044.1	85,909.7	86,614.7
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	78,414.7	73,173.9	79,347.1	80,271.8	80,966.2
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,548.9	5,367.6	5,609.1	5,551.3	5,562.2
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	78.4	58.0	87.9	86.5	86.3
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	25,582.3	25,385.2	27,206.6	27,108.6	27,221.9
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	23,972.1	24,437.2	25,930.3	25,832.3	25,945.6
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	23,974.1	24,439.2	25,932.2	25,834.3	25,947.5
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,610.2	948.0	1,276.3	1,276.3	1,276.3
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	246.2	255.7	255.7	256.0
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	20,594.8	22,339.3	21,153.6	21,608.6	20,846.0
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,469.5	8,853.4	8,632.3	8,557.9
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,261.3	12,869.8	12,300.2	12,976.3	12,288.1
एम₃ (1+2+3+4-5)	127,919.4	120,057.8	131,473.1	132,787.6	132,725.3

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
	1	दिसं. 23	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	26,819.6	19,945.7	28,310.7	28,633.7	29,087.3
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	71,695.2	64,345.6	74,107.4	74,868.6	75,094.1
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	129,706.3	122,002.5	133,278.1	134,549.7	134,544.0
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	12,641.2	7,858.6	15,815.5	16,059.6	16,159.9
1.2 निवासियों की कुल जमाराशियां	113,690.9	110,601.0	114,036.3	115,085.8	114,935.6
1.2.1 मांग जमाराशियां	13,967.4	11,934.5	12,266.0	12,341.8	12,698.5
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,723.5	98,666.5	101,770.3	102,744.0	102,237.2
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,875.6	44,399.9	45,796.6	46,234.8	46,006.7
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,479.4	1,273.8	1,238.9	1,281.5
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,847.9	54,266.6	55,973.7	56,509.2	56,230.4
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	152.6	229.2	232.3	228.9
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,163.2	3,390.3	3,197.1	3,171.9	3,219.5
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	129,185.0	123,446.2	132,496.5	134,346.1	133,304.8
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,566.1	38,111.9	40,039.7	41,045.3	39,391.7
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	36.6	4,474.1	5,287.0	3,868.4
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	32,358.0	38,075.2	35,565.6	35,758.2	35,523.3
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	90,618.9	85,334.3	92,456.8	93,300.9	93,913.1
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	72.9	54.4	80.6	77.0	86.9
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	90,546.0	85,280.0	92,376.2	93,223.9	93,826.2
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	6,462.5	6,587.5	7,250.5	7,218.2	7,108.2
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	246.2	255.7	255.7	256.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,819.8	23,353.3	25,536.0	25,340.8	25,495.2
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,437.2	25,930.3	25,832.3	25,945.6
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-152.3	-1,083.9	-394.3	-491.5	-450.4
2.4 पूंजी खाता	18,195.5	18,883.2	19,739.5	19,575.3	19,510.2
2.5 अन्य मदें (निवल)	5,353.9	6,160.0	5,270.5	5,817.6	5,001.7

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2016-17	2016	2017		
		दिसं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	129,706.3	122,002.5	133,013.3	133,278.1	134,544.0
2 डाकघर जमाराशियां	2,562.1	2,549.6	2,717.2	2,717.2	2,717.2
3 एन₁ (1 + 2)	132,268.3	124,552.1	135,730.5	135,995.4	137,261.2
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एन₂ (3 + 4)	132,297.7	124,581.4	135,759.8	136,024.7	137,290.6
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	317.9	314.0	313.6
7 एन₃ (5 + 6)	132,615.6	124,895.5	137,604.2

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		दिसं. 23	नव. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	9,432.1	16,600.2	16,825.9	16,973.6
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,622.7	4,680.6	4,669.1	4,790.6
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,087.7	4,311.6	4,365.9	4,360.7	4,476.7
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	152.6	229.2	232.3	228.9
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	19,004.8	14,207.4	21,510.0	21,727.3	21,993.1
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	3,115.3	-1,006.5	4,177.4	4,271.7	4,349.5
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	36.6	4,474.1	5,287.0	3,868.4
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	6,195.9	0.1	4,445.5	5,252.6	3,848.0
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	—	—	—	—	—
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	7,494.9	7,744.6	6,566.7	6,522.5	6,523.9
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	7,494.9	7,734.2	6,566.7	6,522.5	6,523.9
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	4.5	7.2	7.7	7.5	7.4
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,303.5	7,751.7	2,128.8	1,277.4	2,683.3
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	12.2	36.5	28.6	34.5	20.4
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-3,165.7	-1,097.5	-377.3	-1,092.4	394.2
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-3,165.7	-1,097.5	-377.3	-1,092.4	394.2
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	72.9	54.4	80.6	77.0	86.9
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	14.8	12.3	17.9	14.5	20.8
2.1.3.2 नाबाई को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	246.2	255.7	255.7	256.0
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,437.2	25,930.3	25,832.3	25,945.6
2.3.1 सोना	1,288.3	1,369.4	1,338.7	1,334.0	1,334.8
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,684.0	23,068.0	24,591.7	24,498.5	24,610.9
2.4 पूंजी खाता	7,512.8	8,443.9	8,150.1	7,980.3	7,890.8
2.5 अन्य मदें (निवल)	820.6	1,025.6	703.2	652.0	667.1

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2016-17	2016	2017				
		दिसं. 30	नव. 24	दिसं. 8	दिसं. 15	दिसं. 22	दिसं. 29
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	19,004.8	14,355.7	21,510.0	21,727.3	22,333.2	21,993.1	22,375.9
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	9,383.8	16,600.2	16,825.9	16,918.8	16,973.6	16,932.7
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,809.8	4,680.6	4,669.1	5,187.1	4,790.6	5,198.0
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	162.2	229.2	232.3	227.4	228.9	245.2
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	6,208.1	523.2	4,474.1	5,287.0	5,051.8	3,868.4	4,276.0
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-3,165.7	-1,468.6	-377.3	-1,092.4	-266.0	394.2	158.6
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	72.9	58.9	80.6	77.0	85.3	86.9	91.3
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,501.4	25,930.3	25,832.3	25,723.7	25,945.6	26,185.5
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	246.2	255.7	255.7	255.7	256.0	256.0
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,505.4	8,853.4	8,632.3	8,517.3	8,557.9	8,591.4

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		दिसं. 23	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	106,200.3	103,252.5	106,556.2	107,610.9	107,450.7
1.1.1 मांग जमाराशियां	12,814.4	10,785.3	11,132.3	11,210.5	11,568.0
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	93,385.9	92,467.2	95,423.8	96,400.4	95,882.7
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	42,023.6	41,610.2	42,940.7	43,380.2	43,147.2
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,479.4	1,273.8	1,238.9	1,281.5
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	51,362.2	50,856.9	52,483.1	53,020.2	52,735.5
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,163.2	3,390.3	3,197.1	3,171.9	3,219.5
स्रोत					
2.1 देशी ऋण	115,141.3	115,817.3	120,080.7	121,184.8	121,530.4
2.1.1 सरकार को ऋण	30,297.5	36,018.6	33,469.0	33,669.2	33,422.9
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	84,843.8	79,798.7	86,611.7	87,515.6	88,107.5
2.1.2.1 बैंक ऋण	78,414.7	73,173.9	79,347.1	80,271.8	80,966.2
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	77,875.4	72,123.3	78,603.4	79,584.1	80,301.8
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	44.2	95.6	84.3	98.6	105.9
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	12.2	31.4	19.4	16.6	16.9
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	6,372.9	6,497.8	7,160.9	7,128.6	7,018.6
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-152.3	-1,083.9	-394.3	-491.5	-450.4
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,983.5	1,379.5	1,855.7	1,769.1	1,840.4
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,376.3	1,445.6	1,392.1	1,409.8	1,400.8
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	759.5	1,017.9	857.9	850.7	890.0
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	8,867.0	6,807.0	5,429.0	6,122.5	4,798.3
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,087.7	4,311.6	4,365.9	4,360.7	4,476.7
2.3.2 उपलब्ध नकदी	613.6	1,397.9	685.8	669.4	715.8
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-3,165.7	-1,097.5	-377.3	-1,092.4	394.2
2.4 पूंजी खाता	10,441.0	10,197.6	11,347.7	11,353.3	11,377.7
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	4,051.6	4,700.1	4,014.5	4,679.7	3,830.4
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,877.6	4,068.3	3,894.0	5,552.5	4,099.0
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-62.4	-253.1	-254.4	-358.8	-230.0

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31, 2017 की स्थिति	2016	2017		
		दिसं. 23	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	30,309.6	36,050.0	33,488.4	33,685.8	33,439.8
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.6	1,237.1	1,059.4	1,072.0	1,095.5
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर	91.9	78.9	113.4	111.0	115.5
3.1 सरकारी उद्यम	567.3	496.7	717.8	723.6	727.9
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	51.8	43.7	42.2	42.1	42.9
3.3 अन्य					
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	1,118.5	1,170.1	1,133.0	1,080.7	1,062.8
4.1 सरकारी उद्यम	1,680.0	1,480.9	1,893.0	1,935.6	2,031.1
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	810.9	630.0	666.1	642.8	616.7
4.3 अन्य					
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत	134.0	895.9	903.4	768.5	549.4
5.1 म्यूचुअल फंड	844.3	649.2	770.3	752.4	776.7
5.2 वित्तीय संस्थाएं					

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति									
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
	2016-17	2016		2017		2016-17	2016		2017	
		दिसं.	नव.	दिसं.	दिसं.		दिसं.	नव.	दिसं.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	221	219	223	223	150	148	149	149		
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,397.7	2,349.1	2,203.3	2,196.5	2,330.7	2,275.6	2,152.1	2,145.7		
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,765.5	1,873.2	1,429.5	1,532.3	1,698.6	1,800.6	1,379.9	1,483.1		
1.2 बैंकों से उधार राशि	573.6	430.7	619.4	600.8	573.5	429.9	619.2	600.8		
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	58.6	45.2	154.4	63.4	58.6	45.2	153.0	61.8		
2 अन्य के प्रति देयताएं	118,405.4	117,516.3	118,977.0	121,753.8	115,376.9	114,505.7	115,897.2	118,655.6		
2.1 कुल जमाराशियां	110,485.7	108,578.8	110,896.5	112,971.8	107,576.6	105,686.2	107,948.3	110,018.8		
2.1.1 मांग	13,104.8	11,648.5	11,407.0	12,363.7	12,814.4	11,359.9	11,132.3	12,097.1		
2.1.2 मीयादी	97,381.0	96,930.3	99,489.5	100,607.9	94,762.2	94,326.3	96,815.9	97,921.6		
2.2 उधार	3,192.8	3,551.5	3,231.7	3,656.6	3,163.2	3,525.8	3,197.1	3,611.0		
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	4,726.9	5,386.0	4,848.9	5,125.5	4,637.1	5,293.8	4,751.9	5,025.8		
3 रिज़र्व बैंक से उधार	218.1	154.8	562.7	869.7	218.1	154.8	562.7	869.7		
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.2 अन्य	218.1	154.8	562.7	869.7	218.1	154.8	562.7	869.7		
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,869.3	5,903.3	5,191.3	5,701.8	5,701.3	5,695.7	5,051.7	5,561.5		
4.1 उपलब्ध नकदी	630.5	1,282.7	704.7	696.4	613.60	1,200.0	685.8	678.2		
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,238.8	4,620.6	4,486.7	5,005.4	5,087.7	4,495.8	4,365.9	4,883.3		
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	2,934.5	3,149.4	2,910.6	2,896.9	2,437.3	2,645.1	2,490.7	2,474.8		
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	1,898.0	2,065.3	1,855.5	2,031.6	1,700.1	1,855.3	1,677.6	1,842.5		
5.1.1 चालू खाते में	197.3	232.1	132.1	173.7	160.6	180.5	110.9	149.4		
5.1.2 अन्य खातों में	1,700.7	1,833.1	1,723.4	1,857.9	1,539.5	1,674.8	1,566.7	1,693.2		
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	296.9	279.0	527.6	312.1	77.0	69.9	344.4	142.5		
5.3 बैंकों को अग्रिम	380.4	321.4	250.9	293.8	379.5	319.9	249.9	286.5		
5.4 अन्य आस्तियां	359.1	483.7	276.6	259.3	280.7	400.0	218.8	203.3		
6 निवेश	31,161.1	36,689.2	34,449.8	34,490.0	30,309.6	35,808.3	33,488.4	33,527.3		
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	31,144.8	36,668.0	34,381.2	34,430.1	30,297.5	35,792.0	33,469.0	33,516.6		
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	16.4	21.2	68.6	60.0	12.2	16.3	19.4	10.7		
7 बैंक ऋण	80,817.8	76,312.1	81,802.9	84,871.3	78,414.7	74,100.6	79,347.1	82,359.2		
7क खाद्यान्न ऋण	652.4	1,224.4	935.2	776.1	539.3	1,061.7	743.8	584.6		
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	78,490.1	74,169.0	79,679.3	82,612.8	76,148.5	72,010.1	77,281.1	80,158.6		
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	263.5	224.0	198.7	210.4	246.0	209.6	182.6	190.9		
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,402.8	1,265.8	1,310.6	1,365.7	1,365.9	1,234.9	1,275.8	1,334.0		
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	248.6	241.6	230.3	258.6	246.4	238.9	228.1	256.2		
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	412.7	411.7	384.0	423.8	407.9	407.2	379.5	419.5		

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			दिसं. 23	नवं. 24		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	71,347	66,458	71,501	72,631	1.8	9.3
1.1 खाद्यान्न ऋण	400	669	356	238	-40.7	-64.5
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	70,947	65,790	71,145	72,393	2.0	10.0
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,924	9,113	9,882	9,981	0.6	9.5
1.2.2 उद्योग	26,800	25,791	26,041	26,341	-1.7	2.1
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,697	3,436	3,592	3,683	-0.4	7.2
1.2.2.2 मझौले	1,048	1,060	947	957	-8.7	-9.7
1.2.2.3 बड़े	22,055	21,295	21,502	21,701	-1.6	1.9
1.2.3 सेवाएं	18,022	15,794	17,593	18,119	0.5	14.7
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,104	1,021	1,145	1,152	4.3	12.8
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	179	180	169	179	0.2	-0.3
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	375	375	368	367	-2.0	-1.9
1.2.3.4 नौवहन	84	107	75	73	-13.0	-31.6
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,377	1,194	1,353	1,422	3.3	19.1
1.2.3.6 व्यापार	4,279	3,785	4,328	4,406	3.0	16.4
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	1,932	1,708	1,909	1,935	0.1	13.3
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,347	2,077	2,419	2,471	5.3	19.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,856	1,778	1,819	1,825	-1.7	2.6
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	3,910	3,221	3,603	3,682	-5.8	14.3
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	4,859	4,134	4,732	5,013	3.2	21.3
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	16,200	15,092	17,630	17,952	10.8	18.9
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	208	194	180	182	-12.4	-6.3
1.2.4.2 आवास	8,601	8,197	9,221	9,362	8.8	14.2
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	661	600	537	557	-15.8	-7.1
1.2.4.4 शयेरों और बाड़ों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	48	47	55	58	21.5	21.8
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	521	471	637	642	23.1	36.2
1.2.4.6 शिक्षा	701	713	717	704	0.4	-1.3
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,705	1,674	1,808	1,831	7.3	9.3
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,755	3,194	4,475	4,617	22.9	44.5
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	24,357	22,443	24,017	24,224	-0.5	7.9
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,909	9,081	9,844	9,932	0.2	9.4
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,020	8,194	8,953	9,066	0.5	10.6
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,697	3,436	3,592	3,683	-0.4	7.2
1.2अ.2.2 सेवाएं	5,322	4,759	5,361	5,383	1.1	13.1
1.2अ.3 आवास	3,683	3,575	3,701	3,727	1.2	4.3
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	189	179	160	169	-10.6	-5.5
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	604	608	597	592	-2.1	-2.7
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	6	6	3	3	-56.0	-54.3
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,546	5,120	5,421	5,493	-1.0	7.3
1.2अ.8 निर्यात ऋण	425	458	414	409	-3.8	-10.7

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक 2017-18	वर्ष-दर-वर्ष 2017
			दिसं. 23	नवं. 24		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,800	25,791	26,041	26,341	-1.7	2.1
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	345	342	326	334	-3.3	-2.3
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,455	1,289	1,389	1,439	-1.1	11.6
1.2.1 चीनी	327	285	265	270	-17.5	-5.4
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	184	167	189	194	5.7	16.4
1.2.3 चाय	35	36	47	48	35.1	32.2
1.2.4 अन्य	909	801	888	927	1.9	15.7
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	173	171	166	170	-1.6	-0.8
1.4 वस्त्र	1,963	1,866	1,949	2,007	2.2	7.6
1.4.1 सूती वस्त्र	964	897	967	1,002	4.0	11.7
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	23	20	24	25	6.4	22.4
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	204	195	228	235	15.5	20.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	773	753	730	745	-3.5	-1.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	107	101	107	109	2.1	8.4
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	105	99	105	106	0.7	6.5
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	326	339	308	310	-5.1	-8.8
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	596	490	466	471	-21.0	-4.0
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,724	1,444	1,549	1,598	-7.3	10.6
1.9.1 उर्वरक	335	242	240	244	-27.1	0.6
1.9.2 औषधि और दवाइयां	464	471	447	474	2.2	0.5
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	507	324	430	443	-12.7	36.6
1.9.4 अन्य	419	407	431	438	4.5	7.6
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	392	363	405	408	4.1	12.4
1.11 कांच और कांच के सामान	79	80	82	82	3.5	3.2
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	542	531	532	531	-2.2	-0.2
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,211	4,127	4,133	4,132	-1.9	0.1
1.13.1 लोहा और स्टील	3,192	3,118	3,223	3,223	0.9	3.4
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	1,018	1,009	910	910	-10.6	-9.8
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,496	1,470	1,503	1,514	1.2	3.0
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	336	341	347	350	4.2	2.7
1.14.2 अन्य	1,160	1,129	1,157	1,164	0.3	3.0
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	736	715	712	730	-0.8	2.0
1.16 रत्न और आभूषण	690	686	681	690	0.0	0.7
1.17 निर्माण	822	791	855	862	4.8	8.9
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,064	8,962	8,796	8,898	-1.8	-0.7
1.18.1 पावर	5,254	5,278	5,121	5,200	-1.0	-1.5
1.18.2 दूरसंचार	851	799	844	854	0.4	6.9
1.18.3 सड़क	1,800	1,798	1,707	1,703	-5.4	-5.3
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,160	1,087	1,124	1,140	-1.7	4.9
1.19 अन्य उद्योग	1,973	1,925	1,977	1,952	-1.1	1.4

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखनेवाले राज्य सहकारी बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति					
	2016-17	2016		2017		
		सितं. 30	अग. 25	सितं. 01	सितं. 15	सितं. 29
	1	2	3	4	5	6
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	29	30	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	527.8	444.5	515.4	534.4	535.8	530.9
2 मांग और मीयादी देयताएं						
2.1 मांग देयताएं	183.2	152.4	162.9	158.1	154.4	158.2
2.1.1 जमाराशियां						
2.1.1.1 अंतर-बैंक	45.0	43.1	41.9	37.7	37.4	40.5
2.1.1.2 अन्य	106.3	79.2	95.2	94.2	91.1	90.4
2.1.2 बैंकों से उधार	2.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	30.0	27.4	25.8	26.2	25.9	27.2
2.2 मीयादी देयताएं	947.6	834.2	848.3	870.3	873.5	868.5
2.2.1 जमाराशियां						
2.2.1.1 अंतर-बैंक	512.6	460.3	419.0	423.5	422.3	420.2
2.2.1.2 अन्य	421.5	365.2	420.2	440.2	444.7	440.5
2.2.2 बैंकों से उधार	4.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	9.2	8.6	6.4	6.6	6.4	7.7
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	517.2	436.4	444.4	432.4	434.6	464.0
4.1 मांग	180.4	137.1	168.4	155.6	156.9	162.9
4.2 मीयादी	336.8	299.3	276.0	276.9	277.7	301.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	66.6	43.2	47.0	45.8	46.0	44.6
5.1 उपलब्ध नकदी	3.7	2.6	2.9	3.0	3.3	2.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	62.9	40.6	44.1	42.9	42.8	41.8
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	17.5	6.9	6.3	7.3	6.9	9.8
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	329.8	282.4	312.1	531.2	310.1	311.4
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	254.4	239.6	216.2	211.9	207.8	205.0
9 बैंक ऋण (10.1+11)	458.7	434.9	473.9	471.1	466.7	465.4
10 अग्रिम						
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	458.6	434.8	473.9	471.1	466.7	465.4
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	777.0	721.6	724.0	725.9	730.5	741.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2016-17			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसं. 16	नव.17	दिसं. 17	दिसं. 16	नव.17	दिसं. 17	दिसं. 16	नव.17	दिसं. 17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	135.3	134.9	135.2	134.7	142.4	141.5	132.8	141.5	138.8	134.0	142.1	140.5
1.1 अनाज और उत्पाद	130.8	128.9	130.2	132.6	136.3	136.3	131.6	134.3	134.4	132.3	135.7	135.7
1.2 मांस और मछली	137.9	140.1	138.7	137.3	142.5	143.8	138.2	142.1	142.6	137.6	142.4	143.4
1.3 अंडा	128.9	130.7	129.6	131.6	140.5	145.2	134.9	146.7	145.9	132.9	142.9	145.5
1.4 दूध और उत्पाद	135.2	132.4	134.1	136.3	141.5	141.9	133.1	139.5	139.5	135.1	140.8	141.0
1.5 तेल और चर्बी	120.3	112.0	117.3	121.6	121.6	122.9	113.5	115.2	115.9	118.6	119.2	120.3
1.6 फल	138.1	132.8	135.6	135.6	147.3	147.2	129.3	136.4	135.0	132.7	142.2	141.5
1.7 सब्जी	139.2	144.8	141.1	127.5	168.0	161.1	121.1	185.2	163.2	125.3	173.8	161.8
1.8 दाल और उत्पाद	165.6	170.3	167.2	167.9	135.8	133.8	170.3	122.2	119.8	168.7	131.2	129.1
1.9 चीनी और उत्पाद	112.1	114.9	113.0	113.8	122.5	121.9	115.5	123.9	120.7	114.4	123.0	121.5
1.10 मसाले	135.1	143.8	138.0	137.5	136.0	135.8	145.5	138.3	139.7	140.2	136.8	137.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	128.1	122.4	125.7	129.1	131.9	131.1	123.1	125.4	125.7	126.6	129.2	128.8
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	141.7	139.2	140.5	143.6	151.4	151.4	140.9	146.0	146.3	142.3	148.9	149.0
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	140.1	144.2	141.2	142.4	152.1	153.2	145.0	156.2	157.0	143.1	153.2	154.2
3 कपड़ा और जूते	137.9	127.8	133.9	139.7	147.3	147.1	128.8	133.5	134.0	135.4	141.8	141.9
3.1 कपड़ा	138.6	128.9	134.8	140.4	148.2	148.0	130.0	135.0	135.6	136.3	143.0	143.1
3.2 जूते	133.7	121.7	128.7	135.2	141.5	141.9	122.2	125.4	125.6	129.8	134.8	135.1
4 आवास	--	128.0	128.0	--	--	--	128.5	138.6	139.1	128.5	138.6	139.1
5 ईंधन और लाइट	130.1	116.4	124.9	132.0	141.1	142.6	117.8	125.7	126.8	126.6	135.3	136.6
6 विविध	125.0	120.6	122.9	126.3	131.7	131.8	121.4	124.9	125.1	123.9	128.4	128.6
6.1 घरेलू सामान और सेवा	131.3	124.3	128.0	132.9	139.4	139.4	125.0	128.8	129.3	129.2	134.4	134.6
6.2 स्वास्थ्य	128.1	121.6	125.6	129.7	135.8	136.2	122.3	127.4	128.2	126.9	132.6	133.2
6.3 परिवहन और संचार	117.4	112.8	114.9	118.6	121.6	122.0	113.7	115.3	115.3	116.0	118.3	118.5
6.4 मनोरंजन	125.9	121.0	123.2	127.3	133.7	133.4	121.8	125.1	125.6	124.2	128.9	129.0
6.5 शिक्षा	132.3	131.1	131.6	134.2	141.5	141.0	132.3	136.6	136.7	133.1	138.6	138.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	121.7	120.3	121.1	121.9	128.1	127.8	119.9	124.9	124.6	121.1	126.8	126.5
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	132.4	127.9	130.3	132.8	140.0	139.8	127.6	134.8	134.1	130.4	137.6	137.2

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2016-17	2017		
				दिसं.	नव.	
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	276	275	288	286
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	870	876	905	900
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	875	881	910	906

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2016-17	2016		2017	
		दिसं.	नव.	दिसं.	नव.
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	29,665	27,754	29,399	28,763	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42,748	40,289	39,332	37,270	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2017			
			दिसं.	अक्तू.	नवं.(अ).	दिसं.(अ).
1 सभी पण्य	100.000	111.6	111.7	115.6	116.3	115.7
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	128.9	126.8	133.9	135.6	131.7
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	140.3	137.6	148.0	150.6	144.1
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	152.0	157.5	143.1	141.7	140.8
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	138.7	120.5	177.1	188.8	162.2
1.1.1.3 दूध	4.440	134.3	135.0	140.2	139.9	140.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	133.0	132.0	135.9	137.4	134.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	140.5	140.6	124.9	126.3	128.2
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	150.5	153.1	139.0	140.4	141.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	122.2	119.4	118.5	116.9	119.0
1.1.2.1 फाइबर	0.839	117.1	113.4	112.8	112.9	119.0
1.1.2.2 तिलहन	1.115	136.0	130.0	128.0	127.1	129.2
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	114.9	114.2	112.1	108.8	106.5
1.1.2.4 फूल	0.204	137.4	135.1	151.8	154.8	184.0
1.1.3 खनिज	0.833	113.1	113.8	122.3	129.3	122.3
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	98.4	97.0	109.1	118.3	109.1
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	164.4	172.4	168.5	168.0	168.5
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.1	75.7	74.6	74.5	78.1
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	86.3	88.4	93.8	95.0	96.5
1.2.1 कोल	2.138	109.0	107.0	118.3	117.6	118.3
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	108.2	101.4	135.5	135.5	135.5
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	110.5	110.7	110.7	110.7	110.7
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	90.2	88.8	112.5	95.9	113.5
1.2.2 खनिज तेल	7.950	73.3	76.6	82.4	84.6	87.0
1.2.3 बिजली	3.064	104.2	106.2	106.1	106.1	106.1
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	110.7	111.1	113.7	113.9	114.0
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	125.4	127.7	128.2	127.9	127.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.1	141.4	133.0	132.9	135.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	127.7	126.6	130.5	125.9	131.1
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	120.3	119.5	118.8	119.4
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	107.0	110.1	108.5	110.1	111.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	132.3	134.6	143.8	142.4	141.6
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	136.2	141.6	138.5	137.4	137.2
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	114.6	110.5	112.2	112.0	111.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	127.0	128.0	128.4	128.8	128.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	124.8	125.7	131.9	130.8	124.5
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	125.5	125.9	126.5	126.5	127.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	137.1	146.8	128.0	128.0	132.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	125.9	122.5	132.2	131.5	128.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	124.5	127.2	118.4	119.6	121.5
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	126.3	126.7	128.5	127.6	127.1
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.2	141.4	141.2	138.7	139.1
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	165.4	163.2	150.5	150.6	150.2
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	116.1	117.0	118.9	119.5	119.7
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.3	115.1	114.1	114.0	113.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	114.2	114.1	117.8	118.6	118.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	121.8	122.0	127.0	128.3	130.7
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	141.6	142.8	149.9	155.3	152.1
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	141.6	142.8	149.9	155.3	152.1
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	111.2	110.9	112.7	113.5	113.0
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	103.3	102.9	104.7	104.9	105.4
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	120.9	120.2	122.2	124.6	122.2
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	107.1	106.5	108.4	107.7	108.2
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	121.7	122.5	124.5	124.4	124.1
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.0	142.2	143.0	141.1	137.9
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	112.9	114.7	116.8	116.5	117.9
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	131.0	132.5	138.0	137.5	138.9
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	133.9	134.7	136.9	138.2	138.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	123.3	126.7	140.8	135.7	139.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2016-17	2016	2017			
		1	2	दिसं.	अक्तू.	नव.(अ).	दिसं.(अ).
				3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद	0.535	122.6	120.5	120.4	119.5	120.3	
1.3.6.1 चमड़े की ट्रेनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाया	0.142	119.9	116.2	111.5	110.8	110.0	
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	132.3	132.1	133.5	131.0	133.0	
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	121.5	119.7	121.2	120.7	121.9	
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	129.8	129.6	131.7	131.6	130.3	
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.9	121.8	120.9	121.1	119.9	
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	127.3	126.7	130.7	130.7	131.0	
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	153.8	158.8	160.4	160.4	157.8	
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.3	140.5	138.4	137.7	129.7	
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	113.6	114.4	119.4	118.1	118.4	
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	117.7	118.0	121.5	121.5	122.4	
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	114.7	117.5	117.9	113.6	113.4	
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	105.9	105.6	117.6	117.3	117.1	
1.3.9 मुद्रण और रिकार्ड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	141.1	141.9	143.0	142.5	143.7	
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	141.1	141.9	143.0	142.5	143.7	
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	111.0	110.2	111.9	112.2	112.8	
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	104.7	104.4	110.2	111.2	113.1	
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	118.7	116.7	116.8	116.8	116.8	
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.7	112.5	112.7	112.6	112.9	
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एगोकेमिकल उत्पाद	0.454	116.8	115.5	112.9	114.0	114.6	
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.5	108.9	107.7	106.4	107.5	
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	113.7	114.1	115.2	115.3	115.3	
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	106.5	106.3	109.7	109.4	109.4	
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	94.1	93.2	96.8	98.6	99.0	
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	119.7	119.7	122.1	121.6	123.1	
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	119.7	119.7	122.1	121.6	123.1	
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.5	107.9	107.5	107.6	107.5	
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	101.4	101.4	99.8	100.4	100.4	
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	90.4	90.7	91.8	90.8	90.0	
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.3	114.0	113.9	113.9	113.9	
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	109.8	108.9	111.7	111.4	111.6	
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	116.6	114.7	117.1	116.6	116.9	
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	116.2	115.1	113.2	111.7	111.8	
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.3	87.8	90.5	92.0	94.3	
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	111.8	111.8	113.1	112.1	112.3	
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	110.6	109.5	113.3	113.0	113.3	
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	115.3	115.9	120.0	119.0	119.7	
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	117.4	119.0	116.7	117.3	116.8	
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	70.9	68.8	77.4	77.4	76.9	
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	91.1	92.7	100.7	101.0	102.0	
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	82.9	87.5	97.0	96.9	97.7	
1.3.14.2 मैटेलिक आयरन	0.653	79.4	81.6	98.6	99.2	100.4	
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	89.8	88.8	92.4	92.6	94.3	
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	85.3	86.0	91.7	92.5	91.4	
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	89.4	91.6	104.8	104.9	105.9	
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	85.6	86.3	93.8	93.7	95.5	
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	84.1	86.1	95.5	96.1	100.8	
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	107.8	111.2	116.4	118.0	120.0	
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	100.1	102.3	109.9	110.2	109.5	
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	102.2	101.2	104.5	104.5	106.1	
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.2	117.5	120.3	120.3	119.6	
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	105.1	105.6	109.6	111.1	110.9	
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	102.5	102.9	104.0	105.2	106.3	
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	109.2	111.5	126.6	128.7	126.1	
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	108.5	109.3	109.4	109.4	109.4	
1.3.15.4 धातु की फॉजिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	94.7	93.7	89.2	90.9	91.0	
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	111.5	110.5	94.3	97.8	97.7	
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	108.1	108.4	117.2	118.5	118.2	
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	108.3	108.2	111.2	110.3	110.7	
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.7	108.3	104.4	103.7	102.8	
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.3	127.3	127.4	127.4	127.4	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2016	2017		
			दिसं.	अक्तू.	नव.(अ).	दिसं.(अ).
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	104.1	104.1	115.7	115.7	116.0
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	100.0	98.6	103.5	101.6	102.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	103.1	102.3	106.2	106.5	107.8
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	139.8	137.2	136.1	136.1
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	104.3	103.5	104.3	102.3	102.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	96.6	95.0	113.6	113.6	113.6
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	108.2	108.3	110.2	110.0	110.0
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.0	104.9	106.5	106.3	105.9
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	120.4	120.8	115.6	116.4	116.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.8	118.3	117.2	114.2	114.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	99.7	101.4	106.0	107.3	107.3
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.5	107.2	111.9	111.0	111.2
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.4	119.9	121.7	121.7	121.5
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	104.4	103.8	108.1	106.7	108.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	107.9	108.3	109.0	109.4	109.2
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.1	104.1	101.4	101.3	101.8
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	114.3	114.7	115.7	115.2	115.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	106.6	107.7	108.3	108.7	109.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	104.5	106.8	110.2	110.2	109.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	77.8	74.0	79.1	79.5	79.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	103.2	103.3	107.4	109.0	107.8
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	124.9	126.1	127.6	128.7	127.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.3	112.2	112.7	112.8	113.1
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	100.1	99.9	98.9	98.7	99.8
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	79.6	76.7	74.0	74.7	74.0
1.3.18.12 खाद, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	116.9	121.2	121.3	122.8	121.8
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	116.2	115.7	118.2	119.2	119.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	115.8	116.7	120.2	120.7	119.6
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	73.7	72.4	71.0	71.0	70.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	110.4	110.1	110.3	110.4	110.3
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.4	113.6	112.2	112.0	111.9
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	107.2	106.3	108.2	108.6	108.6
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	107.7	109.3	110.5	110.8	110.6
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.7	158.8	158.8	158.8	158.7
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	100.6	102.5	104.7	104.7	104.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	102.8	104.7	105.8	106.1	106.0
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	118.0	117.6	120.1	120.1	120.1
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	116.5	115.1	119.7	119.0	119.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	114.1	113.6	122.1	122.5	120.1
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	114.1	113.6	122.1	122.5	120.1
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	119.7	112.6	108.4	108.7	111.7
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	118.4	110.7	105.7	105.8	109.0
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	158.0	160.6	185.2	181.2	181.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	124.7	126.5	126.1	125.9	125.3
1.3.22.4 खेल और खेलौने	0.005	125.2	123.2	125.8	126.3	128.5
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	143.3	144.5	155.3	157.6	157.6
2 खाद्य सूचकांक	24.378	134.7	133.9	140.6	142.1	137.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2015-16	2016-17	अप्रैल-नवंबर		नवंबर	
				2016-17	2017-18	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	114.7	120.0	117.8	121.6	115.9	125.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	97.3	102.5	95.5	98.4	106.2	107.4
1.2 विनिर्माण	77.63	115.9	121.0	119.3	123.0	115.7	127.5
1.3 बिजली	7.99	133.8	141.6	143.1	150.5	134.9	140.1
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	112.0	117.5	114.6	118.5	117.0	120.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	98.4	101.5	98.2	100.3	98.7	108.0
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	118.4	122.3	120.9	122.0	117.7	124.2
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	120.3	125.0	123.4	128.1	113.7	129.1
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.1	122.6	124.2	122.4	118.3	121.2
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	117.2	126.5	122.1	133.6	120.5	148.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-दिसं.			
	2017-18 (संशोधित अनुमान)	2017-18 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	संशोधित अनुमानों का प्रतिशत	
				2017-18	2016-17
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	15,157.7	10,136.2	9,345.7	66.9	67.9
1.1 कर राजस्व (निवल)	12,270.1	9,001.2	7,521.2	73.4	71.4
1.2 करेतर राजस्व	2,887.6	1,135.0	1,824.5	39.3	56.5
2 पूंजीगत प्राप्तियां	6,309.6	6,853.3	5,351.8	108.6	89.0
2.1 ऋण की वसूली	119.3	106.4	104.0	89.2	97.8
2.2 अन्य प्राप्तियां	725.0	537.4	235.3	74.1	41.6
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	5,465.3	6,209.5	5,012.5	113.6	93.9
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	21,467.4	16,989.6	14,697.5	79.1	74.3
4 राजस्व व्यय	18,369.3	14,623.6	12,888.6	79.6	74.5
4.1 ब्याज भुगतान	5,230.8	3,739.6	3,256.8	71.5	66.1
5 पूंजी व्यय	3,098.0	2,366.0	1,808.9	76.4	73.2
6 कुल व्यय (4+5)	21,467.4	16,989.6	14,697.5	79.1	74.3
7 राजस्व घाटा (4-1)	3,211.6	4,487.4	3,543.0	139.7	100.1
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	5,465.3	6,209.5	5,012.5	113.6	93.9
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	234.5	2,469.9	1,755.7	1,053.1	425.8

स्रोत: महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016		2017				
		दिसं. 30	नवं. 24	दिसं. 1	दिसं. 8	दिसं. 15	दिसं. 22	दिसं. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	275.3	230.0	291.0	197.5	224.3	179.0	274.3
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	218.4	265.9	221.3	194.8	203.0	224.1	182.7
1.3 राज्य सरकारें	146.2	691.9	894.9	894.9	864.9	959.0	1,004.0	1,022.0
1.4 अन्य	343.4	677.6	689.8	643.5	741.9	676.8	673.2	589.3
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	320.4	333.8	379.9	334.8	365.3	362.7	361.4
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	361.0	244.1	219.5	209.8	210.7	218.1	193.2
2.3 राज्य सरकारें	193.6	177.3	110.2	80.3	80.3	76.2	76.2	61.2
2.4 अन्य	120.9	81.8	172.5	116.2	189.0	117.8	122.0	108.7
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	682.1	341.2	364.6	336.6	340.8	332.6	339.8
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	561.8	586.2	609.6	550.4	602.0	555.9	606.0
3.3 राज्य सरकारें	26.3	26.2	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
3.4 अन्य	326.4	292.6	378.0	351.1	390.1	351.8	378.9	341.2
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,172.9	1,261.0	1,328.7	1,003.1	1,264.4	1,391.5	1,564.5
4.4 अन्य	5.1	4.7	4.6	4.7	5.1	5.4	5.7	4.7
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)	3,320.8	4,366.5	4,276.5	4,201.6	4,119.8	4,157.4	4,156.4	4,109.3

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार 'मध्यवर्ती' हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिस्थित राशि	प्राप्त बोलियाँ				स्वीकृत बोलियाँ				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
नवं. 29	70	49	1,113.44	70.32	44	70.00	70.32	140.32	98.49	6.1495		
दिसं. 6	70	47	1,418.87	52.00	44	70.00	52.00	122.00	98.49	6.1495		
दिसं. 13	70	47	867.86	180.51	38	70.00	180.51	250.51	98.49	6.1495		
दिसं. 20	70	50	434.01	122.37	28	70.00	122.37	192.37	98.48	6.1908		
दिसं. 27	70	47	568.79	70.58	18	70.00	70.58	140.58	98.48	6.1908		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
नवं. 29	20	30	64.68	0.02	16	20.00	0.02	20.02	96.98	6.2452		
दिसं. 6	20	43	82.75	—	21	20.00	—	20.00	96.97	6.2665		
दिसं. 13	20	43	84.00	35.01	26	20.00	35.01	55.01	96.95	6.3092		
दिसं. 20	20	50	111.99	0.01	24	20.00	0.01	20.01	96.94	6.3305		
दिसं. 27	20	35	86.78	—	8	20.00	—	20.00	96.94	6.3305		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
नवं. 29	20	40	105.73	—	7	20.00	—	20.00	94.11	6.2758		
दिसं. 6	20	40	88.83	—	2	20.00	—	20.00	94.13	6.2532		
दिसं. 13	20	48	68.32	—	31	20.00	—	20.00	94.04	6.3551		
दिसं. 20	20	39	69.48	—	18	20.00	—	20.00	94.00	6.4005		
दिसं. 27	20	48	91.78	—	18	20.00	—	20.00	93.98	6.4232		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	
		भारत औसत दरें	
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
दिसंबर	2, 2017	4.30-5.85	5.30
दिसंबर	4, 2017	5.05-6.05	5.83
दिसंबर	5, 2017	4.95-6.00	5.82
दिसंबर	6, 2017	4.95-6.00	5.80
दिसंबर	7, 2017	4.80-6.00	5.76
दिसंबर	8, 2017	4.80-6.05	5.90
दिसंबर	11, 2017	4.85-6.05	5.86
दिसंबर	12, 2017	4.85-6.05	5.82
दिसंबर	13, 2017	4.85-6.05	5.82
दिसंबर	14, 2017	4.85-6.10	5.83
दिसंबर	15, 2017	4.85-6.40	5.97
दिसंबर	16, 2017	5.00-6.25	5.68
दिसंबर	18, 2017	4.90-6.30	6.01
दिसंबर	19, 2017	4.90-6.25	6.02
दिसंबर	20, 2017	4.90-6.20	5.98
दिसंबर	21, 2017	4.90-6.25	5.94
दिसंबर	22, 2017	4.90-6.06	5.97
दिसंबर	26, 2017	4.85-6.50	5.96
दिसंबर	27, 2017	4.95-6.40	5.96
दिसंबर	28, 2017	4.95-6.80	6.00
दिसंबर	29, 2017	4.20-6.55	6.04
दिसंबर	30, 2017	5.00-6.50	6.04
जनवरी	1, 2018	4.80-6.25	5.92
जनवरी	2, 2018	4.80-6.07	5.87
जनवरी	3, 2018	4.80-6.00	5.84
जनवरी	4, 2018	4.90-6.00	5.80
जनवरी	5, 2018	4.70-6.02	5.87
जनवरी	6, 2018	4.50-6.10	5.83
जनवरी	8, 2018	4.80-6.05	5.87
जनवरी	9, 2018	4.90-6.05	5.86
जनवरी	10, 2018	4.90-6.00	5.89
जनवरी	11, 2018	4.90-6.15	5.88
जनवरी	12, 2018	4.90-6.10	5.90
जनवरी	15, 2018	4.90-6.05	5.91

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमाराशि प्रमाण-पत्र

मद	2016		2017		
	दिसं. 23	नवं. 10	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 22
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,468.0	1,216.5	1,218.9	1,196.6	1,269.8
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	16.7	61.8	135.1	122.2	185.2
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.00-6.49	6.18-6.65	6.18-6.61	6.21-6.65	6.21-7.75

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2016		2017		
	दिसं. 31	नवं. 15	नवं. 30	दिसं. 15	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,618.0	4,815.8	4,736.8	4,815.3	4,090.5
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	906.9	1,034.1	960.2	961.9	916.0
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.02-12.66	6.08-11.26	6.01-37.73	5.98-11.19	6.22-10.76

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016		2017				
		दिसं. 30	नवं. 24	दिसं. 1	दिसं. 8	दिसं. 15	दिसं. 22	दिसं. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	259.0	283.6	295.8	203.3	282.6	192.8	264.5	300.7
2 नोटिस मुद्रा	46.8	51.6	4.2	61.4	1.9	49.5	2.4	50.0
3 मीयादी मुद्रा	8.4	5.9	8.1	8.9	8.9	8.2	3.4	5.3
4 सीबीएलओ	1,700.2	2,360.2	2,132.7	2,748.5	2,099.4	2,373.0	1,972.4	2,691.9
5 बाजार रिपो	1,753.3	2,133.7	2,021.9	2,003.7	2,004.3	2,078.8	1,940.2	2,345.3
6 कापॉरिट बांड में रिपो	2.5	1.0	3.0	1.1	3.8	12.3	3.5	1.2
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	51,765	56,366	77,794	65,910	59,964	62,997	69,022
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,249.1	689.3	1,170.8	913.1	828.2	834.5	680.9	760.2
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	50.7	49.1	23.5	19.1	14.9	20.7	23.5	19.7
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	45.1	77.2	11.8	7.2	8.1	8.9	14.5	44.9
10.2 182-दिवसीय	11.8	8.8	4.6	7.1	11.7	3.7	0.5	4.4
10.3 364-दिवसीय	18.5	10.0	0.7	0.8	2.2	3.4	5.7	11.7
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13.8	42.6	—	—	—	—	—	—
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	1388.8	877.0	1,211.4	947.3	865.1	871.3	725.2	840.9
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	—	0.8	41.8	1.7	3.1	2.3	2.3	0.6

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2016-17		2016-17 (अप्रै.-दिसं.)		2017-18 (अप्रै.-दिसं.)*		दिसं. 2016		दिसं. 2017 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	116	303.6	74	247.7	143	369.7	5	13.8	18	22.4
1ए प्रीमियम	113	291.3	71	237.9	142	356.7	5	13.4	18	20.7
1.1 पब्लिक	105	280.7	69	234.8	130	324.5	5	13.8	16	13.9
1.1.1 प्रीमियम	102	270.4	66	226.3	129	313.8	5	13.4	16	13.1
1.2 राइट्स	11	22.9	5	13.0	13	45.1	—	—	2	8.5
1.2.1 प्रीमियम	11	20.9	5	11.7	13	42.9	—	—	2	7.6
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	16	295.5	12	271.6	5	41.2	2	32.7	1	2.3
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	16	295.5	12	271.6	5	41.2	2	32.7	1	2.3
3.1.1 पब्लिक	16	295.5	12	271.6	5	41.2	2	32.7	1	2.3
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	132	599.0	86	519.3	148	410.9	7	46.5	19	24.7
5.1 पब्लिक	121	576.1	81	506.4	135	365.8	7	46.5	17	16.2
5.2 राइट्स	11	22.9	5	13.0	13	45.1	—	—	2	8.5

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2016-17	2016		2017			
			दिसं.	अग.	सितं.	अक्तू.	नव.	दिसं.
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	बिलियन ₹	18,541.0	1,633.4	1,490.7	1,846.3	1,486.9	1,693.3	1,738.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	276,547.0	24,056.5	23,304.2	28,651.5	22,846.5	26,105.9	27,068.5
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,120.3	196.1	181.5	231.7	201.8	231.2	210.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	31,622.3	2,887.4	2,837.9	3,594.8	3,100.9	3,564.0	3,281.8
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	16,420.7	1,437.4	1,309.2	1,614.7	1,285.1	1,462.1	1,528.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	244,924.7	21,169.0	20,466.3	25,056.7	19,745.6	22,541.9	23,786.7
2 आयात	बिलियन ₹	25,668.2	2,349.5	2,306.3	2,443.8	2,439.0	2,622.8	2,690.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	382,740.9	34,602.5	36,053.8	37,923.2	37,475.7	40,436.2	41,883.3
2.1 तेल	बिलियन ₹	5,825.6	520.6	498.7	527.4	605.8	619.5	664.6
	अमेरिकी मिलियन डालर	86,865.7	7,667.0	7,795.7	8,184.8	9,309.1	9,550.9	10,345.5
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,842.6	1,828.9	1,807.6	1,916.4	1,833.1	2,003.3	2,026.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	295,875.2	26,935.5	28,258.1	29,738.4	28,166.6	30,885.3	31,537.8
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-7,127.2	-716.1	-815.6	-597.5	-952.1	-929.5	-951.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	-106,193.9	-10,546.0	-12,749.6	-9,271.7	-14,629.3	-14,330.3	-14,814.7
3.1 तेल	बिलियन ₹	-3,705.4	-324.5	-317.1	-295.8	-404.0	-388.3	-453.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	-55,243.4	-4,779.6	-4,957.8	-4,590.0	-6,208.2	-5,986.9	-7,063.7
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-3,421.9	-391.5	-498.4	-301.7	-548.1	-541.2	-497.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	-50,950.6	-5,766.4	-7,791.9	-4,681.8	-8,421.1	-8,343.4	-7,751.0

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2017			2018			
		जन. 27	दिसं. 22	दिसं. 29	जन. 5	जन. 12	जन. 19	जन. 26
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	24,642	25,936	26,177	26,067	26,294	26,431	26,535
	अमेरिकी मिलियन डालर	361,558	404,922	409,367	411,125	413,825	414,785	417,789
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	23,123	24,376	24,615	24,536	24,762	24,896	25,000
	अमेरिकी मिलियन डालर	339,211	380,680	385,104	387,149	389,834	390,769	393,744
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,263	1,335	1,335	1,306	1,306	1,306	1,306
	अमेरिकी मिलियन डालर	18,584	20,716	20,716	20,422	20,422	20,422	20,422
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,065	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
	बिलियन ₹	99	96	97	96	97	98	98
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,444	1,503	1,512	1,515	1,521	1,531	1,544
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	158	130	130	129	130	131	132
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,318	2,023	2,035	2,039	2,049	2,063	2,080

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2016-17	2016	2017		2016-17	2017-18
		दिसं.	नव.	दिसं.	अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	116,867	109,831	120,879	123,315	-15,065	5,040
1.1 एफसीएनआर (बी)	21,002	20,859	21,170	21,808	-24,456	806
1.2 एनआर (ई) आरए	83,213	77,513	86,870	88,135	7,824	3,703
1.3 एनआरओ	12,652	11,458	12,839	13,372	1,568	531

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2016-17	2016-17	2017-18	2016	2017	
		अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.	दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	35,612	30,616	24,169	1,990	-1,336	4,323
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	42,215	33,076	31,155	3,006	-709	4,724
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,220	47,880	48,201	4,630	4,307	6,290
1.1.1.1.1 ईक्विटी	44,701	36,735	36,759	3,451	3,191	4,923
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	5,900	5,762	6,488	248	18	55
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	30,417	24,467	22,663	2,411	2,327	2,995
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,161	5,615	6,789	687	741	1,769
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,223	890	818	104	104	104
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,343	9,102	9,016	1,020	1,020	1,020
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,176	2,043	2,426	158	97	347
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18,005	14,804	17,046	1,624	5,016	1,565
1.1.1.2.1 ईक्विटी	17,318	14,500	16,861	1,604	5,004	1,561
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	687	305	185	20	13	4
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	6,603	2,459	6,986	1,016	626	401
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	9,792	6,321	3,859	670	390	357
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,925	2,194	2,294	244	244	244
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,450	2,851	3,578	263	241	277
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	10,564	8,907	2,746	160	248	476
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	7,612	-3,187	19,838	-4,380	2,662	-351
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	7,766	-3,365	19,788	-4,371	2,731	-355
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	154	-178	-51	9	69	-4
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	43,224	27,429	44,008	-2,391	1,326	3,972

सं. 35: निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2016-17	2016	2017		
		दिसं.	अक्तू.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4	5
एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	8,170.7	619.1	811.3	830.8	981.4
1.1 जमाराशियां	283.8	21.6	22.0	22.2	31.6
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	92.9	6.3	6.2	5.6	10.9
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	443.6	37.5	33.2	43.1	31.0
1.4 उपहार	749.5	55.9	85.1	99.0	107.9
1.5 दान	8.8	1.3	0.6	0.4	0.4
1.6 यात्रा	2,568.0	201.8	279.9	271.0	361.6
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,169.5	160.2	201.1	235.2	255.3
1.8 चिकित्सा उपचार	17.3	1.5	2.0	2.9	2.7
1.9 विदेश में शिक्षा	1,536.4	120.3	167.4	136.3	147.0
1.10 अन्य	300.8	12.8	13.8	15.1	32.9

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (एनईईआर)

मद	2015-16	2016-17	2017		2018
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	74.75	74.65	75.22	77.22	76.88
1.2 रीर	112.08	114.51	114.69	122.57	122.03
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	76.45	76.38	76.98	79.16	79.01
2.2 रीर	114.44	116.44	116.43	124.69	124.45
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.52	66.86	67.39	68.07	67.57
1.2 रीर	122.71	125.17	125.13	131.96	129.87
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	101.00	100.00	100.79	101.81	101.07
2.2 रीर	98.04	100.00	99.97	105.43	103.75

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) – पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2016-17	2016	2017	
		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	729	67	63	56
1.2 राशि	16,247	1,023	2,012	905
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	37	5	6	1
2.2 राशि	5,738	1,778	1,027	400
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	766	72	69	57
3.2 राशि	21,985	2,801	3,039	1,305
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)				
	5.30	3.40	6.80	6.20
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.62	1.10	0.80	2.39
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-14.75	0.00-14.75	0.00-11.00	0.00-10.50

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	266,603	258,092	8,512	292,468	282,969	9,499
1 चालू खाता (1.1+1.2)	127,666	131,133	-3,467	145,566	152,793	-7,227
1.1 पण्य	67,411	93,023	-25,612	76,082	108,880	-32,798
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	60,255	38,110	22,146	69,484	43,913	25,571
1.2.1 सेवाएं	40,880	24,586	16,295	47,408	28,987	18,421
1.2.1.1 यात्रा	5,534	4,525	1,009	6,962	5,332	1,630
1.2.1.2 परिवहन	3,931	3,492	439	4,206	4,175	31
1.2.1.3 बीमा	577	357	220	635	542	92
1.2.1.4 जीएनआईई	146	156	-10	126	145	-19
1.2.1.5 विविध	30,692	16,055	14,637	35,479	18,793	16,686
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,644	994	17,650	19,290	1,325	17,965
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	8,249	8,008	241	9,084	9,559	-475
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,479	1,530	-51	1,321	1,574	-253
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	611	266	345	536	215	321
1.2.2 अंतरण	15,247	1,345	13,902	17,522	1,883	15,640
1.2.2.1 आधिकारिक	67	212	-146	108	245	-137
1.2.2.2 निजी	15,180	1,133	14,048	17,414	1,638	15,776
1.2.3 आय	4,128	12,179	-8,051	4,554	13,044	-8,490
1.2.3.1 निवेश आय	3,226	11,612	-8,386	3,524	12,480	-8,956
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	902	566	336	1,030	564	466
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	138,938	126,103	12,835	146,541	130,176	16,365
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	86,378	63,328	23,050	87,185	72,721	14,464
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	24,066	7,066	17,000	20,040	7,642	12,398
2.1.1.1 भारत में	18,064	4,081	13,983	18,973	4,288	14,685
2.1.1.1.1 इक्विटी	14,328	3,904	10,424	15,203	4,253	10,950
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	2,874	-	2,874	3,037	-	3,037
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	863	177	686	732	34	698
2.1.1.2 विदेश में	6,002	2,985	3,016	1,067	3,355	-2,288
2.1.1.2.1 इक्विटी	6,002	1,612	4,390	1,067	978	89
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	731	-731	0	781	-781
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	643	-643	0	1,595	-1,595
2.1.2 संविभाग निवेश	62,312	56,262	6,050	67,145	65,079	2,066
2.1.2.1 भारत में	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
2.1.2.1.1 एफआईआई	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	49,356	44,833	4,523	52,492	55,924	-3,432
2.1.2.1.1.2 ऋण	12,790	10,604	2,186	14,524	8,655	5,869
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	167	825	-658	128	500	-372
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	28,893	30,583	-1,690	33,429	30,585	2,843
2.2.1 बाह्य सहायता	1,014	1,133	-119	1,259	1,215	44
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	58	-43	14	70	-56
2.2.1.2 भारत को	999	1,075	-75	1,245	1,145	100
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6,154	7,542	-1,388	8,146	9,341	-1,195
2.2.2.1 भारत द्वारा	859	596	263	2,964	2,672	292
2.2.2.2 भारत को	5,295	6,946	-1,651	5,182	6,669	-1,487
2.2.3 भारत को अल्पावधि	21,726	21,908	-182	24,023	20,029	3,994
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	21,400	21,908	-508	23,614	20,029	3,585
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	326	0	326	409	0	409
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	15,881	22,487	-6,606	16,876	16,702	174
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	15,624	22,487	-6,862	16,790	16,702	88
2.3.1.1 आस्तियां	943	8,992	-8,049	2,566	4,936	-2,370
2.3.1.2 देयताएं	14,682	13,495	1,187	14,224	11,766	2,458
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13,611	11,523	2,088	12,187	11,476	711
2.3.2 अन्य	256	0	256	86	0	86
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	17	-17	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	7,785	9,688	-1,903	9,052	10,165	-1,114
3 भूल-चूक	-	857	-857	360	-	360
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	8,512	-8,512	0	9,499	-9,499
4.1 आईएमएफ	0	0	0	-	-	-
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	8,512	-8,512	-	9,499	-9,499

सं. 39: भारत का समय भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	17,852	17,282	570	18,802	18,192	611
1 चालू खाता (1.1+1.2)	8,549	8,781	-232	9,358	9,823	-465
1.1 पण्य	4,514	6,229	-1,715	4,891	7,000	-2,109
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,035	2,552	1,483	4,467	2,823	1,644
1.2.1 सेवाएं	2,737	1,646	1,091	3,048	1,864	1,184
1.2.1.1 यात्रा	371	303	68	448	343	105
1.2.1.2 परिवहन	263	234	29	270	268	2
1.2.1.3 बीमा	39	24	15	41	35	6
1.2.1.4 जीएनआईई	10	10	-1	8	9	-1
1.2.1.5 विविध	2,055	1,075	980	2,281	1,208	1,073
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,248	67	1,182	1,240	85	1,155
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	552	536	16	584	615	-31
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	99	102	-3	85	101	-16
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	41	18	23	34	14	21
1.2.2 अंतरण	1,021	90	931	1,126	121	1,005
1.2.2.1 आधिकारिक	4	14	-10	7	16	-9
1.2.2.2 निजी	1,017	76	941	1,120	105	1,014
1.2.3 आय	276	816	-539	293	839	-546
1.2.3.1 निवेश आय	216	778	-562	227	802	-576
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	60	38	22	66	36	30
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9,303	8,444	859	9,421	8,369	1,052
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,784	4,241	1,543	5,605	4,675	930
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,612	473	1,138	1,288	491	797
2.1.1.1 भारत में	1,210	273	936	1,220	276	944
2.1.1.1.1 इक्विटी	959	261	698	977	273	704
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	192	0	192	195	0	195
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	58	12	46	47	2	45
2.1.1.2 विदेश में	402	200	202	69	216	-147
2.1.1.2.1 इक्विटी	402	108	294	69	63	6
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	49	-49	0	50	-50
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	43	-43	0	103	-103
2.1.2 संविभाग निवेश	4,173	3,767	405	4,317	4,184	133
2.1.2.1 भारत में	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,305	3,002	303	3,375	3,595	-221
2.1.2.1.1.2 ऋण	856	710	146	934	556	377
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	11	55	-44	8	32	-24
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	1,935	2,048	-113	2,149	1,966	183
2.2.1 बाह्य सहायता	68	76	-8	81	78	3
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	4	-3	1	5	-4
2.2.1.2 भारत को	67	72	-5	80	74	6
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	412	505	-93	524	601	-77
2.2.2.1 भारत द्वारा	58	40	18	191	172	19
2.2.2.2 भारत को	355	465	-111	333	429	-96
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,455	1,467	-12	1,544	1,288	257
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,433	1,467	-34	1,518	1,288	231
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	22	0	22	26	0	26
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,063	1,506	-442	1,085	1,074	11
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,046	1,506	-460	1,079	1,074	6
2.3.1.1 आस्तियां	63	602	-539	165	317	-152
2.3.1.2 देयताएं	983	904	79	914	756	158
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	911	772	140	783	738	46
2.3.2 अन्य	17	0	17	6	0	6
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	1	-1	0	0	-
2.5 अन्य पूंजी	521	649	-127	582	654	-72
3 भूल-चूक	-	57	-57	23	-	23
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	570	-570	0	611	-611
4.1 आईएमएफ	0	0	0	-	-	-
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	570	-570	0	611	-611

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जुला.-सित्त. 2016 (अं.सं)			जुला.-सित्त. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	127,663	131,112	-3,449	145,558	152,770	-7,213
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	108,291	117,608	-9,318	123,490	137,867	-14,377
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	67,411	93,023	-25,612	76,082	108,880	-32,798
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	67,072	89,024	-21,951	75,534	103,167	-27,633
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	338	0	338	548	0	548
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	3,999	-3,999	-	5,713	-5,713
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	40,880	24,586	16,295	47,408	28,987	18,421
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	24	8	15	32	9	24
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	34	88	-53	52	109	-58
1.अ.ख.3 परिवहन	3,931	3,492	439	4,206	4,175	31
1.अ.ख.4 यात्रा	5,534	4,525	1,009	6,962	5,332	1,630
1.अ.ख.5 निर्माण	526	180	346	517	366	152
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	577	357	220	635	542	92
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,479	1,530	-51	1,321	1,574	-253
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए भौतिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	113	1,241	-1,128	142	1,290	-1,147
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	19,351	1,325	18,026	19,981	1,653	18,328
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	8,249	8,008	241	9,084	9,559	-475
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	356	633	-277	371	723	-353
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	146	156	-10	126	145	-19
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	561	3,043	-2,481	3,978	3,510	468
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,128	12,179	-8,051	4,554	13,044	-8,490
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	902	566	336	1,030	564	466
1.आ.2 निवेश आय	2,786	11,465	-8,679	2,795	12,358	-9,563
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,237	5,719	-4,483	1,486	5,899	-4,413
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	36	2,645	-2,608	70	3,442	-3,372
1.आ.2.3 अन्य निवेश	522	3,100	-2,578	153	3,009	-2,856
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	991	1	990	1,086	8	1,078
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	440	147	293	728	122	607
1.इ दिवतीय आय (1.इ.1+1.इ.2)	15,244	1,325	13,919	17,514	1,860	15,654
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	15,180	1,133	14,048	17,414	1,638	15,776
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	14,668	891	13,777	16,854	1,352	15,502
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	513	242	271	560	286	274
1.इ.2 सामान्य सरकार	64	192	-129	100	222	-122
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	58	72	-14	83	118	-35
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	14	-9	20	41	-22
2.2 पूँजी अंतरण	53	58	-5	64	76	-13
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	138,882	134,562	4,320	146,466	139,580	6,887
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	20,066	7,066	17,000	20,040	7,642	12,398
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	18,064	4,081	13,983	18,973	4,288	14,685
3.1अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17,201	3,904	13,297	18,241	4,253	13,987
3.1अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	14,328	3,904	10,424	15,203	4,253	10,950
3.1अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	2,874	-	2,874	3,037	-	3,037
3.1अ.2 ऋण लिखत	863	177	686	732	34	698
3.1अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	863	177	686	732	34	698
3.1आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	6,002	2,985	3,016	1,067	3,355	-2,288
3.1आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	6,002	2,343	3,659	1,067	1,760	-693
3.1आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	6,002	1,612	4,390	1,067	978	89
3.1आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	731	-731	-	781	-781
3.1आ.2 ऋण लिखत	0	643	-643	0	1,595	-1,595
3.1आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	643	-643	-	1,595	-1,595
3.2 संविभाग निवेश	62,312	56,262	6,050	67,145	65,079	2,066
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	49,356	44,833	4,523	52,492	55,924	-3,432
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12,790	10,604	2,186	14,524	8,655	5,869
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	167	825	-658	128	500	-372
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5,986	5,180	806	4,617	5,670	-1,053
3.4 अन्य निवेश	46,518	57,542	-11,024	54,665	51,690	2,975
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13,867	11,523	2,344	12,273	11,476	797
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	256	0	256	86	0	86
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13,611	11,523	2,088	12,187	11,476	711
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	9,181	19,638	-10,457	14,008	15,783	-1,775
3.4.3अ भारत को ऋण	8,308	18,984	-10,677	11,030	13,041	-2,011
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	873	654	219	2,979	2,742	236
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	40	63	-23	42	203	-161
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	21,726	21,908	-182	24,023	20,029	3,994
3.4.6 अन्य खाले प्राप्य / देय-अन्य	1,705	4,410	-2,705	4,317	4,199	118
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	8,512	-8,512	-	9,499	-9,499
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	8,512	-8,512	-	9,499	-9,499
4. कुल आस्तियां / देयताएं	138,882	134,562	4,320	146,466	139,580	6,887
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	78,751	57,148	21,603	76,588	68,310	8,277
4.2 ऋण लिखत	58,427	64,493	-6,066	65,561	57,572	7,989
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	1,705	12,921	-11,217	4,317	13,698	-9,380
5. निवल भूत-चूक	-	857	-857	360	-	360

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जुला.-सित. 2016 (अं.सं)			जुला.-सित. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	8,549	8,780	-231	9,358	9,821	-464
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	7,251	7,875	-624	7,939	8,863	-924
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	4,514	6,229	-1,715	4,891	7,000	-2,109
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,491	5,961	-1,470	4,856	6,632	-1,776
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	23	0	23	35	0	35
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	268	-268	-	367	-367
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	2,737	1,646	1,091	3,048	1,864	1,184
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	1	2	1	2
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	2	6	-4	3	7	-4
1.अ.ख.3 परिवहन	263	234	29	270	268	2
1.अ.ख.4 यात्रा	371	303	68	448	343	105
1.अ.ख.5 निर्माण	35	12	23	33	24	10
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	39	24	15	41	35	6
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	99	102	-3	85	101	-16
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	8	83	-76	9	83	-74
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,296	89	1,207	1,285	106	1,179
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	552	536	16	584	615	-31
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	24	42	-19	24	47	-23
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	10	10	-1	8	9	-1
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	38	204	-166	256	226	30
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	276	816	-539	293	839	-546
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	60	38	22	66	36	30
1.आ.2 निवेश आय	187	768	-581	180	794	-615
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	83	383	-300	96	379	-284
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	2	177	-175	5	221	-217
1.आ.2.3 अन्य निवेश	35	208	-173	10	193	-184
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	66	0	66	70	1	69
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	29	10	20	47	8	39
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,021	89	932	1,126	120	1,006
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,017	76	941	1,120	105	1,014
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	982	60	923	1,084	87	997
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	34	16	18	36	18	18
1.इ.2 सामान्य सरकार	4	13	-9	6	14	-8
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	4	5	-1	5	8	-2
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	0	1	-1	1	3	-1
2.2 पूँजी अंतरण	4	4	-0	4	5	-1
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	9,300	9,011	289	9,416	8,973	443
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	1,612	473	1,138	1,288	491	797
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	1,210	273	936	1,220	276	944
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1,152	261	890	1,173	273	899
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुननिवेश से इतर इक्विटी	959	261	698	977	273	704
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुननिवेश	192	0	192	195	0	195
3.1.अ.2 ऋण लिखत	58	12	46	47	2	45
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	58	12	46	47	2	45
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	402	200	202	69	216	-147
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	402	157	245	69	113	-45
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुननिवेश को छोड़कर इक्विटी	402	108	294	69	63	6
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुननिवेश	0	49	-49	0	50	-50
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	43	-43	0	103	-103
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	43	-43	0	103	-103
3.2 संविभाग निवेश	4,173	3,767	405	4,317	4,184	133
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,305	3,002	303	3,375	3,595	-221
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	856	710	146	934	556	377
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	11	55	-44	8	32	-24
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	401	347	54	297	365	-68
3.4 अन्य निवेश	3,115	3,853	-738	3,514	3,323	191
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	929	772	157	789	738	51
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	17	0	17	6	0	6
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	911	772	140	783	738	46
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	615	1,315	-700	901	1,015	-114
3.4.3.अ भारत को ऋण	556	1,271	-715	709	838	-129
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	58	44	15	191	176	15
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	3	4	-2	3	13	-10
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,455	1,467	-12	1,544	1,288	257
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	114	295	-181	278	270	8
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	570	-570	0	611	-611
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	570	-570	0	611	-611
4. कल आस्तियां / देयताएं	9,300	9,011	289	9,416	8,973	443
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	5,273	3,827	1,447	4,924	4,392	532
4.2 ऋण लिखत	3,912	4,319	-406	4,215	3,701	514
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	114	865	-751	278	881	-603
5. निवल भूत-चूक	-	57	-57	23	-	23

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2016-17		2016		2017			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	148,229	342,642	140,624	311,682	151,291	353,354	153,578	364,246
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	99,114	327,845	94,035	297,528	100,968	337,563	101,661	348,134
1.2 अन्य पूंजी	49,115	14,796	46,588	14,153	50,323	15,791	51,918	16,112
2 संविभाग निवेश	2,615	238,604	2,256	232,069	2,084	251,152	2,456	253,991
2.1 इक्विटी	1,593	153,978	1,943	148,085	2,021	154,901	2,408	150,062
2.2 ऋण	1,022	84,627	313	83,984	63	96,251	48	103,928
3 अन्य निवेश	43,433	377,436	52,402	390,273	36,605	378,671	38,859	381,642
3.1 व्यापार ऋण	1,793	88,896	2,236	81,966	1,154	89,580	1,263	93,589
3.2 ऋण	7,305	159,873	6,248	166,982	5,146	158,633	5,882	156,925
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,073	117,110	26,813	130,220	16,083	118,475	17,208	118,266
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	14,261	11,557	17,104	11,105	14,222	11,983	14,506	12,862
4 रिज़र्व्स	369,955	–	371,990	–	386,539	–	400,205	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	564,231	958,682	567,272	934,024	576,520	983,178	595,099	999,878
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-394,451		-366,751		-406,658		-404,779

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2016-17	2017			2016-17	2017		
		अक्तू.	नव.	दिसं.		अक्तू.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	107.86	10.00	10.83	10.90	1,253,652.08	115,808.00	123,579.36	128,098.85
1.1 ग्राहक लेनदेन	103.66	9.71	10.51	10.58	849,950.51	82,084.42	87,550.13	90,557.83
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	4.17	0.29	0.32	0.31	131,953.25	9,971.68	10,860.36	10,349.96
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.018	0.002	0.002	0.002	271,748.31	23,751.90	25,168.88	27,191.06
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.65	0.27	0.33	0.28	1,056,173.36	86,873.56	101,377.16	88,062.67
2.1 सीबीएलओ	0.22	0.02	0.02	0.02	229,528.33	22,981.83	27,794.59	23,657.46
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.51	0.08	0.11	0.09	404,389.08	27,863.13	35,379.85	30,067.97
2.2.1 एकमुश्त	1.34	0.06	0.09	0.07	168,741.46	7,604.53	10,840.19	8,453.70
2.2.2 रिपो	0.168	0.016	0.020	0.016	235,647.62	20,258.60	24,539.65	21,614.27
2.3 विदेशी समाशोधन	1.93	0.18	0.20	0.18	422,255.95	36,028.59	38,202.72	34,337.24
3 पेपर समाशोधन	1,206.69	96.41	98.60	96.44	80,958.15	6,478.86	6,774.71	6,752.50
3.1 चेक ट्रंक्शन प्रणाली	1,111.86	94.44	96.30	94.57	74,035.22	6,340.16	6,633.94	6,563.97
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 अन्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	94.83	1.97	2.30	1.86	6,922.93	138.70	140.77	188.53
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	4,204.96	444.62	460.10	469.96	132,250.12	15,598.70	15,620.80	17,464.68
4.1 ईसीएस नामे	8.76	0.12	0.13	0.13	39.14	0.83	0.83	0.84
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	10.10	0.50	0.54	0.51	144.08	10.72	10.38	7.24
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,622.10	158.78	161.97	169.05	120,039.68	13,851.28	13,884.00	15,779.20
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	506.73	88.12	89.49	98.01	4,111.06	750.42	782.58	871.06
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,057.27	197.09	207.97	202.26	7,916.17	985.45	943.02	806.34
5 कार्ड	12,055.87	1,144.31	1,118.88	1,175.09	30,214.00	3,364.50	3,254.08	3,459.55
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,093.51	124.04	116.59	124.42	3,312.21	422.60	396.17	421.84
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	6.37	0.68	0.69	0.71	28.39	3.21	3.20	3.34
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,087.13	123.36	115.90	123.71	3,283.82	419.39	392.96	418.50
5.2 डेबिट कार्ड	10,962.36	1,020.27	1,002.30	1,050.67	26,901.79	2,941.90	2,857.91	3,037.71
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,563.06	741.87	731.33	760.32	23,602.73	2,533.21	2,492.72	2,633.10
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	2,399.30	278.40	270.96	290.35	3,299.07	408.69	365.19	404.61
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	1,963.66	245.18	236.16	319.85	838.01	116.98	133.21	143.34
6.1 एम-वॉलेट	1,629.98	201.23	186.67	288.37	532.42	86.60	93.88	125.68
6.2 पीपीआई कार्ड	333.11	43.91	49.45	31.44	277.52	28.80	37.71	16.34
6.3 पेपर वाउचर	0.51	0.04	0.04	0.03	25.36	1.58	1.63	1.33
7 मोबाइल बैंकिंग	976.85	150.68	184.98	250.61	13,104.76	917.02	1,054.24	1,108.40
8 कार्ड बकाया	801.49	860.13	867.66	877.97	-	-	-	-
8.1 क्रेडिट कार्ड	29.84	33.87	34.78	35.50	-	-	-	-
8.2 डेबिट कार्ड	771.65	826.25	832.89	842.47	-	-	-	-
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222475	221314	221350	221832	-	-	-	-
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	2529141	2958301	2998733	3027382	-	-	-	-
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	19,542.66	1,940.78	1,924.90	2,072.51	2,282,337.40	204,488.69	225,570.44	216,790.53

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2016-17	2016	2017		
		1	मई	मई	अप्रै.	मई
			2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	4,341.75	308.59	480.30	27.29	48.03
	बकाया	7,312.73	6,817.61	7,312.73	7,339.92	7,387.84
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	3,879.55	282.04	397.56	27.92	37.33
	बकाया	4,689.77	4,319.89	4,689.77	4,717.69	4,755.02
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	2,474.46	180.68	239.64	10.63	4.43
	बकाया	920.64	667.94	920.64	931.27	935.69
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0.56	0.01	0.49	-0.36	-0.32
	बकाया	33.01	34.27	33.01	32.65	32.33
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.01	0.00	0.02	-0.06	-0.04
	बकाया	-0.48	1.09	-0.48	-0.54	-0.58
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	353.34	26.48	41.41	-4.23	-1.19
	बकाया	1,800.66	1,897.58	1,800.66	1,796.43	1,795.24
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना	प्राप्तियां	100.02	6.90	13.93	8.40	12.01
	बकाया	294.53	234.79	294.53	302.93	314.94
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	476.65	34.94	56.00	9.74	15.26
	बकाया	796.58	717.78	796.58	806.32	821.58
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	518.38	501.48	518.38	521.44	527.91
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	36.58	30.66	36.58	37.33	38.38
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	51.77	48.33	51.77	52.12	52.64
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	189.85	137.31	189.85	195.43	202.65
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	474.51	33.03	46.07	3.80	7.18
	बकाया	844.53	766.14	844.53	848.33	855.52
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	बकाया	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
1.1.10 अन्य जमाराशियां	बकाया	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	289.85	18.35	53.84	0.03	7.32
	बकाया	1,989.35	1,925.33	1,989.35	1,989.28	1,996.49
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	120.63	4.97	29.88	-7.13	-5.04
	बकाया	872.39	869.15	872.39	865.26	860.23
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	बकाया	8.86	8.87	8.86	8.86	8.87
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-0.01	0.01	-0.49	-10.55	-11.88
	बकाया	535.72	625.01	535.72	525.17	513.30
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	169.23	13.37	24.45	17.73	24.27
	बकाया	460.23	309.96	460.23	477.96	502.21
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	बकाया	0	0.00	-	-0.02	-0.05
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	बकाया	-1.12	-0.95	-1.12	-1.14	-1.18
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-0.62	-0.60	-0.62	-0.62	-0.62
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	113.89	113.89	113.89	113.79	113.68
	बकाया	172.35	8.20	28.90	-0.66	3.38
		633.61	572.39	633.61	632.95	636.33

स्रोत: महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	47967.49	49246.98	49109.75	50430.94	51451.83
1. वाणिज्यिक बैंक	40.00	40.92	40.46	39.68	40.37
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.14	0.28	0.16	0.31	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	22.68	22.55	22.90	23.13	23.49
4. म्यूच्युअल फंड	2.13	1.96	1.49	1.44	1.86
5. सहकारी बैंक	2.47	2.63	2.70	2.65	2.62
6. वित्तीय संस्थाएं	0.84	0.86	0.81	0.73	0.78
7. कॉरपोरेट	1.09	1.05	1.05	1.29	1.04
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.82	3.13	3.53	4.29	4.58
9. भविष्य निधियां	6.25	6.24	6.27	6.13	5.99
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.80	14.61	14.65	14.29	12.84
11. अन्य	5.79	5.77	5.98	6.07	6.11
11.1 राज्य सरकार	1.84	1.83	1.92	1.91	1.92

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	18114.95	19343.91	20893.41	21467.07	22488.35
1. वाणिज्यिक बैंक	40.22	41.25	39.01	37.94	37.64
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.35	0.30	0.39	0.38	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	32.67	31.87	32.50	33.53	34.00
4. म्यूच्युअल फंड	1.62	1.36	2.42	1.89	1.92
5. सहकारी बैंक	4.21	4.47	4.75	4.82	4.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.27	0.29	0.30	0.27	0.22
7. कॉरपोरेट	0.14	0.13	0.17	0.11	0.11
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.06	0.07	0.08	0.16
9. भविष्य निधियां	16.84	16.81	17.27	18.10	18.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.01	0.03	0.06	0.06	0.06
11. अन्य	3.59	3.43	3.05	2.81	2.37
11.1 राज्य सरकार	-	-	-	-	-

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	4202.40	4366.47	3320.80	6135.01	5704.50
1. वाणिज्यिक बैंक	52.58	50.47	57.85	53.96	52.15
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.38	1.80	1.25	1.09	1.32
3. बीमाकृत कंपनियां	1.91	2.02	4.58	3.20	4.32
4. म्यूच्युअल फंड	16.06	12.91	7.85	15.31	12.44
5. सहकारी बैंक	3.52	3.28	5.62	2.48	2.33
6. वित्तीय संस्थाएं	2.75	2.76	4.57	2.60	3.54
7. कॉरपोरेट	1.21	1.81	1.83	1.54	1.64
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-	-	-
9. भविष्य निधियां	0.45	0.43	0.35	0.06	0.20
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.16	0.09	0.02	0.05	0.06
11. अन्य	19.96	24.44	16.09	19.72	22.01
11.1 राज्य सरकार	15.98	20.51	11.02	16.71	18.73

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 स.अ.	2017-18 ब.अ.
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	26,949.34	30,002.99	32,852.10	33,782.60	40,599.68	43,957.96
1.1 गतिविधियां	15,741.62	17,142.21	18,720.62	19,429.44	24,271.15	26,194.51
1.1.1 राजस्व	12,807.14	13,944.26	14,830.18	14,971.45	18,457.92	19,701.57
1.1.2 पूंजी	2,446.11	2,785.08	3,322.62	3,400.51	4,471.03	5,515.05
1.1.3 ऋण	488.38	412.88	567.82	1,057.49	1,342.20	977.89
1.2 गैर गतिविधियां	10,850.47	12,427.83	13,667.69	13,984.15	15,870.24	17,261.83
1.2.1 राजस्व	9,991.40	11,413.65	12,695.20	12,739.11	15,031.91	16,430.73
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	4,543.06	5,342.30	5,845.42	6,134.74	6,881.68	7,536.87
1.2.2 पूंजी	837.14	990.37	946.87	1,207.71	816.42	807.16
1.2.3 ऋण	21.93	23.81	25.63	37.33	21.92	23.94
1.3 अन्य	357.24	432.95	463.79	369.01	458.29	501.62
2. कुल प्राप्तियां	27,690.29	30,013.72	31,897.37	34,487.63	39,810.09	42,551.06
2.1 राजस्व प्राप्तियां	19,716.19	22,114.75	23,876.93	24,504.58	30,356.58	33,511.38
2.1.1 कर प्राप्तियां	16,879.59	18,465.45	20,207.28	20,754.42	23,917.47	27,066.67
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	10,385.91	11,257.81	12,123.48	12,912.47	15,168.50	16,914.54
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	6,462.73	7,176.34	8,051.76	7,803.16	8,706.20	10,105.34
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	30.94	31.30	32.04	38.78	42.77	46.79
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	2,836.60	3,649.30	3,669.65	3,750.16	6,439.11	6,444.71
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	355.43	401.62	396.22	347.38	322.08	275.25
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	389.20	391.13	609.55	588.52	595.33	1,245.96
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	129.29	93.85	220.72	155.86	136.03	519.12
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	259.91	297.28	388.83	432.66	459.30	726.84
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	6,843.95	7,497.11	8,365.63	8,689.51	9,647.78	9,200.62
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,352.80	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,306.09	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	548.40	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	3,419.14	4,065.61	8,611.06	6,251.12	3,192.96	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,536.94	6,391.99	6,640.58	6,354.19	6,472.74	6,970.13
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-85.70	-142.81	-565.80	-785.15	-1,091.76	-941.16
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	329.94	312.90	343.39	298.82	326.18	332.03
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-4.12	34.63	51.09	-33.22	-82.42	-10.45
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27.22	255.45	275.45	134.70	386.99	502.14
3ख.1.6 नकद शेष	-740.96	-10.72	954.74	-705.03	789.59	1,406.90
3ख.1.7 अन्य	708.62	582.75	536.84	3,297.71	2,697.73	783.13
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.1	26.7	26.4	24.7	26.7	26.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.8	26.7	25.6	25.2	26.2	25.3
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.8	19.7	19.2	17.9	20.0	19.9
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	17.0	16.4	16.2	15.2	15.8	16.1
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.5

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2017 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	6.58	18	12.16	16	8.44	11
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	0.88	17	0.48	7	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	2.90	14	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	1.70	23	1.49	12	0.16	6
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.07	23	4.79	23	1.15	3
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	3.05	14	2.45	6	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2017 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	63.89	6.64	0.10	0
2	अरुणाचल प्रदेश	7.60	--	--	0
3	असम	40.19	0.34	0	14.00
4	बिहार	43.90	--	0	0
5	छत्तीसगढ़	31.05	--	0.01	0
6	गोवा	4.41	2.20	--	0
7	गुजरात	111.36	3.92	0	20.00
8	हरियाणा	17.04	9.55	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	0	--	0	0
12	कर्नाटक	25.21	--	0	228.00
13	केरल	17.52	--	0.03	0
14	मध्य प्रदेश	--	7.49	0.00	0
15	महाराष्ट्र	251.49	--	--	400.00
16	मणिपुर	2.77	0.65	0	0
17	मेघालय	4.55	0.17	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.06	0.20	--	0
19	नगालैंड	9.95	0.25	--	0
20	उड़ीसा	109.11	11.80	0.69	70.00
21	पुदुचेरी	2.72	--	--	7.67
22	पंजाब	0	0	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	59.74
24	तमिलनाडु	50.99	--	0.48	263.50
25	तेलंगाना	39.16	5.70	0.07	0
26	त्रिपुरा	3.65	0.03	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.82	0
28	उत्तराखंड	24.39	0.65	0.01	0
29	पश्चिम बंगाल	86.30	2.95	4.30	50.00
	कुल	951.31	52.54	8.97	1112.91

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं (1),(2) और (3) के सामने दर्शाए गए आंकड़े अंतिम (आरआरबी सहित) हैं और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़ कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दिनांक 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी. केका. प्लान.बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपये-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक । 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। आरईईआर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध ।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

टेबल फार्मेट केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राज्य सरकारों की धारित प्रतिभूतियों को अलग श्रेणी में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉन्ड शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 26 राज्यों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजा और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाशिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थ व्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2018	₹ 300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का अभिदान) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का अंशदान - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का अभिदान) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय स्टेट 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय इकोनॉमी 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹400 एक प्रति (रियायती) ₹450 एक प्रति (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2016-17 के बजटों का अध्ययन	₹500 एक प्रति (काउंटर पर) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 23 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मिंट रोड माइलस्टोन्स: आरबीआई ऐट 75	₹1,650 एक प्रति (काउंटर पर)	अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी - हिंदी)	₹110 एक प्रति (काउंटर पर)	

टिप्पणिया:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. अभिदान मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंज़िल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रता शीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपना अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई मेल आईडी to spsdcs@rbi.org.in को प्रेषित करें ताकि हम सुचारु रूप से आपके साथ संपर्क कर सकें।

